राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 51

मूल्य ₹8 .00, नई दिल्ली, शनिवार, 31 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14



आज खेलेंगी सेमीफाइल मुकाबला >> 12

सिंधू से सोने की आस, लवलीना ने रचा इतिहास

भारत के अन्य परिणाम

विश्व नंबर एक तीरंदाज दीपिका कुमारी को क्वार्टर फाइनल में कोरिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त अन सान ने 6-0 से हराया।

निशानेबाजी में मनु भाकर और राही सरनोबत महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल्स में प्रवेश करने से चूक गईं।

अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपलचेस स्पर्धा में अपना ही राष्ट्रीय रिकार्ड बेहतर किया, लेकिन फाइनल में जगह नहीं बना सके। दुती चंद भी 100 मीटर की स्पर्धा में शुरुआती दौर से ही बाहर हो गईं। एमपी जाबीर पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ से बाहर हो गए।

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई (69 किग्रा) ने शुक्रवार को इतिहास रचते हुए टोक्यो ओलिंपिक में एक और पदक पक्का किया तो बैडमिंटन में पीवी सिंधू ने सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए स्वर्ण की आस को जीवंत बनाए रखा।

मुक्केबाजी में भारत का तीसरा पदक : पहली बार ओलिंपिक में खेल रहीं लवलीना ने पूर्व चीनी ताइपे की विश्व चैंपियन नियेन चिन चेन को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब यह तय हो गया कि वह पदक लेकर लौटेंगी। वह ओलिंपिक में पदक जीतने वाली कुल तीसरी भारतीय और दूसरी महिला मुक्केबाज होंगी। इससे पहले विजेंद्र सिंह (2008 बीजिंग) और एमसी मेरी कोम (2012 लंदन) कांस्य पदक जीत चुके हैं। हालांकि, एक अन्य भारतीय मुक्केबाज सिमरनजीत कौर (60 किग्रा) का सफर प्री-क्वार्टर फाइनल में थम गया। उन्हें थाइलैंड की सुदापोर्न सीसोंदी ने 5-0 से हराया।

सिंधू स्वर्ण से दो जीत दूर : मौजूदा विश्व चैंपियन और रियो ओलिंपिक की रजत विजेता सिंधू ने विश्व नंबर पांच जापान की अकाने यामागुची को हराकर स्वर्ण पदक की उम्मीदों को बल दिया। सिंधू ने यामागुची को सीधे गेम में 21-13, 22-20 से हराया। सिंधू अब स्वर्ण से दो जीत और अपने दूसरे ओलिंपिक पदक से एक जीत दूर हैं। सेमीफाइनल में सिंधू का सामना चीनी ताइपे की ताई जु यिंग से होगा।

हाकी में दोहरी जीत : पहले ही क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर चुकी पुरुष हाकी टीम ने पूल-ए के आखिरी मैच में मेजबान जापान को 5-3 से हराया। गुरजंत सिंह (17 व 56वें मिनट) ने दो गोल दागे, जबकि हरमनप्रीत सिंह (13वें मिनट), शमशेर सिंह (34वें मिनट) और नीलाकांत शर्मा (51वें मिनट) ने एक-एक गोल किया। वहीं नवनीत कौर के 57वें मिनट में किए गए गोल से महिला हाकी टीम ने आयरलैंड को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को कायम रखा।

संबंधित खबरें >> पेज 12



>> मुक्केबाज बोरगोहाई ने पक्का किया भारत का दूसरा पदक

जागरण विशेष

प्रशिक्षु सेनाधिकारी सीखेंगे ड्रोन बनाना और चलाना



कानपुर: देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बनकर उभरे ड्रोन की तकनीक से सेना के प्रशिक्षु अधिकारी रूबरू होंगे। उन्हें दक्ष करने का जिम्मा आइआइटियंस संभालेंगे। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति पृष्ठ 3

मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह भी हंगामे की भेंट चढ़ा

नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह भी विपक्ष के शोर-शराबे की भेंट चढ़ गया। पेगासस जासूसी कांड और किसानों के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा सप्ताह के आखिरी दिन भी नहीं थमा। विपक्ष जहां पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं सरकार ने हंगामे के बीच कई विधायी कार्य कराए और बिना चर्चा कई विधेयक पारित करा लिए। संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की ओर से विपक्षी नेताओं को साधने की लगातार कोशिश की जा रही है।

लाल किला हिंसा के आरोपित किसानों को कानूनी सहायता देगी पंजाब सरकार

मदद ▸ आंदोलन में मौत होने पर पहले ही कर रखा है स्वजन को नौकरी व पांच लाख रुपये मुआवजे का एलान

इंद्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

तीन कृषि सुधार कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपित किसानों पर केस दर्ज किया था, पंजाब सरकार उन्हें कानूनी मदद के साथ-साथ मुआवजा देने पर भी विचार कर रही है।

पंजाब विधानसभा की ओर से कांग्रेस विधायक कुलदीप वैद की अगुआई में बनाई गई कमेटी ऐसे करीब 100 आरोपित किसानों के बयान दर्ज कर रही है। 60 किसानों के बयान दर्ज भी किए जा चुके हैं। शुक्रवार को भी 10 किसानों के बयान लिए गए।

गौरतलब है कि 26 जनवरी को तीन कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने ट्रैक्टर परेड निकालने का एलान किया था, लेकिन इसी बीच फिल्म कलाकार दीप सिद्धू की अगुआई में बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पुलिस के तय रूट को छोड़कर लाल किले की ओर बढ़ गए थे। यहां पर उन्होंने निशान साहिब फहरा दिया और काफी देर तक हुड़दंग मचाते रहे। पुलिस के साथ मारपीट भी की। दिल्ली पुलिस ने कई किसानों व युवा प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज किया था। दीप सिद्धू वहां से भाग गया था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था।



कांग्रेस विधायक कुलदीप वैद। जागरण

कमेटी में भाजपा को छोड़ सभी पार्टियों के विधायक

कमेटी में शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायक शामिल हैं। इससे पहले राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि तीन कृषि सुधार कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे जिन किसानों की जान गई है, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी और पांच लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे 220 किसानों के केस तैयार कर लिए गए हैं और उन्हें जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।

हिंसा करने वाले किसान नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता : भाजपा

भारतीय जनता पार्टी के महासचिव डा. सुभाष शर्मा ने कहा है कि 26 जनवरी को लाल किले पर जाने वाले लोगों की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी निंदा की थी, लेकिन आज उन्हें कानूनी सहायता और मुआवजा देने की बात से साफ हो गया है कि वे किसान नहीं बल्कि कांग्रेसी थे। भाजपा नेता ने कहा कि हम पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है और जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, वे किसान नहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं।

विधानसभा कमेटी के चेयरमैन कुलदीप वैद ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने किसानों के साथ बहुत ज्यादती की है। उन्हें बुरी तरह से पीटा गया है। कई तो लाल किले की ओर गए भी नहीं थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लेकर यातनाएं दीं। अभी तक हम 60 आरोपित किसानों के बयान रिकार्ड कर चुके हैं और लगभग 40 के बयान और लिए जाने हैं। इनमें से कई किसान गरीब परिवारों से है। उन्हें कानूनी सहायता की जरूरत है। इसके अलावा कमेटी इन्हें मुआवजा देने की भी सिफारिश करेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री से भी चर्चा की जाएगी। अभी रिपोर्ट तैयार करने में समय लग सकता है।

प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज राजद्रोह के केस नहीं होंगे रद

चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा की गाड़ी पर पथराव करने के आरोपितों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने को चुनौती देने वाली याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सरकार के इस कदम को किसानों को डराने का प्रयास बताते हुए हरियाणा प्रोग्रेसिव किसान यूनियन ने अर्जी याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि यह कानून असंवैधानिक है, यह अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का हनन करता है। (पेज-6)

राजस्थान में प्रदर्शनकारियों ने फिर की भाजपा नेता से मारपीट

जयपुर : राजस्थान के श्रीगंगानगर में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल के साथ मारपीट की। महाराजा गंगसिंह चौक पर एकत्रित प्रदर्शनकारी किसानों ने मेघवाल को घेर लिया और मारपीट करने लगे। उनके कपड़े फाड़ दिए। किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। ज्ञात हो कुछ दिन पहले भी एक भाजपा नेता के साथ प्रदर्शनकारी किसानों ने ऐसा ही बर्ताव किया था। (पेज-6)

जज हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से मांगी रिपोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- शीर्ष अदालत ने मामले पर लिया स्वतः संज्ञान
- देश में अदालतों व जजों की सुरक्षा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के धनबाद में जज की हत्या के मामले में शुक्रवार को स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने जज की हत्या को गंभीरता से लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव व डीजीपी से एक हफ्ते में जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट द्वारा की जा रही निगरानी और सुनवाई जारी रहेगी।

शुक्रवार की सुबह सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को आदेश दिया कि वे अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में जांच की स्थिति रिपोर्ट एक हफ्ते में कोर्ट में पेश करें। जस्टिस रमना ने कहा, न्यायिक अधिकारियों और वकीलों पर हमले की ऐसी घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। उनकी चिंता अदालतों में और उसके बाहर जजों की सुरक्षा को लेकर है। वे विचार करेंगे कि इसके लिए राज्य सरकारों ने क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने अगली तारीख पर झारखंड के एडवोकेट जनरल को भी मौजूद रहने को कहा है। पीठ ने कहा, अन्य राज्यों को नोटिस जारी करने के मुद्दे पर अगले हफ्ते विचार होगा।

झारखंड के धनबाद में एक आटो रिक्शा से टक्कर मार कर जज उत्तम आनंद की हत्या कर दी गई थी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए संज्ञान लेने का आग्रह किया था। रमना ने उनसे कहा था कि उन्हें घटना की जानकारी है और उनकी झारखंड के मुख्य न्यायाधीश से बात हो गई है। हाई कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। इसके बाद गुरुवार को ही हाई कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए घटना की जांच के लिए एसआइटी गठित कर दी थी। हाई कोर्ट ने घटना पर नाराजगी जताते हुए तीखी टिप्पणियां भी की थीं।



50 टीमें छान रहीं खाक, जज के हत्यारों का अब तक सुराग नहीं

धनबाद : जज की हत्या के दो दिनों बाद भी पुलिस हत्यारों का सुराग नहीं पा सकी है। हत्या क्यों हुई, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हत्या की गुत्थी सुलझाने को पुलिस की 50 टीमें लगी हैं, पर सफलता के नाम पर आटो की बरामदगी और दो आरोपितों राहुल व लखन को ही पकड़ा जा सका है। (पेज-5)

बिना परीक्षा 99 .37 % छात्र 12वीं में पास

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- मेरिट सूची नहीं हुई जारी, एक साथ मिलेगा मार्कशीट और सर्टिफिकेट
- परिणाम से संतुष्ट नहीं होने पर दोबारा दे सकेंगे परीक्षा

बच्चों के भविष्य से जुड़े अभिभावकों का संशय दूर करने से लेकर अदालत को संतुष्ट करने के बाद आखिरकार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शुक्रवार को 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। इस साल भी मेरिट सूची जारी नहीं की गई है। न तो विषयवार मेरिट सूची आएगी, न ही किसी छात्र का मेरिट सर्टिफिकेट जारी होगा। बोर्ड मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ जारी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर विद्यार्थियों को बधाई दी। पीएम ने कहा, शिक्षा जगत ने कोरोना के कारण कई बदलाव देखे। जिन लोगों को लगता है कि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, उनसे कहना चाहता हूं कि अपने अनुभव से सीखें और सिर ऊंचा रखें। एक उज्ज्वल और अवसर से भरा भविष्य उनका इंतजार कर रहा है।

सीबीएसई के मुताबिक, इस वर्ष 14.30 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें 12 लाख से अधिक उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत 99.37 रहा है। लड़कियों का पास फीसद लड़कों के मुकाबले 0.54 फीसद ज्यादा है। 99.67 फीसद लड़कियां, 99.13 फीसद लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों का नतीजा शत-प्रतिशत रहा है।



विक्ट्री चिन्ह बनाकर यादगार पलों को मोबाइल में कैद करती छात्राएं। ध्रुव कुमार

उन युवा दोस्तों को बधाई, जिन्होंने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। उज्ज्वल, सुखी और स्वस्थ भविष्य के लिए शुभकामनाएं।
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

पांच फीसद से अधिक छात्रों के 95 फीसद से अधिक अंक

70,004 यानी 5.37 फीसद छात्रों के 95 फीसद या उससे अधिक अंक आए हैं। वहीं 1,50,152 छात्रों ने 90 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यानी 11.51 फीसद छात्र ऐसे हैं जिनके 90-95 फीसद के बीच अंक आए हैं।

99 फीसद से अधिक दिव्यांग छात्र हुए उत्तीर्ण : दिव्यांग विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा। इस साल 99.59 फीसद दिव्यांग छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। कुल 3,925 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें 3,909 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें 129 छात्रों के 95 फीसद या उससे अधिक अंक आए हैं। वहीं, 400 ऐसे छात्र हैं जिनके 90-95 फीसद के बीच अंक आए हैं।

इस फार्मूले से जारी हुआ नतीजा : कोरोना के कारण इस बार भी परीक्षाएं आयोजित नही हुई और बोर्ड ने 30-30-40 फार्मूले पर परीक्षा परिणाम जारी किया है। इसमें 12वीं के 40 फीसद अंक, 11वीं व 10वीं के 30-30 फीसद अंक जोड़े गए हैं।

65,184 छात्रों का रिजल्ट नहीं हुआ जारी : 65,184 छात्रों का परिणाम पांच अगस्त कर घोषित होगा। बोर्ड के मुताबिक 1060 स्कूलों के पास रेफरेंस ईयर का डाटा नहीं था। ऐसे में इन स्कूलों के छात्रों के परिणाम में फिलहाल 'रिजल्ट लेटर' लिख कर आएगा।

असंतुष्ट छात्र फिर दे सकेंगे परीक्षा : 6,149 छात्रों की कंपार्टमेंट आई है। इन्हें 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के लिए परीक्षा देनी होगी, जो 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। इस दौरान वे छात्र भी परीक्षा दे सकते हैं जो परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं।

प्राइवेट व पत्राचार के छात्रों की होगी परीक्षा पेज>>5

गहलोत के मंत्रियों पर पार्टी के विधायकों ने ही लगाए दलाल रखने के आरोप

नरेन्द्र शर्मा, जयपुर

- रायशुमारी के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के समक्ष की शिकायत
- कहा-पार्टी पदाधिकारियों व विधायकों के बजाय दलालों की मर्जी से होते हैं काम
- माकन बोले-सरकार से संगठन में जाएंगे कुछ मंत्री, पीसीसी में चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के आसार



जयपुर में शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन (मध्य में)। एएनआइ

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट में जारी तनातनी के बीच कई विधायकों ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन से विधायकों ने कहा है कि मंत्रियों के यहां दलाल लगे हुए हैं। विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों की सुनवाई नहीं होती है, लेकिन दलालों की मर्जी से काम हो जाते हैं। विधायकों की इच्छा को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है और दलाल तबादला सूची बनाते हैं । विधायकों ने ऐसे पांच मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोला है, जिनकी छुट्टी होना तय माना जा रहा है।

दरअसल, पार्टी की खेमेबाजी को दूर करने के साथ ही सत्ता-संगठन में बदलाव को लेकर माकन विधायकों व पार्टी के पदाधिकारियों से रायशुमारी कर रहे थे। इसी कड़ी में विधायकों ने माकन के समक्ष मंत्रियों की शिकायत की।

सूत्रों के अनुसार माकन ने चिकित्सा मंत्री डा. रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना को मंत्री पद से हटाने के संकेत दिए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का भी मंत्री पद जा सकता है। वह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। उनको एक ही जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगस्त के दूसरे सप्ताह में होने वाले फेरबदल से पहले इन मंत्रियों से इस्तीफे मांगे जा सकते हैं।

कांग्रेस के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी ने बताया कि पंजाब की तर्ज पर यहां भी चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। हालांकि, माकन दिल्ली लौट गए हैं। अब वह कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।

राजस्थान में मंत्रियों पर भड़के कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी पेज>>4

खरी बात

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया वेदों और पुराणों का हवाला, कहा, महान दूरदृष्टा थे भारतीय उपमहाद्वीप के संत और ऋषि-मुनि, पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए ही पद्म पुराण में दी गई यह चेतावनी

'तालाबों, कुओं या झीलों को प्रदूषित करने वाले जाते हैं नरक'

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने शुक्रवार को वेदों और पुराणों का हवाला देते हुए कहा कि जो व्यक्ति तालाबों, कुओं या झीलों के पानी को प्रदूषित करता है, वह नरक में जाता है।

एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण पश्चिम की सोच या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी उत्पत्ति कुछ दशक या कुछ शताब्दी पहले हुई है। ट्रिब्यूनल ने कहा, 'भारत में कम से कम इस बात के पर्याप्त दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि इस देश के लोगों ने प्रकृति और पर्यावरण को उचित सम्मान दिया है और समग्रता व श्रद्धा का व्यवहार किया है। इसमें सभी समुदाय और संगठन शामिल हैं।'

एनजीटी ने आगे कहा, 'असल में हमारे वैदिक साहित्य में मानव शरीर को पंचभूतों से निर्मित माना गया है जिनमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी शामिल हैं। प्रकृति ने इन तत्वों और प्राणियों में संतुलन बनाए रखा है। हम पाते हैं कि अनादि काल या वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल से भारतीय उपमहाद्वीप के संत और ऋषि-मुनि महान दूरदृष्टा थे। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से ब्रह्मांड के सृजन को समझा। उन्होंने ब्रह्मांड के विकास के रहस्यों को बेहद बुद्धिमानी से उजागर किया।'

ट्रिब्यूनल ने कहा कि प्राचीन भारत में लोगों को प्रकृति के नजदीक लाने के लिए ऋषियों ने इसे धार्मिक रूप दे दिया ताकि प्रकृति के प्रति निर्देशों को लोग अनिवार्य मानें और उसके संरक्षण के सभी उपायों का पालन करें। वैदिक साहित्य में पानी को सबसे अधिक सम्मान दिया गया है और उसे बेहद श्रद्धेय माना गया है। पानी को मानव पर्यावरण का हिस्सा बताते हुए एजीटी ने कहा कि इसे पांच रूपों में मिलना बताया गया है- बारिश का पानी (दिव्य), प्राकृतिक झरने (श्रेवंती), कुएं और नहरें (खनित्रिमह), झीलें (स्वयंजह) और नदियां (समुद्रस्थ)। कहा गया है कि सभी जीवों का जन्म जल से हुआ है और जल ही सभी चल-अचल का निर्माता है। संत और ऋषि-मुनि जानते थे कि मानव बस्तियां ज्यादातर नदियों और जल स्रोतों के तटों पर हैं और उनकी दैनिक गतिविधियों से पानी प्रदूषित हो सकता है व प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। इसे हतोत्साहित करने के लिए ही पद्म पुराण में चेतावनी दी गई है कि जो व्यक्ति तालाबों, कुओं या झीलों के पानी को प्रदूषित करता है वह नरक में जाता है। चंडोग्य उपनिषद में कहा गया है कि पानी ने पौधों को उत्पन्न किया है जो भोजन पैदा करते हैं। ऋग्वेद कहता है कि वनों को नष्ट नहीं करना चाहिए, पृथ्वी सृजन की बेल और वनों की पिटारी है और पेड़ या औषधि और पौधे जीवित हैं।

बेंगलुरु में गोदरेज के हाईराइज प्रोजेक्ट को तत्काल ढहाने का आदेश

एनजीटी ने जल और पर्यावरण की महत्ता पर उक्त टिप्पणियां बेंगलुरु में गोदरेज प्रापर्टीज लिमिटेड और वंडर प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के हाईराइज लक्जरी प्रोजेक्ट को प्रदान की गई पर्यावरण मंजूरी को खारिज करते हुए की। ट्रिब्यूनल ने इन्हें तत्काल ढहाने का आदेश दिया है।



अहम टिप्पणी : एनजीटी। फाइल फोटो

पराली जलाने पर किसानों को भरना पड़ सकता है हर्जाना

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के लिए किसानों को भविष्य में पर्यावरणीय हर्जाना भरना पड़ सकता है। जहरीली हवा की समस्या से निपटने के लिए आयोग के गठन से संबंधित लोस में पेश बिल में यह प्रविधान किया गया है। (पेज-3)

ईडी की बड़ी कार्रवाई, यूनीटेक ग्रुप का लंदन स्थित होटल जब्त किया

- संजय तथा अजय चंद्रा के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट कंपनी यूनीटेक के मालिकों का लंदन स्थित होटल जब्त कर लिया। इस होटल की कीमत करीब 58.61 करोड़ रुपये है। ईडी ने यह कार्रवाई कंपनी के मालिकों संजय चंद्रा तथा अजय चंद्रा के खिलाफ प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत की है। बेड एंड ब्रेकफास्ट नाम के इस होटल का मालिकाना हक इबार्नशोर्न लिमिटेड नामक कंपनी के पास है जो कार्नोस्ती ग्रुप की ब्रिटेन स्थित सहायक कंपनी है। इस मामले में अब तक कुल 595.61 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि संपत्ति कुर्क करने के लिए पीएमएलए के तहत आदेश जारी किया गया था। बता दें कि फ्लैट खरीदारों ने यूनीटेक के मालिकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में एफआइआर दर्ज कराई थी। ईडी ने कहा, फ्लैट खरीदारों के 325 करोड़ रुपये गलत तरीके से कार्नोस्ती ग्रुप को स्थानांतरित किए गए। इनमें से 41.3 करोड़ रुपये कार्नोस्ती ग्रुप, इंडिया और इनडिजाइन इंटरप्राइजेज प्रा.लि., साइप्रस के जरिये ब्रिटेन स्थानांतरित किए गए। इस राशि का इस्तेमाल कार्नोस्ती ग्रुप से जुड़ी कंपनी कार्नोस्ती मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इबानशोर्न लिमिटेड, ब्रिटेन के शेयर खरीदने में किया गया।

प्रवर्तन निदेशालय ने यूनीटेक ग्रुप और इसके मालिकों के खिलाफ इस साल के शुरू में पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। संजय चंद्रा तथा अजय चंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से 2,000 करोड़ रुपये साइप्रस और केमैन द्वीप भेजे।

न्यूज गैलरी

जामिया की कुलपति मामले में एकल पीठ के फैसले को चुनौती

नई दिल्ली : जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति नजमा अख्तर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार, केंद्रीय सतर्कता आयोग, यूजीसी और जामिया से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई फिलहाल 22 सितंबर तक टाल दी है। जामिया वीसी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अपील की गई है। (जासं)

एंबियंस समूह का चेयरमैन राज गहलोत सात दिन की रिमांड पर

नई दिल्ली : मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार गुरुग्राम स्थित एंबियंस समूह के चेयरमैन राज गहलोत को पटियाला हाउस कोर्ट ने पांच अगस्त तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड पर भेजा है। ईडी ने 800 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गहलोत को गिरफ्तार किया है। (जासं)

चौथे दिन भी झमाझम बरसे बदरा, गर्मी से राहत बरकरार

नई दिल्ली : दिल्ली में लगातार चौथे दिन भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। इससे गर्मी से भी राहत बनी रही और तापमान भी सामान्य से कम ही रहा। शनिवार को भी कमोबेश ऐसा ही मौसम बना रहेगा। अगले चार-पांच दिन बारिश का दौर जारी रहेगा। शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 32.0 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा। (राब्यू)

यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर

नई दिल्ली : पहाड़ों पर मूसलधार बारिश से दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से दिल्ली की ओर लगातार हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। शुक्रवार शाम सात बजे तक यमुना का जलस्तर स्तर 205.56 मीटर पहुंच तक गया। जलस्तर लगातार बढ़ने से प्रशासन ने खादर के क्षेत्र में मुनादी करवाकर लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। (जासं)

मुस्लिमों की शादियों के पंजीकरण मामले में जवाब तलब

नई दिल्ली : मुस्लिमों की शादियों के पंजीकरण को लेकर दायर एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से चार अक्टूबर तक जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिमों की शादियों को विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के तहत पंजीकृत किया जा रहा है और बिना देरी और नोटिस के पंजीकरण की व्यवस्था देने वाले अनिवार्य विवाह आदेश के तहत पंजीकरण का विकल्प नहीं दिया जा रहा है। (जासं)

विधानसभा में दूसरे दिन भी हंगामा, विपक्ष का वाकआउट

सियासत ▶ आप विधायक भारती पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी को लेकर हुआ हंगामा

विपक्षी विधायक ओम प्रकाश शर्मा का निलंबन कुछ ही घंटे बाद वापस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा में मानसून सत्र के में दूसरे दिन शुक्रवार को भी हंगामा होता रहा। इस बार हंगामे की वजह विधायक सोमनाथ भारती पर विपक्ष के विधायक द्वारा की गई व्यंग्यात्मक टिप्पणी बनी। हंगामे के चलते न सिर्फ विधानसभा की कार्यवाही प्रभावित हुई, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष को विपक्ष के विधायक ओम प्रकाश शर्मा को अगले सत्र तक के लिए निलंबित भी करना पड़ा। इसके विरोध में भाजपा के सभी विधायकों ने सदन से वाकआउट कर दिया। हालांकि, नेता प्रतिपक्ष के आग्रह पर विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ घंटे बाद ही शर्मा का निलंबन वापस ले लिया।

दरअसल, दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने सदन के प्रश्नकाल के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) विधायक सोमनाथ भारती के बारे में एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर दी। इस पर भारती समेत सत्तापक्ष के कई विधायक विधानसभा अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए और बिष्ट से माफी मांगने की मांग पर अड़ गए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, जितेंद्र महाजन, अनिल बाजपेयी सहित अन्य भाजपा विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद अध्यक्ष ने आप विधायकों को अपनी सीटों पर लौटने का निर्देश दिया और बिष्ट से माफी मांगने को भी कहा, उन्होंने अन्य भाजपा विधायकों से भी शांति बनाए रखने के लिए कहा।

बिष्ट ने मांगी माफी : विधायक बिष्ट ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी, लेकिन शर्मा और महाजन चिल्लाते रहे। ऐसे में स्पीकर ने महाजन को 10 मिनट के लिए सदन से बाहर जाने को कहा और शर्मा को सदन को चलने नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। शर्मा नहीं माने और उन्होंने बिष्ट से माफी मंगवाने के स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाया, जिसके बाद गोयल ने उन्हें अगले सत्र के लिए निलंबित करने का आदेश दिया। गोयल के इस फैसले के बाद भाजपा के सभी विधायक सदन से बहिर्गमन कर गए। 70 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा के आठ सदस्य हैं, जबकि आप के 62 सदस्य हैं।



विधानसभा मानसून सत्र में बोलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सौजन्य-दिल्ली सरकार

डाक्टरों को सामूहिक रूप से भारत रत्न दिए जाने की मांग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से देश के सभी डाक्टरों को सामूहिक रूप से भारत रत्न देने की मांग की गई है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने यह प्रस्ताव रखा, जिसे सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष ने भी समर्थन दिया। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना काल में डाक्टर व अन्य स्वास्थ्यकर्मी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने उनके हित में कई कदम उठाए हैं। उनके रहने के लिए पांच सितारा होटल में व्यवस्था की थी। ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने से किसी की मृत्यु होने पर उनके स्वजन को एक करोड़ रुपये की राशि देने की घोषणा की गई। दिल्ली सरकार ने अब पद्म पुरस्कारों के लिए सिर्फ स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों के नाम भेजने का फैसला किया है। वहीं,नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लिफ्टमैन, पुलिसकर्मियों की भी कोरोना से लड़ाई में जान गई है। इनके स्वजनों को भी एक-एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि मिलनी चाहिए।

दिल्ली जीएसटी संशोधन विधेयक 2021 पास

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मानसून सत्र के दूसरे और अंतिम दिन दिल्ली जीएसटी संशोधन विधेयक 2021 भी पास हो गया। शुक्रवार को वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसका प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया। इसके तहत जीएसटी के सेक्शन 15 में संशोधन किया गया है और शेड्यूल दो के पैराग्राफ सात को हटा दिया गया। यह संशोधन 39वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंजूर किए गए थे।

सिसोदिया ने कहा कि प्रस्तावित दिल्ली जीएसटी (संशोधन) विधेयक 2021 व्यापारियों की कठिनाइयों को कम करने और जीएसटी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इससे फर्जी फर्म बनाकर टैक्स चोरी करने वालों पर भी लगाम लगेगी।

नहीं दिखा सकेंगे कम बिक्री : टैक्स भरते समय व्यापारी एक और फर्जीवाड़ा कर रहे थे। दरअसल कुछ लोग जीएसटीआर-एक और तीन बी फार्म भरते समय आर एक में बढ़ी हुई राशि और तीन बी में कम राशि दिखाते थे। इसके बाद जब आइटीसी पास करने की बात आती, तो लोग अधिक बिक्री का दावा करते हैं, लेकिन टैक्स भरने के समय बिक्री कम दिखाते हैं।

ये संशोधन किए गए हैं

- सेक्शन 15 के तहत व्यापारियों को कंपल्सरी आडिट और रिकान्सिलिएशन आफ स्टेटमेंट देना जरूरी था। इस बाध्यता को अब हटा दिया गया है।
- माल से भरी गाड़ी जब्त होने पर अभी तक सामान तब छोड़ा जाता था जब व्यापारी टैक्स और जुर्माना दोनों देते थे। अब सामान की कीमत पर जुर्माना देना होगा। टैक्स बाद में दिया जा सकेगा।
- रिटर्न देर से फाइल होने की स्थिति में ग्रास अमाउंट पर ब्याज देना पड़ता था। अब केवल जो अमाउंट टैक्स के रूप में नकद दिया जाएगा, उस पर ब्याज लगेगा। ये व्यवस्था एक जुलाई 2017 से लागू मानी जाएगी।
- फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी चोरी करने वाले लोगों की संपत्ति भी अब कुर्क की जाएगी। अभी तक सिर्फ उसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती थी, जिसके नाम फर्म रजिस्टर्ड है, लेकिन अब फर्जीवाड़े में शामिल मास्टरमाइंड पर भी गाज गिरेगी।
- ई-वे बिल के मामले में अभी गाड़ी पकड़े जाने पर विवादित राशि का 10 फीसद प्री-डिपाजिट रखने का प्रविधान है, जिसे बढ़ाकर 25 फीसद किया गया है।

बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत पंजीकरण अब सिर्फ 30 दिनों में

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- मकान मालिकों को आनलाइन ही उपलब्ध कराया जाएगा सर्टिफिकेट
- इस योजना के तहत अब तक 347 मकानों के 1630 कमरे हो चुके हैं पंजीकृत

दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत पंजीकरण अब 90 के बजाय सिर्फ 30 दिनों में होगा। एक माह में पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और पंजीकरण कराने वाले अपने घर में पर्यटकों को ठहरने की सुविधा देकर कमाई कर सकेंगे। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) भोजन तथा शयन कक्ष संस्थापन (पंजीकरण एवं विनियम) (संशोधन) विधेयक 2021 रखा, जिसे विधानसभा में पारित कर दिया गया।

सिसोदिया ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए अब मकान मालिकों को सर्टिफिकेट लेने के लिए दफ्तरों में नहीं जाना होगा, बल्कि उन्हें आनलाइन ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए घर में एक से छह कमरे तक खाली होने के साथ ही जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए। इसके अलावा मकान मालिक के परिवार का उसी घर में रहना जरूरी है। मकान गेस्ट हाउस, लाज या होटल की श्रेणी में आता है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इससे न सिर्फ ईज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आवेदन करने वालों को फास्ट डिलीवरी भी मिलेगी।

सिसोदिया के मुताबिक योजना में सुविधाओं की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता के आधार पर कमरों को गोल्ड और सिल्वर नाम से दो श्रेणियों में रखा जाता है। इसका विवरण पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है। इससे पर्यटक बिना किसी बिचौलिए के संपर्क में आए सीधे मकान मालिक से संपर्क कर सकेंगे। इस योजना के तहत अब तक 347 मकानों के 1630 कमरे पंजीकृत हो चुके हैं। सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नियमों में बदलाव करने के बाद यह संख्या तेजी से बढ़ेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन कानून वापस लेने का प्रस्ताव पास

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन कानून निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने सदन में यह प्रस्ताव रखा था। मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि यह कानून संविधान की भावना के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना है, इसलिए केंद्र सरकार को इसे वापस लेना चाहिए।

इससे पहले त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली विधानसभा और इसकी समितियों के अधिकार क्षेत्र में असंवैधानिक तरीके से हस्तक्षेप किया गया है। यह दिल्ली दंगा के आरोपितों को बचाने के लिए किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा और भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण देकर दिल्ली का माहौल खराब किया। अब इन्हें बचाने की कोशिश हो रही है।

जबकि भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने इस कानून को सही ठहराते हुए कहा कि इस कानून में लोकसभा के समान विधानसभा की समितियों को शक्ति दी गई है। समितियों की शक्ति कम नहीं हुई है।

नए कृषि कानून निरस्त करने की मांग, भाजपा ने किया विरोध

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा में तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव पास किया गया। आप के विधायक जरनैल सिंह ने सदन में प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से इन कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इसे वापस नहीं ले रही है। मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दो-तीन बड़ी कंपनियों को ध्यान में रखकर ये कानून बनाए गए हैं। कृषि उत्पाद की भंडारण क्षमता की सीमा हटाने से कंपनियों को फायदा हुआ है। बिहार व उत्तर प्रदेश के किसानों को कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं मिलता है। अब सरकार पूरे देश में इसे खत्म कर रही है, जिससे पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों के किसानों का हाल भी बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों की तरह हो जाएगा।

बिधूड़ी बोले, केजरीवाल सरकार ने इसे दिल्ली में दी है मंजूरी

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि तीनों कृषि सुधार कानून को संसद ने पास किया है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में इसे मंजूरी दी है। इन कानूनों से किसानों की आय बढ़ेगी। मंडियों का विस्तार होगा। ये कानून पास होने के बाद हरियाणा और पंजाब में रिकार्ड खरीदारी हुई है। दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मूल्य से 50 फीसद ज्यादा मूल्य देने का वादा किया था, उसे पूरा करे। उन्होंने किसानों की भूमि अधिग्रहित करने पर उन्हें आवासीय भूखंड देने, मुआवजा बढ़ाने और गांवों की जमीन को जनहित में उपयोग करने की मांग की। उन्होंने किसानों के हित में केंद्र सरकार की योजनाओं को दिल्ली में लागू करने, मुफ्त बिजली देने और कृषि उपकरण पर सब्सिडी देने की मांग की। आप नेता सत्येंद्र जैन ने भी ग्राम सभा की जमीन का उपयोग जनहित में करने की मांग का समर्थन किया।

दिल्ली सरकार पर नहीं है निगमों का बकाया : जैन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार को निगमों को बकाया देना नहीं बल्कि उनसे लेना है। तीनों नगर निगमों पर दिल्ली सरकार का 6,836 करोड़ रुपये बकाया है। यह जानकारी शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रश्नकाल के दौरान सदन को दी। दरअसल, आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को दी जाने वाली वित्तीय राशि के आवंटन से जुड़ी राशि की जानकारी मांगी थी। जैन ने कहा कि 2015 से अब तक दिल्ली के तीनों निगमों पर दिल्ली सरकार का अलग-अलग बकाया है। दक्षिणी निगम के ऊपर 760 करोड़ रुपये, पूर्वी दिल्ली पर 2,407 करोड़ और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के ऊपर 3,669 करोड़ रुपये बकाया है।

सत्येंद्र जैन ने सदन में दावा किया कि भाजपा के विधायक भी मान रहे हैं कि निगमों की सड़कों व सफाई का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि निगमों की बदहाली व भ्रष्टाचार के लिए भाजपा जिम्मेदार है।

निगमों का गला घोट रही दिल्ली सरकार : भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा कि दिल्ली सरकार नगर निगमों का गला घोट रही है। पांचवें दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निगमों को फंड नहीं दे रही है। आप का निगमों पर कब्जा करने का सपना कभी पूरा नहीं होगा।

सीबीएसई के परिणामों से डीयू में दाखिले का मुकाबला होगा कड़ा

संजीव कुमार मिश्र, नई दिल्ली

- डीयू के प्रमुख कालेजों में शुरुआती तीन कटआफ ऊंचा रहने के आसार
- टाप कालेज 99.5 फीसद से शुरू कर सकते हैं कटआफ

सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इस बार एक लाख 50 हजार से अधिक छात्रों को 90 फीसद से अधिक नंबर मिले हैं। इनमें भी 70 हजार से अधिक छात्रों को 95 फीसद से अधिक नंबर प्राप्त हुए हैं। यह संख्या गत वर्ष के मुकाबले अधिक है। ऐसे में डीयू में दाखिले के लिए बेहद कड़ा मुकाबला होने वाला है।

डीयू दाखिला समिति के अध्यक्ष प्रो. राजीव गुप्ता कहते हैं कि ज्यादा संख्या में छात्रों को अधिक नंबर मिले हैं, ऐसे में डीयू के कटआफ ऊंचे रहना स्वाभाविक है। हालांकि, अभी जेईई, नीट, व क्लैट होना बाकि है। अक्सर ये परीक्षाएं डीयू में दाखिले से पहले हो जाती थीं, जिससे काफी छात्र इन परीक्षाओं के जरिये इंजीनियरिंग, मेडिकल व कानून की पढ़ाई करने चले जाते थे, लेकिन इस बार अभी ये परीक्षाएं भी होना बाकी है, ऐसे में ज्यादातर छात्र डीयू में आवेदन तो करेंगे ही, जिससे दाखिले के लिए बेहद कड़ा मुकाबला होने की संभावना है।

वहीं, रामानुजन कालेज के प्राचार्य प्रो. एसपी अग्रवाल कहते हैं कि अभी तो राज्यों के बोर्ड के परीक्षा परिणाम आने बाकि हैं। डीयू में अन्य बोर्ड के छात्र भी दाखिला लेते हैं। केरल, मध्य प्रदेश बोर्ड के छात्रों के अंक अधिक होते हैं। इस बार हरियाणा, यूपी, बिहार में भी मूल्यांकन के जरिये ही परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। ऐसे में ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या काफी होगी।

इसका असर यह होगा कि डीयू के कालेजों का कटआफ दो से तीन फीसद ऊपर चला जाएगा। शीर्ष कालेजों का कटआफ 99.5 से शुरू होने की संभावना है। डीयू में दो अगस्त से स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।

दिल्ली-एनसीआर में चार सालों में प्रदूषक तत्व 20 फीसद घटे

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आइआइटी दिल्ली के विशेषज्ञों का अध्ययन

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और आइआइटी दिल्ली के विशेषज्ञों ने एक संयुक्त अध्ययन में पाया है कि दिल्ली-एनसीआर में पार्टिकुलेट मैटर (प्रदूषक तत्व पीएम 2.5) के स्तर में पिछले चार वर्षों के दौरान 20 फीसद की गिरावट आई है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि भारत ने हाल ही में नेशनल बायोमास मिशन की घोषणा की है। यह एक बहु मंत्रालयीय प्रयास है, जिससे पीएम 2.5 के स्तर में और भी सुधार होने की उम्मीद हैं। इसके तहत न सिर्फ कृषि क्षेत्र, बल्कि नगरीय और अन्य अनेक सेक्टर भी कवर होंगे।

वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के अवसरों पर बातचीत के लिए इंटरनेशनल सेंटर फार इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (आइसीआइएमओडी) और क्लाइमेट ट्रेंड्स ने एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें विशेषज्ञों ने समूचे दक्षिण-एशिया में विकराल रूप लेती वायु प्रदूषण की समस्या और उसके स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं की भयावहता को सामने रखा।



प्रदूषण में और भी सुधार की उम्मीद। फाइल फोटो

आइआइटी कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डा. एसएन त्रिपाठी ने कहा कि भारत और नेपाल के सिंधु गंगा के संपूर्ण मैदानों के बीच एक अप्रत्याशित समानता है। काठमांडू में पीएम 2.5 का स्तर दिल्ली के मुकाबले बढ़ा हुआ दिखाई देता है। वहीं, ढाका में यह अब भी काफी कम है। अगर ढाका व कानपुर की बात की जाए तो घरों में खाना बनाने से निकलने वाला प्रदूषण वायु प्रदूषण के लिए बड़ा जिम्मेदार है। जबकि रसोई गैस का इस्तेमाल होने से घरेलू उत्सर्जन में बहुत कमी आई है। उन्होंने कहा कि कानपुर और ढाका के बीच एक और महत्वपूर्ण समानता यह है कि ढाका में पीएम 2.5 का स्तर कानपुर के मुकाबले कम है, लेकिन धात्विक संकेंद्रण यानी लेड की मात्रा की बात करें तो ढाका की हवा में इसकी मात्रा काफी ज्यादा है।

प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र सरकार का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी काफी हद तक शहरों पर केंद्रित है। इसमें 113 नान अटेनमेंट सिटीज को चयनित किया गया है जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को नहीं अपनाती। जल्द ही नेशनल नालेज नेटवर्क के तहत देश के उच्च प्रौद्योगिकी संस्थानों को साथ लेकर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को जमीन पर उतारा जाएगा।

अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले पांच लोग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मालवीय नगर थाना पुलिस ने तकनीकी सहायता के नाम पर अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले गिरोह का राजफाश करते हुए काल सेंटर में मौजूद एक महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों से 13 कंप्यूटर व बड़ी संख्या में इलेक्ट्रानिक उपकरण बरामद किए गए हैं।

दक्षिणी जिले के पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि कांस्टेबल हरिकेश व कांस्टेबल राजेश खिड़की एक्सटेंशन इलाके में गुरुवार रात को गश्त कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने बताया कि पंचशील विहार इलाके में एक काल सेंटर चल रहा है जहां से अमेरिकी नागरिकों से ठगी की जाती है। पुलिसकर्मियों ने एसएचओ सतीश कुमार को जानकारी दी। फिर टीम ने जब काल सेंटर पर छापा मारा तब सभी अमेरिकी नागरिकों को फोन करने में व्यस्त थे। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मयंक, चंदन, शुभम, प्रीतपाल सिंह और किनकिनी दास के तौर पर हुई है। इसमें प्रीतपाल सिंह इस काल सेंटर का मालिक है, जबकि महिला किनकिनी दास एचआर मैनेजर है। जांच में सामने आया कि इस काल सेंटर में एक्स लाइट एवं आइबीम नाम के विशेष साफ्टवेयर का इस्तेमाल फोन करने के लिए किया जाता था। इस साफ्टवेयर से इंटरनेट आधारित काल की जाती थी और सरकारी राजस्व को भी क्षति पहुंचाई जाती थी। आरोपितों ने बताया कि वे अमेरिकी नागरिकों से बात कर उनके सिस्टम में वायरस अटैक का भय दिखाकर मैसेज भेजते थे। फिर 100 से 400 डालर तक की रकम ई-वालेट के जरिये वसूल लेते थे। पुलिस ठगे गए लोग और कुल रकम का आकलन कर रही है।

आनलाइन ठगी का हब बनी दक्षिणी दिल्ली : दक्षिणी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में विदेशी नागरिकों के साथ ठगी करने वाले काल सेंटर चल रहे हैं। पिछले चार माह में पुलिस ने 80 से अधिक व्यक्तियों को ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है।

सुखद

बायो डायवर्सिटी पार्कों से जग रही हरियाली की उम्मीद

विभिन्न पार्कों में चल रहे कीकर उन्मूलन के कार्यक्रम, इनमें लगाए जा रहे हैं देशज पौधे, बढ़ रही हरियाली

अरविंद कुमार द्विवेदी, नई दिल्ली

राजधानी में हर तरफ फैले कीकर के जाल को खत्म करने के लिए विभिन्न बायो डायवर्सिटी पार्कों व कुछ पब्लिक पार्कों में चल रही परियोजनाओं से उम्मीद जगती है। वसंत विहार स्थित अरावली बायो डायवर्सिटी पार्क, नेब सराय स्थित तिलपथ वैली बायो डायवर्सिटी पार्क और वसंत कुंज स्थित नीला हौज बायो डायवर्सिटी पार्क में से काफी हद तक विलायती कीकर के पेड़ खत्म हो गए हैं। वहीं, इन पार्कों के जरिये लोगों को देशज पेड़-पौधों के प्रति जागरूक करने के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनके जिस हिस्से से विलायती कीकर खत्म हो रहा है, वहां पर इसे दोबारा पनपने नहीं दिया जा रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फार एन्वायर्नमेंटल मैनेजमेंट आफ डीग्रेडेड ईकोसिस्टम (सीईएमडीई) के हेड प्रो. सीआर बाबू के नेतृत्व में ये सभी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। वहीं, ग्रेटर कैलाश में 435 एकड़ में फैले डीडीए के जहांपनाह सिटी फारेस्ट में भी कीकर की जगह देशज पेड़ लगाकर पार्क विकसित किए गए हैं। पार्क में रोजाना हजारों लोग घूमने आते हैं।



नीला हौज बायो डायवर्सिटी पार्क में फैली हरियाली। फोटो- पार्क प्रबंधन

तिलपथ वैली का 90 प्रतिशत हिस्सा हुआ कीकर मुक्त: नेब सराय स्थित तिलपथ वैली बायो डायवर्सिटी पार्क में कीकर को खत्म करने के लिए वर्ष 2015 से लेकर अब तक करीब डेढ़ लाख से ज्यादा देशज पौधे लगाए जा चुके हैं। पार्क के ईकोलाजिस्ट व साइंटिस्ट इंचार्ज डा. आर जया कुमार ने बताया कि अब पार्क के लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्रफल से कीकर के पेड़ खत्म हो चुके हैं। पार्क सुबह व शाम आम लोगों व पर्यावरण प्रेमियों के लिए खुला रहता है। यहां पर करीब 200 लोग नियमित रूप से घूमने आते हैं। इससे लोगों को प्राकृतिक माहौल में घूमने के साथ ही विभिन्न वन्यजीव व पक्षियों को देखने का मौका भी मिलता है। यहां पर तितली पार्क भी बनाया गया है।

डा. आर जया कुमार ने बताया कि इस पार्क को विकसित करने का मकसद अरावली को उसका अपना ईको सिस्टम लौटाना है। पार्क में अरावली के प्राकृतिक पेड़-पौधे व लताएं ही लगाई गई हैं।

नीला हौज से खत्म हुआ कीकर: वसंत कुंज स्थित करीब 10 एकड़ में फैले नीला हौज बायो डायवर्सिटी पार्क में से विलायती कीकर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कीकर को खत्म करने के लिए यहां पर 35 देसी प्रजातियों के 10 हजार से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जो अब काफी बड़े हो गए हैं। इससे यहां पर करीब 70 प्रजातियों के पक्षी भी दिखाई देने लगे हैं।

पार्क के फील्ड सुपरवाइजर नरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि यहां एक तितली पार्क व एक लैंडस्केप गार्डन भी बनाया गया है। यह पार्क संजय वन के पास स्थित है। वहीं, वसंत विहार के अरावली बायो डायवर्सिटी पार्क से भी कीकर को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। यहां पर बने बटरफ्लाई पार्क में तमाम तरह की तितलियां हैं। यह सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि यहां सैकड़ों प्रजाति के देशज पेड़-पौधे लगाए गए हैं।

दिल्ली दंगा : ताहिर समेत 13 आरोपितों की न्यायिक हिरासत 21 तक बढ़ी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली दंगे की साजिश रचने के मामले में मुख्य आरोपित व आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, जेएनयू के छात्र शरजील इमाम, पूर्व पार्षद इशरत जहां समेत 13 आरोपितों की न्यायिक हिरासत 21 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

गत वर्ष फरवरी में हुए दंगे में 53 लोगों की जान गई थी, जबकि 550 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बड़े स्तर पर निजी और सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ था। इस मामले के 18 आरोपितों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। जिसमें से पांच को जमानत मिल चुकी है। जबकि मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, जेएनयू छात्र शरजील इमाम, कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां समेत अन्य सलाखों के पीछे हैं। शुक्रवार को इनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी।

971 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आनी है नए संसद भवन पर। अगले साल अक्टूबर तक इसका निर्माण कार्य पूरा होना है। इसके निर्माण पर अब तक 238 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह भी हंगामे की भेंट चढ़ा

संसद में गतिरोध जारी ▶ पेगासस जासूसी कांड और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने दिखाया आक्रामक रुख

हंगामे के बीच सरकार ने पारित कराए कई विधेयक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद के मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह भी विपक्ष के शोर-शराबे और हो-हल्ले की भेंट चढ़ गया। पेगासस जासूसी कांड और किसानों के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा सप्ताह के आखिरी दिन भी नहीं थमा। विपक्ष जहां पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं सरकार भी उनके दबाव में नहीं आती दिख रही। सरकार ने इस सप्ताह विपक्ष के हंगामे के बीच कई विधायी कार्य कराए और बिना चर्चा कई विधेयक पारित करा लिए।

संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की ओर से विपक्षी नेताओं को साधने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक बात नहीं पाई है। उम्मीद की जा रही है कि अगले सप्ताह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कोई रास्ता निकल जाए।

दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही रोजाना की तरह शुक्रवार को भी विपक्ष ने अपनी चिरपरिचित शैली में विरोध करना शुरू किया। प्लेकार्ड लहराते विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच सरकार ने राज्यसभा में दो विधेयक पेश किए और ध्वनिमत से एक विधेयक पारित करा लिया। लोकसभा में भी दो विधेयक पेश किए गए। हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

राज्यसभा में शून्यकाल नहीं चल सका। हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्यवाही दोपहर ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उपसभापति हरिबंश ने सदन के दोबारा बैठने पर गैरविधायी कार्य के लिए सदस्यों के नाम पुकारे, लेकिन न किसी ने अपने संकल्प पेश किए और न ही किसी पर चर्चा शुरू हो सकी। इस बीच कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वामदलों के सदस्य एक बार फिर आक्रामक हो गए और सदन के बीचोबीच पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच उपसभापति ने सीमित भागीदारी (संशोधन) विधेयक-2021 और डिपाजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन बिल-2021 पेश करा दिया। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक-2021 पेश किया जो चर्चा के बगैर ध्वनिमत से पारित भी हो गया।

लोकसभा में दूसरे हफ्ते के आखिरी दिन भी हंगामा पूर्ववत जारी रहा। शुक्रवार को कार्यवाही शुरू होते ही शोर-शराबा होने पर लोकसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। दोबारा सदन शुरू होने पर हालात ज्यों के त्यों रहे। लेकिन पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल इस दौरान कुछ विधायी कार्य पूरा कराते रहे। इसी दौरान 'द कमीशन फार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडज्वाइनिंग एरिया बिल-2021' को वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पेश किया। जबकि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस (नेशनलाइजेशन) संशोधन बिल-2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया।

शोर-शराबे के बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने विपक्ष पर गैरजरूरी मुद्दे पर हंगामा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों पर विपक्ष बिफर रहा है, उसे लेकर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का विस्तृत बयान पहले ही आ चुका है। विपक्ष बिना किसी वाजिब मुद्दे के संसद के कामकाज में अवरोध पैदा कर रहा है। संसद में हंगामा कर कामकाज रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तैयार है।

संसद परिसर में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गतिरोध तोड़ने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, जिसके लिए वह तैयार नहीं है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने मांग की, 'सबसे पहले पेगासस जासूसी मामले की चर्चा होनी चाहिए, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें और उस समय संसद में प्रधानमंत्री मौजूद रहें।'


पेगासस जासूसी कांड समेत विभिन्न मुद्दों पर शुक्रवार को भी राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। प्रेट्र

लोकसभा का 86 फीसद और राज्यसभा का 78 फीसद समय बर्बाद

देश की प्रमुख समस्याओं पर नीति बनाने और लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई को शुरू हुआ। तब से विपक्ष ने जासूसी मामले सहित अन्य मुद्दों पर देश की सबसे बड़ी पंचायत को लगातार बंधक सा बना रखा है। रोजाना के हंगामे में दोनों सदनों का बहुमूल्य समय नष्ट हो रहा है। संसद के कामकाज पर बारीक नजर रखने वाली संस्था पीआरएस लेजिस्लेटिव के अनुसार गुरुवार तक संसद का निचला सदन यानी लोकसभा अपने तय घंटे का सिर्फ 14 फीसद ही काम कर सकी। यानी 86 फीसद समय हंगामे की भेंट चढ़ा। यही हाल राज्यसभा का भी रहा। इसी समयावधि में संसद के इस उच्च सदन का 78 फीसद समय बेकार गया। कामकाज के तय घंटे का सिर्फ 22 फीसद ही सार्थक रहा।

पराली जलाने पर किसानों को भरना पड़ सकता है हर्जाना

▸ एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए लोकसभा में बिल पेश

▸ विधेयक में उपयुक्त शक्तियों के साथ वैधानिक प्राधिकरण स्थापित करने का प्रविधान

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आस-पास के इलाकों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के लिए किसानों को भविष्य में पर्यावरणीय हर्जाना भरना पड़ सकता है। एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में जहरीली हवा की समस्या से निपटने के लिए आयोग के गठन संबंधित शुक्रवार को लोकसभा में पेश बिल में यह प्रविधान किया गया है।

किसानों और पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे पर विपक्ष के भारी शोर-शराबे के बीच इस बिल को सदन में पेश किया गया। इसमें एनसीआर और इसके आस-पास के इलाकों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त शक्तियों के साथ एक वैधानिक प्राधिकरण स्थापित करने का प्रविधान किया गया है।

'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2021' नामक यह विधेयक पारित होने के बाद हाल ही में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक के मुताबिक आयोग पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण का कारण बनने वाले किसानों पर निर्धारित दर और तरीकों से पर्यावरणीय मुआवजा लगा सकता है और एकत्र कर सकता है। पर्यावरण मंत्री भूपेंदर यादव की ओर से इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों पर जारी बयान में कहा गया है कि वायु प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर है और इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए देश में एक स्व-नियामकीय तंत्र की जरूरत है जिसकी लोकतांत्रिक रूप से निगरानी की जा सके। यह आयोग पुराने पैनलों का स्थान लेगा और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जन सहयोग और शोध आदि को प्रोत्साहित करेगा।

मार्च में समाप्त हो गया था पहला अध्यादेश

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में कानून की तत्काल आवश्यकता थी और संसद सत्र नहीं चल रहा था इसलिए 28 अक्तूबर, 2020 को एनसीआर और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2020 लाया गया था। लेकिन इस अध्यादेश को बदलने के लिए एक विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सका। नतीजतन, 12 मार्च, 2021 को अध्यादेश समाप्त हो गया। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2021 को 13 अप्रैल, 2021 को अधिसूचित किया गया था।

एन. राम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह करेगा सुनवाई

पेगासस जासूसी कांड

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पेगासस जासूसी कांड की वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से स्वतंत्र जांच कराने की मांग संबंधी वरिष्ठ पत्रकार एन. राम और शशि कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। शुक्रवार को उनकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की। सिब्बल ने कहा कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों की स्वतंत्रता व निजता से जुड़ा हुआ है। इसका व्यापक असर है। सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह इस मामले को अगले सप्ताह सुनवाई पर लगाएंगे।

याचिका में कहा गया है कि पत्रकारों, राजनेताओं आदि की इजरायली स्पाइवेयर पेगासस से जासूसी की गई जो गंभीर मामला है। इसमें अवैध तरीके से फोन हैकिंग हुई। यह अभिव्यक्ति की आजादी व असहमति को दबाने की कोशिश है। याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह बताए कि क्या किसी सरकारी एजेंसी के पास प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी तरह से निगरानी करने का पेगासस स्पाइवेयर लाइसेंस है।

याचिका के मुताबिक, विश्व के विभिन्न मीडिया समूहों ने उजागर किया है कि बहुत से भारतीयों जिनमें पत्रकार, नेता, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट आदि शामिल हैं, की पेगासस स्पाइवेयर के जरिये निगरानी हुई है। मिलिट्री ग्रेड स्पाइवेयर का प्रयोग कर निगरानी की गई जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। ये निजता के अधिकार का हनन है। इसके अलावा अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन हुआ है। पहली निगाह में यह साइबर आतंकवाद है जिसके राजनीतिक और सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रभाव हैं।

स्कूल, कालेज खोलने पर जल्द होगा फैसला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ राज्यों के साथ चर्चा के बाद जारी हो सकती है गाइडलाइन, शिक्षा मंत्रालय ने दिए संकेत


फिलहाल राज्यों को ही स्कूल खोलने पर निर्णय लेने का है अधिकार। फाइल/इंटरनेट मीडिया

वैक्सीनेशन की मांगी रिपोर्ट

शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की भी रिपोर्ट मांगी है। साथ ही सीबीएसई और यूजीसी को भी निर्देश दिए हैं कि वे स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अब तक हुए वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी जुटाएं और यह सुनिश्चित करें कि शिक्षण संस्थानों से जुड़े सभी कर्मचारी वैक्सीन की डोज लगवा लें। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद मंत्रालय निर्णय लेने की स्थिति में होगा।

कोरोना संक्रमण में पहले के मुकाबले भारी कमी दर्ज होते ही स्कूल-कालेजों सहित दूसरे सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का सिलसिला फिर चल पड़ा है। मध्य प्रदेश, बिहार व हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों ने नौवीं से 12वीं तक के स्कूलों को अपनी सहूलियत के आधार पर खोल दिए हैं। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य अभी इसको लेकर असमंजस में हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र ने राज्यों के असमंजस को खत्म करने को लेकर रुचि दिखाई है। साथ ही संकेत दिया है कि राज्यों के साथ चर्चा करके जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। जरूरत पड़ी तो स्टैंडर्ड गाइडलाइन भी जारी की जाएगी।

शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर यह दिलचस्पी उस समय दिखाई है, जब संक्रमण में कमी आने पर कई राज्यों ने अपने स्कूल खोल दिए हैं, जबकि कुछ राज्य अभी कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। यह स्थिति तब है, जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर स्कूल-कालेज खोलने और बंद करने का अधिकार दिया गया था। फिलहाल अभिभावकों और छात्रों की ओर से इस पर उठाए जा रहे सवालों को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों के साथ इस पर चर्चा करने का फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार, अगले हफ्ते राज्यों के साथ इस मसले पर चर्चा हो सकती है। इस चर्चा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी मौजूद रह सकते हैं।

शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने को लेकर सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण में कमी के बाद बाजार, माल, क्लब, सिनेमा आदि पहले जैसी सामान्य स्थिति में बहाल कर दिए गए हैं। ट्रेनों और बसों में भी सामान्य आवाजाही शुरू हो गई है। वैसे भी 12वीं का रिजल्ट आने के बाद से उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला शुरू होने वाला है। आने वाले दिनों में नीट जैसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा भी होने वाली है। ऐसे में शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा गया तो समस्याएं और बढ़ सकती हैं।

प्रदूषित नदी क्षेत्रों की संख्या 302 से बढ़कर 351 हुई

नई दिल्ली, आइएएनएस : देश में प्रदुषित नदी क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2015 में ऐसे क्षेत्रों की संख्या 302 थी, जो 2018 में बढ़कर 351 हो गई। यह जानकारी लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दी गई।

देश की नदियों में प्रदूषण को लेकर पूछे गए सवालों के लिखित उत्तर में केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नदियों में सबसे ज्यादा प्रदूषण गंदे नालों एवं सीवर के पानी से हो रहा है। इसके अलावा तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ औद्योगिकीकरण भी इसके लिए जिम्मेदार है। मंत्री ने कहा कि कुछ विशेषज्ञों ने नदियों के जलप्रवाह में कमी को लेकर चिंता जताई है, लेकिन जलप्रवाह के आंकड़ों पर निगरानी रखने वाले केंद्रीय जल आयोग ने विगत वर्षों की स्थिति का अध्ययन किया है और उसने कहीं पर भी जल की उपलब्धता में उल्लेखनीय कमी का संकेत नहीं दिया। पटेल ने कहा कि आयोग के मुताबिक बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और लोगों की बदलती जीवनशैली से देश में प्रति व्यक्ति सालाना जल उपलब्धता में कमी आई है। उन्होंने बताया कि 351 प्रदूषित नदी क्षेत्रों को पांच प्राथमिकता वर्ग में श्रेणीबद्ध किया गया है।

पटेल ने कहा कि आयोग के मुताबिक बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण व लोगों की बदलती जीवनशैली से देश में प्रति व्यक्ति सालाना जल उपलब्धता में कमी आई है। 351 प्रदूषित नदी क्षेत्रों को पांच प्राथमिकता वर्ग में श्रेणीबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत 16 राज्यों में 77 नगरों के 34 प्रदूषित नदी क्षेत्रों को लाया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए 5965.90 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की परियोजनाओं के लिए नमामी गंगे के तहत भी 30,235 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

भारत व अमेरिका ने वैश्विक कल्याण का समझौता पांच साल के लिए बढ़ाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास में साझेदारी के लिए अपना समझौता और पांच साल के लिए बढ़ा लिया है। यह समझौता सहयोगी देशों को संयुक्त रूप से मदद मुहैया कराने के संबंध में है। इस समझौते के जरिये दोनों देश संपर्क बढ़ाने, कारोबार, निवेश, स्वास्थ्य सुविधाओं और कृषि के क्षेत्र में मदद मुहैया कराते हैं। यह समझौता त्रिकोणीय आधार पर है, जिसमें भारत और अमेरिका के अलावा मदद पाने वाला देश भी भागीदार बनता है।

स्टेटमेंट आफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स (एसजीपी) पर सबसे पहले नवंबर 2014 में दस्तखत हुए थे। इसके बाद इसमें बढ़ोतरी होती रही। 2026 में इस समझौते में संशोधन किया जाएगा। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि यह समझौता दोनों देशों को खासतौर पर एशिया और अफ्रीका में साथ मिलकर विकास कार्यों को करने का मौका देगा। इस समझौते के जरिये दोनों देश वैश्विक स्थिरता और संपन्नता के लिए कार्य करेंगे।



कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार अगले सप्ताह

कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बासवराज सोमप्पा बोम्मई ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उन्हें नए सफर की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं और राज्य के विकास के लिए पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। बोम्मई ने पीएम से मुलाकात के बाद कहा कि कर्नाटक में बाढ़ और कोरोना की स्थिति को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार अगले सप्ताह किया जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद बोम्मई पहली बार दिल्ली के दौरे पर हैं। इससे पहले दिन में बोम्मई ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। प्रेट्र

संसदीय समिति की बैठक में नहीं आए अफसर, थरूर ने की कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली, प्रेट्र : सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष व कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर मंत्रालयों के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने आखिरी समय में समिति की बैठक में उपस्थित होने से इन्कार कर दिया था।

पेगासस जासूसी मामले समेत कई मसलों पर चर्चा के लिए बुधवार को समिति की बैठक होनी थी। इसमें इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय व संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के अधिकारियों को समन किया गया था। यह बैठक नहीं हो सकी क्योंकि समिति में शामिल भाजपा सदस्यों ने उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए, हालांकि वे बैठक कक्ष में उपस्थित थे। इससे बैठक का कोरम पूरा नहीं हो सका। बिरला को लिखे पत्र में थरूर ने कहा कि बुधवार दोपहर तीनों मंत्रालयों/विभागों से ईमेल प्राप्त हुआ कि उनके प्रतिनिधि समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

अमेरिका जाने वाली फ्लाइट होंगी दोगुनी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ अगस्त से प्रति सप्ताह एयर इंडिया के 22 विमान जाएंगे अमेरिका

▸ पढ़ाई करने वाले सैकड़ों भारतीय छात्रों को मिलेगी इससे राहत

अमेरिका में पढ़ाई करने वाले सैकड़ों भारतीय छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। एयर इंडिया अगस्त के पहले सप्ताह से अमेरिका जाने वाले विमानों की संख्या को दोगुनी करने जा रही है। अभी अमेरिका जाने वाले विमानों की संख्या कम होने से छात्रों को टिकट मिलने में भारी दिक्कत के साथ काफी अधिक किराया भी देना पड़ रहा है।

एयर इंडिया के मुताबिक अभी एक सप्ताह में 11 विमान अमेरिका जा रहे हैं, जिनकी संख्या सात अगस्त से बढ़ाकर 22 कर दी जाएगी। एयर इंडिया अगस्त के पहले सप्ताह से अमेरिका जाने वाले अधिक से अधिक यात्री को समायोजित करने की कोशिश कर रही है। एयर इंडिया के ट्वीट के मुताबिक इन 22 विमानों के अलावा नई दिल्ली से न्यूयार्क के लिए छह, 13, 20 और 27 अगस्त को एयर इंडिया के विमान उड़ान भरेंगे।

सूत्रों के मुताबिक, फ्लाइट की संख्या बढ़ने के बावजूद अमेरिका में पढ़ रहे छात्रों व काम करने वाले पेशेवरों को आसानी से टिकट नहीं मिलने जा रहा है। बड़ी संख्या में अमेरिका में पढ़ने वाले छात्र वहां जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

एयर इंडिया ने पहले ही अगस्त के पहले सप्ताह से अमेरिका जाने वाले विमानों की संख्या में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। हाल ही में एयर इंडिया की तरफ से अमेरिका जाने वाले विमान की उड़ान को रद करने एवं उसका नया समय देने को लेकर इंटरनेट मीडिया पर छात्रों ने काफी आलोचना की थी। कहा गया कि एयर इंडिया की तरफ से विमान रद होने की कोई जानकारी नहीं दी गई।

इस मामले में एयर इंडिया की तरफ से कहा गया कि कोरोना की वजह से अमेरिका की उड़ान को प्रतिबंधित कर दिया गया। इनमें मुंबई से न्यूयार्क जाने वाली उड़ान भी शामिल थी। एयर इंडिया के मुताबिक इस उड़ान को रद करने की जानकारी यात्रियों को पहले ही दे दी गई थी।

31 अगस्त तक अंतरराष्ट्रीय यात्री विमानों का बढ़ाया गया निलंबन

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतरराष्ट्रीय यात्री विमानों पर लगाए गए निलंबन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार को कहा कि हालांकि, चुनिंदा मार्गों पर सक्षम अधिकारियों द्वारा अलग-अलग मामलों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकेगी। भारत में कोरोना वायरस महामारी के चलते 23 मार्च, 2020 से अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें निलंबित हैं।

योग्यता का आकलन

एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के सभी छात्रों को देनी होगी यह परीक्षा, विदेश से एमबीबीएस करके आने वाले छात्रों को इसी परीक्षा के आधार पर मिलेगी प्रैक्टिस की अनुमति

2023 में होगी देश की पहली एक्जिट परीक्षा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले भी इसी के आधार पर होंगे

एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए पहली एक्जिट परीक्षा 2023 में होगी और इसका माक रन 2022 में होगा। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई कर आने वाले छात्रों के लिए भारत में प्रैक्टिस करने की खातिर इस परीक्षा को पास करना होगा। इसके साथ ही मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में नामांकन इसी के आधार पर होगा।

शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नेशनल मेडिकल कमीशन के काम-काज की समीक्षा की और एक्जिट परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक्जिट परीक्षा को नेशनल एक्जिट टेस्ट नाम दिया गया है। यह पूरे देश में सभी मेडिकल कालेजों के एमबीबीएस छात्रों को देना होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद एमबीबीएस के छात्रों को पांच साल का कोर्स पूरा करने के बाद अंतिम परीक्षा नहीं देनी होगी और एक्जिट परीक्षा को ही उनकी अंतिम वर्ष की परीक्षा मान ली जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सभी एमबीबीएस छात्रों के लिए एक एक्जिट परीक्षा की व्यवस्था से पूरे देश में डाक्टरों की समान गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में नामांकन का आधार इसे बना दिए जाने से इसके लिए अलग से परीक्षा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से विदेश से एमबीबीएस करके आने वालों के लिए अलग से होने वाली परीक्षा भी खत्म हो जाएगी। यहां तक कि केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डाक्टरों का चयन भी इसी के आधार पर कर लिया जाएगा। अभी इन सबके लिए अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन के गठन के लिए संसद से पारित कानून में ही एक्जिट परीक्षा का प्रविधान कर दिया गया था। नेशनल मेडिकल कमीशन के गठन के बाद ही इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। कमीशन के अधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री को एक्जिट परीक्षा की तैयारियों का ब्योरा पेश किया। मनसुख मांडविया ने उन्हें असली परीक्षा शुरू होने के पहले माक रन करने की सलाह दी, ताकि पहली बार परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।


स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नेशनल मेडिकल कमीशन के काम-काज की समीक्षा की। फाइल

स्वतंत्रता दिवस के भाषण के लिए मोदी ने मांगे जनता से सुझाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने दिए जाने वाले भाषण के लिए देश की जनता से विषयों का चुनाव करने की अपील की है। उनका कहना है कि वह लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में आम जनता के मनोभावों को ही सबके सामने रखना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को एक ट्वीट करके बताया कि भारत सरकार के पोर्टल 'मायगाव' पर लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मोदी इनमें से कुछ चुनिंदा विचारों और सुझावों को अपने भाषण में शामिल कर सकते हैं।

पीएम पिछले कई सालों से स्वतंत्रता दिवस पर अपने सम्भाषण के लिए जनता से अपने सुझाव मांगते हैं और हर साल उसी आधार पर सरकार की योजनाओं, नीतियों और जनभावनाओं को देश-दुनिया के सामने रखते हैं।

कह के रहेंगे माधव जोशी



www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 31 जुलाई, 2021

संघ के प्रचारक को गिरफ्तार करने का प्रस्ताव किया पारित

जागरण संवाददाता, जयपुरः जयपुर नगर निगम (ग्रेटर) में सफाई का काम करने वाली बीवीजी कंपनी से जुड़े रिश्वत कांड में राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच का सामना कर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन की मौजूदगी में आयोजित बैठक में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एक प्रस्ताव पारित कर निंबाराम को गिरफ्तार करने की मांग की।

शुक्रवार को आयोजित बैठक में विधायक रामलाल जाट ने इससे संबंधित प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दो रिश्तेदारों का राज्य प्रशासनिक सेवा में चयन होने को लेकर उठ रहे सवालों पर पार्टी ने उनका बचाव करते हुए भाजपा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। पार्टी नेताओं ने कहा कि रिश्तेदारों के चयन में डोटासरा का कोई सरोकार नहीं है। उधर, कांग्रेस द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस के नेता असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। कटारिया ने कहा कि मामले की जांच एसीबी कर रही है। कोई भी दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई का अधिकार कांग्रेस को नहीं, जांच एजेंसी को है। कांग्रेस को एसीबी के काम में दखल करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का दुरुपयोग हुआ तो भाजपा सड़क पर उतरेगी।

गौरतलब है कि बीवीजी कंपनी के 276 करोड़ रुपये के बिल का भुगतान करने के बदले निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम पर 20 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। कंपनी के दो प्रतिनिधियों के साथ राजाराम की बैठक हुई, जिसका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें निंबाराम भी दिखाई दे रहे थे। वीडियो में रिश्वत को लेकर बातचीत हो रही थी। एसीबी ने मामला दर्ज कर कंपनी के एक प्रतिनिधि और राजाराम को गिरफ्तार कर लिया है ।

जातीय जनगणना को पीएम को पत्र लिखेंगे नीतीश

तेजस्वी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में बिहार के सीएम ने दिया भरोसा

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराने के आग्रह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलने का भी समय मांगेंगे। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ गए विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने शुक्रवार को यह भरोसा दिया है। विपक्षी नेताओं से उनकी मुलाकात विधानसभा स्थित कक्ष में हुई।

मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने पत्रकारों को बताया कि विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र भी दिया। पत्र पर तेजस्वी के अलावा कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा, भाकपा (माले) विधायक दल के नेता महबूब आलम, भाकपा विधायक दल के नेता रामरतन सिंह और माकपा विधायक दल



जाति आधारित जनगणना को लेकर शुक्रवार को पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। एएनआइ

के नेता अजय कुमार के दस्तखत हैं। पत्र में कहा गया है कि 2021 की प्रस्तावित जनगणना में पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्गों की गणना का प्रस्ताव शामिल नहीं है। अगर यह नहीं होता है तो पिछड़े-अति पिछड़े हिंदुओं की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति का आकलन नहीं हो पाएगा। लिहाजा इन वर्गों के विकास के लिए नीतियां नहीं निर्धारित हो पाएंगी। यह उचित होगा कि राज्य के दलीय नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिले। उनसे जातीय जनगणना का अनुरोध करे। पत्र में सलाह दी गई है कि अगर केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं होती है तो राज्य सरकार अपने संसाधन से जातीय जनगणना कराए, ताकि राज्य की पूरी आबादी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता चल सके।

तेजस्वी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिद्धांत रूप में इस प्रस्ताव से सहमत हुए हैं। उन्होंने कर्नाटक से इससे संबंधित दस्तावेज मंगाने का भी भरोसा दिया है।

कर्नाटक में राज्य सरकार अपने संसाधन से जातीय जनगणना करा रही है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा से दो बार सर्वसम्मति प्रस्ताव के जरिये केंद्र से जातीय जनगणना कराने की मांग की जा चुकी है। जदयू भी इसके पक्ष में है।

जदयू को आज मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, पटना

▸ पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया जा सकता है फैसला

दिल्ली के जंतर-मंतर स्थित जदयू के राष्ट्रीय कार्यालय में शनिवार को होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहला एजेंडा पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। इसके अलावा भाजपा के इन्कार के बाद जाति आधारित जनगणना पर आगे बढ़ने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इस मसले पर बिहार में नीतीश कुमार द्वारा तैयार की गई पिच पर तेजस्वी यादव की बैटिंग भी एक प्लाट के रूप में है। महाराष्ट्र से भी जाति आधारित जनगणना कराए जाने की बात मुखर हुई है।

चर्चा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह खुद अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। कहा जा रहा कि आरंभ में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तारीख तय हुई, तभी उन्हें संदेश चला गया था कि पार्टी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत से इधर-उधर नहीं जाएगी। कहा जा रहा कि जदयू लोकसभा में अपने संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंप सकती है। वह नीतीश कुमार के करीबी होने के साथ चुनाव प्रबंधन में महारत रखते हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद किसी अति पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग के सांसद को लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता का पद सौंपे जाने का भी राजनीतिक निहितार्थ तलाशा जा रहा। उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी चर्चा में है। बशिष्ठ नारायण सिंह का नाम भी चर्चा में है। यह भी कहा जा रहा कि नीतीश कुमार कार्यकारी व्यवस्था के तहत फिलहाल खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान अपने हाथ ले सकते हैं। वैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता इससे इन्कार कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाति आधारित जनगणना कराए जाने का भी प्रस्ताव लाया जाएगा।

'स्कालरशिप घोटाले के दाग धोने को उठाने होंगे कड़े कदम'

आक्रोश ▸ बैठक में सिद्धू के सामने दलित विधायकों ने रखी बात

मंत्रिमंडल में छह की जगह तीन ही मंत्री बनाए जाने पर जताई नाराजगी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप घोटाला कांग्रेस के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दलित विधायकों व चार जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसमें भी यह मुद्दा जोर-शोर से उठा। बैठक में कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी, विधायक डा. राजकुमार वेरका और कुलदीप वैद ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस मामले से पंजाब में कांग्रेस की बदनामी हो रही है। विधायकों ने कहा कि घोटाले के दाग धोने के लिए पार्टी को कड़े कदम उठाने चाहिए। सिद्धू के साथ विधायकों की बैठक 30 मिनट में ही खत्म हो गई। इससे कई विधायक नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें बैठक में बोलने का मौका नहीं मिला। यह देखते हुए सिद्धू ने मंगलवार को दोबारा विधायकों की बैठक बुला ली है।

बैठक अपने तय समय से करीब डेढ़ घंटे देर से शुरू हुई। अभी तीन वक्ता ही



चंडीगढ़ में बैठक के दौरान पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के समक्ष अपनी बात रखतीं कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी। जागरण

बोल पाए थे कि सिद्धू ने जल्दी बैठक खत्म करने के लिए सभी को एक-एक मिनट में अपनी बात रखने के लिए कहा। इस पर विधायकों ने आपत्ति जताई। विधायकों ने कहा कि अगर एक मिनट ही मौका मिलना था, तो बैठक करने की कोई वजह नहीं बनती।

विधायकों ने दलितों के मुद्दे पर अपनी ही सरकार की ओर से की जा रह अनदेखी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 34 फीसद आबादी के हिसाब से मंत्रिमंडल में छह मंत्री होने चाहिए, लेकिन सिर्फ तीन ही बनाए गए, जबकि सरकार का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। उन्होंने मांग उठाई कि जिन जिलों में दलितों और पिछड़ों की आबादी अधिक है, वहां दलित अफसरों को डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी नियुक्त किया जाए। बैठक में 85वें संविधान संशोधन और बोर्ड-कारपोरेशन के चेयरमैन की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई।

मोहाली, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और मालेरकोटला जिले की हुई बैठक में वर्करों का गुस्सा भी फूटा। वर्करों ने खुल कर कहा कि सरकार तो कांग्रेस की आ गई, लेकिन उन्हें नजरंदाज कर दिया गया। साढ़े चार साल में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वर्करों के दम पर सरकार बनी, लेकिन बाद में उन्हें मान-सम्मान नहीं दिया गया। साढ़े चार वर्षों में इस तरह की कोई बैठक नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने वर्करों को भरोसा दिलाया कि उनका बनता मान-सम्मान उन्हें दिलवाया जाएगा।

राजनीतिक जासूसी के लगे हैं कई बार आरोप, नहीं मिले सुबूत

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

पेगासस जासूसी मामले को लेकर देशभर में जारी बहस के बीच पूर्व नौकरशाहों ने रेखांकित किया कि देश में अधिकृत तरीके से फोन टैपिंग की अनुमति है, लेकिन नेताओं पर जासूसी करने का कोई आरोप बंगाल में अब तक साबित नहीं हुआ है। राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) व मुख्य सचिव ने सहमति जताई कि राज्य में समय-समय पर राजनीतिक जासूसी के आरोप लगते रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कई मौकों पर दावा किया कि उनके फोन टैप किए जा रहे थे। पूर्व अधिकारियों ने कहा कि इनमें से कोई भी मामला अब तक तार्किक अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है।

बंगाल के पूर्व डीजीपी भूपिंदर सिंह ने कहा कि अपराधियों और संदिग्ध आतंकियों की निगरानी करने के लिए फोन टैपिंग करना एक सामान्य घटना है, लेकिन नेताओं की जासूसी एक जटिल मामला है। इस तरह के आरोपों को साबित करने के लिए अब तक सुबूत नहीं मिले हैं। सिंह ने 2009-2010 में माओवादी उग्रवाद के चरम दिनों में पुलिस बल का नेतृत्व किया था। सिंह ने कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान, हम आमतौर पर अपराधियों, माओवादी नेताओं और संदिग्ध आतंकियों के टेलीफोन या मोबाइल फोन टैप करते थे। प्रक्रिया के लिए निर्धारित दिशा-निर्देश हैं। राज्य स्तर पर गृह सचिव से लिखित

फोन टैपिंग पर राज्य सरकार सफाई दे : भाजपा

उधर, भाजपा की बंगाल इकाई के मुख्य प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि मुकुल रॉय ने 2017 में भाजपा में शामिल होने के बाद आरोप लगाया था कि उनके फोन टैप किए गए। राज्य सरकार को सबसे पहले इस बात पर सफाई देनी चाहिए कि क्या कोई पुलिस आयुक्त कभी जासूसी उपकरण खरीदने के लिए इजराइल गया था?

सहमति लेने के बाद फोन टैपिंग की जाती है। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अर्धेंदु सेन ने भी नेताओं के फोन टैपिंग के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि यह तभी संभव है, जब कोई गृह सचिव अपने कर्तव्य में लापरवाही करे। उन्होंने कहा कि यह सच है कि ममता बनर्जी ने अक्सर आरोप लगाया कि वाम मोर्चे के शासन के दौरान उनका फोन टैप किया गया था, लेकिन यह भी सच है कि पिछले दस वर्षों में वह इस मामले में कोई सुबूत पेश नहीं कर सकीं।

नेताओं के फोन टैप करना अवैध है : कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त गौतम मोहन चक्रवर्ती ने कहा कि कोई भी राजनीतिक जासूसी के आरोपों पर प्रकाश नहीं डाल पाएगा, क्योंकि नेताओं के फोन टैप करना अवैध है। उन्होंने कहा, जो वैध है, मैं उसपर टिप्पणी कर सकता हूं।

दो से अधिक बच्चे होने पर नगर पंचायत अध्यक्ष की गई कुर्सी

जासं, ऊधमसिंह नगर : उत्तराखंड में दो से अधिक बच्चे होने पर केलाखेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष हामिद अली को पद से हटा दिया गया। नए अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने तक जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने एसडीएम बाजपुर को प्रशासक नियुक्त किया है। प्रदेश का इस तरह का दूसरा मामला है। इससे पहले हरिद्वार की लक्सर नगर पालिका के वार्ड-चार की सभासद नीता पांचाल को तीसरी संतान होने पर पद से हटा दिया गया था।

नवंबर 2018 में हुए केलाखेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हामिद अली के साथ अकरम खां भी मैदान में थे। प्रतिद्वंद्वी अकरम ने नामांकन के दौरान आपत्ति जताई थी कि हामिद के तीन बच्चे हैं। सभी का जन्म अप्रैल 2003 के बाद हुआ है। उन्होंने घोषणापत्र में बच्चों के संबंध में गलत सूचना दी है। नियम के तहत अप्रैल, 2003 के बाद दो से अधिक संतान होने पर पंचायत चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इसके बाद भी हामिद चुनाव जीत गए। उनके खिलाफ अकरम ने प्रथम अपर जिला न्यायाधीश रुद्रपुर की अदालत में याचिका दायर की। अदालत ने 22 जुलाई को हामिद को अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। मामले से जिला प्रशासन ने शासन को अवगत कराया। शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन ने भी हामिद को अयोग्य घोषित कर अध्यक्ष पद रिक्त कर दिया।

गुजरात में होने वाले कार्यक्रमों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

▸ रूपाणी सरकार के पांच वर्ष पूरे होने पर होने हैं कार्यक्रम

▸ कांग्रेस ने पूछा, शादी कार्यक्रम में 150 तो राजनीतिक कार्यक्रम में 400 को अनुमति क्यों

गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सरकार के पांच साल पूरे होने वाले कार्यक्रमों को लेकर राजनीति गरमा गई है। सरकार व भाजपा संगठन उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर नेता विपक्ष परेश धनाणी ने कोरोना की नई गाइडलाइन को दोषपूर्ण बताया है जिसमें विवाह कार्यक्रम में 150 लोगों को, तो सामाजिक व राजनतिक कार्यक्रमों में 400 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है।

कांग्रेस ने सरकार पर भाजपा कार्यालय से आने वाले निर्देशों को लागू करने का आरोप लगाया तो प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता यमल व्यास ने उस पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी को लेकर गुजरात सरकार ने नई गाइडलाइन घोषित की है जो 31 जुलाई से लागू होगी। इसमें रात्रि कर्फ्यू रात 10 के स्थान पर 11 बजे से सुबह छह तक कर दिया गया है। सरकार ने सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रमों में 400 लोगों के शामिल होने की भी छूट दी है।

नई गाइडलाइन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावडा ने सरकार पर हमला बोला और कहा है कि विवाह में अगर 150 लोगों के शामिल होने की मंजूरी दी है तो राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रमों में 400 लोगों की छूट क्यों दी गई। बता दें कि रूपाणी सरकार के पांच साल पूरे होने पर सरकार व भाजपा एक से नौ अगस्त तक राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, सांसद तथा भाजपा विधायक भाग लेंगे। कांग्रेस ने सरकार व भाजपा के इन कार्यक्रमों के खिलाफ एक से नौ अगस्त के दौरान विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमों का एलान किया है।

सुवेंदु ने दूसरे राज्यों के विस अध्यक्षों व विरोधी दल के नेताओं को लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

नंदीग्राम से भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में लौटे मुकुल रॉय को लेकर फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुकुल को विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर दूसरे राज्यों के विस अध्यक्षों, उपाध्यक्षों व विरोधी दल के नेताओं को पत्र लिखा है।

सुवेंदु की ओर से पत्र लिखने को सियासी विश्लेषक बंगाल की ममता सरकार पर राजनीतिक व मानसिक दबाव बनाने की रणनीति मान रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि यह पत्र उन्हीं राज्यों के विस अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और विरोधी दल के नेताओं को भेजा गया है, जहां भाजपा की सरकार है। दूसरी तरफ मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता दलबदल विरोधी कानून के तहत रद करने के मामले पर

सरकार की ओर से दी गई यह दलील

राज्य सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने कहा कि पीएसी के अध्यक्ष पद पर सत्तारूढ़ दल के किसी विधायक की नियुवित नहीं की गई है। इस र विरोधी दल के विधायक को ही नियुक्त किया गया है, जिन्होंने दलबदल किया है। उस मामले की विस में सुनवाई चल रही है। विस की किस कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा, यह निर्णय लेने का अधिकार संपूर्ण तौर पर विस अध्यक्ष को है।

शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के समक्ष सुनवाई हुई। इसमें सुवेंदु अधिकारी मौजूद थे, लेकिन मुकुल शामिल नहीं हुए। विस अध्यक्ष के समक्ष अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। उधर, विधानसभा में पीएसी के मुद्दे पर सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री ही नहींएबल्कि दुनिया के सर्वशक्तिमान नेता भी हैं।

हाई कोर्ट ने पूछा-पीएसी मामले को जनहित याचिका के तौर पर क्यों दायर किया गया? : इस मामले में शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में भी सुनवाई हुई। भाजपा विधायक अंबिका राय की ओर से मुकुल रॉय की पीएसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है।

खंडपीठ ने याचिका दायर करने वाले से सवाल किया कि इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर क्यों दायर किया गया है? इस बाबत चार अगस्त तक विस्तार से जवाब देने को कहा गया है। उसके बाद ही तय किया जाएगा कि इसे जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार किया जाए अथवा नहीं।

विधायकों के साथ आई कांग्रेस, बढ़ेगी पुलिस की परेशानी

राज्य ब्यूरो, रांची

▸ झारखंड के विधायकों से पूछताछ में देरी कर रही राज्य पुलिस, महाराष्ट्र के नेताओं के लिए नोटिस तैयार

झारखंड में विधायकों की खरीद-फरोख्त और सरकार को गिराने की साजिश में कांग्रेस विधायकों का नाम आने के बाद शुरू में भले ही कांग्रेस ने मामले की जांच कराई, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस संगठन अपने विधायकों के साथ खड़ा हो गया है। पार्टी किसी भी तरह से मामले को तूल देने से बचने के मूड में आ गई है। बात चंद विधायकों के साजिश में शामिल होने से अलग होकर पूरी कांग्रेस पार्टी पर आ गई है। केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेजने के बाद प्रदेश कांग्रेस इस मामले को अब ठंडे बस्ते में डालना चाहती है।

बता दें कि इससे सर्वाधिक परेशानी पुलिस को होगी। पुलिस के पास दिल्ली और रांची एयरपोर्ट के सीसीटीवी के फुटेज हैं, जिनसे इस मामले में विधायकों की संलिप्तता साबित हो रही हे। इसके बावजूद पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। दूसरी ओर, मुंबई के भाजपा नेताओं को नोटिस देने के मामले पर वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश प्राप्त हो गया है, लेकिन अभी उन्हें नोटिस नहीं भेजा गया है। झारखंड के विधायकों को लेकर अभी तक पुलिस ने कोई तैयारी नहीं की है। माना जा रहा है कि पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश का इंतजार कर रही है।

विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में कांग्रेस विधायकों पर आरोप लग रहा है और प्रमाण भी मिलने लगे हैं, लेकिन पार्टी अब इस मामले को तूल देकर अपनी ही फजीहत नहीं करवाना चाहती है। सभी दागी विधायकों से प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने बात की और अन्य कांग्रेस विधायकों से भी राय ली गई। सबने पूरे प्रकरण को कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश करार दिया। विधायकों से बातचीत में यह बात भी सामने आई कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम नहीं होने से निचले स्तर तक नाराजगी पहुंच चुकी है।

सियासत

ओमप्रकाश चौटाला और सुखबीर सिंह बादल अपने-अपने ढंग से कर रहे तीसरे मोर्चे के गठन के प्रयास

आसान नहीं तीसरे मोर्चे के गठन की राह, नेतृत्व पर रहेगी रार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला ने भले ही तीसरे मोर्चे के गठन के प्रयास तेज कर दिए, लेकिन तीसरे मोर्चे के गठन की राह इतनी आसान नहीं है। तीसरे मोर्चे में कांग्रेस को शामिल करने अथवा नहीं करने को लेकर सबसे बड़ा असमंजस रहने की संभावना है। हालांकि, चौटाला ने कांग्रेस के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा है। मोर्चा अगर बन भी गया तो इसके नेतृत्व को लेकर मोर्चे के नेताओं में आपसी जंग छिड़ना तय है।

जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में 10 साल की सजा पूरी कर लौटे इनेलो प्रमुख ने आते ही तीसरे मोर्चे की नींव डालने के प्रयास आरंभ कर दिए थे। पिछले दिनों उनके गुरुग्राम आवास पर जनता दल (यू) के महासचिव केसी त्यागी ने मुलाकात की। दोनों के बीच करीब दो घंटे तक लंबी मंत्रणा हुई और भोजन भी एकसाथ किया। त्यागी से हुई इस मुलाकात के बाद चौटाला ने तीसरे मोर्चे के गठन के अपने प्रयासों को एक प्रेस कान्फ्रेंस के जरिये जग जाहिर कर दिया।

ऐसे ही प्रयास पंजाब में शिरोमणि अकाली



प्रकाश सिंह बादल। जागरण आर्काइव



ओमप्रकाश चौटाला। जागरण आर्काइव

दल (बादल) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल कर रहे हैं। सुखबीर बादल ने तीसरे मोर्चे के गठन को सिरे चढ़ाने के लिए करीब आधा दर्जन नेताओं से मुलाकात का दावा किया है। हालांकि बड़े बादल और चौटाला के बीच पुरानी दोस्ती है, लेकिन 94 वर्षीय प्रकाश सिंह बादल पिछले काफी समय से सक्रिय राजनीति में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसके बावजूद 87 वर्षीय ओमप्रकाश चौटाला को उम्मीद है कि तीसरे मोर्चे के गठन पर प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर बादल साथ हैं। इनेलो प्रमुख की एक अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात होने वाली है। केसी त्यागी इस मुलाकात के सूत्रधार हैं। त्यागी जब चौटाला के गुरुग्राम आवास पर मिलने आए थे, तब उन्होंने नीतीश की चौटाला से बात भी कराई थी। उसी बातचीत के दौरान नीतीश ने चौटाला के साथ लंच करने का न्यौता स्वीकार कर लिया था। अब दोनों दिग्गजों की इस मुलाकात पर तीसरे मोर्चे के प्रारूप का भविष्य निर्भर है।

चौटाला बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी अच्छे संबंध बताते हैं। ऐसे ही संबंध भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी होने का दावा करते हैं। केजरीवाल और ममता बनर्जी की दो दिन पहले ही दिल्ली में मुलाकात हुई है। चौटाला और बादल परिवार में भले ही पारिवारिक व राजनीतिक रिश्ते हैं, लेकिन जब श्रेय लेने की बात आएगी तो सुखबीर बादल नहीं चाहेंगे कि इसका पूरा श्रेय ओमप्रकाश चौटाला को मिले।

शरद यादव पर स्थिति साफ नहीं: चौटाला व बादल परिवार के रिश्ते नीतीश कुमार के साथ-साथ चंद्रबाबू नायडू के साथ भी हैं। शरद पवार की इच्छा तीसरे मोर्चे के गठन की है। शरद यादव को लेकर किसी ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। हालांकि चौटाला ने कांग्रेस को तीसरे मोर्चे में शामिल होने का न्योता दिया है। तीसरे मोर्चे का मतलब भाजपा व कांग्रेस के विरुद्ध मोर्चेबंदी है, लेकिन जैसे दावे किए जा रहे हैं कि यदि कांग्रेस को तीसरे मोर्चे के किसी नेता का नेतृत्व स्वीकार होगा तो वह इसमें शामिल हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या राहुल गांधी कोई अन्य नेतृत्व स्वीकार करेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है।

सपा-बसपा के बीच राजनीतिक दूरियां मिटाना मुश्किल

बसपा अध्यक्ष मायावती व उप्र के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव तथा उनके बेटे अखिलेश यादव हालांकि तीसरे मोर्चे के हक में हैं, लेकिन जैसे बसपा और सपा के बीच राजनीतिक दूरियां बनी हुई हैं, उन्हें मायावती और अखिलेश यादव स्वीकार कर भी पाते हैं या नहीं, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। भाजपा के विरुद्ध बनने वाले संभावित तीसरे मोर्चे की राह इतनी आसान दिखाई नहीं दे रही है, जितना कि दावा किया जा रहा है।

मंत्रियों पर भड़के पार्टी पदाधिकारी

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमों के बीच चल रहे सियासी संग्राम को खत्म कराने आए माकन ने दो दिन तक विधायकों के साथ वन-टू-वन संवाद किया । शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों से सरकार को लेकर फीडबैक लिया । इस दौरान कई पदाधिकारी भी मंत्रियों पर भड़क गए। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान दवाओं की कालाबाजारी हो रही थी तो मैंने चिकित्सा मंत्री को 10 बार फोन किया, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। प्रदेश महासचिव वेदप्रकाश सोलंकी, सचिव शोभा सोलंकी, मांगीलाल गरासिया और महेंद्र गुर्जर ने कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए । विधायकों और पदाधिकारियों ने माकन से यहां तक कह दिया कि अगर खराब छवि वाले मंत्रियों को नहीं हटाया गया तो पार्टी की छवि को नुकसान होगा और जनता के बीच जाना मुश्किल होगा ।

हारे प्रत्याशियों से चर्चा नहीं किए जाने पर भी नाराजगी : पार्टी के पदाधिकारियों ने करीब 100 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में हारे प्रत्याशियों से चर्चा नहीं करने पर भी माकन के समक्ष नाराजगी जताई । उन्होंने कहा कि जिन निर्दलियों ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराया उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। पदाधिकारियों की नाराजगी बढ़ती देख माकन ने हस्तक्षेप कर 2023 के चुनाव में फिर सत्ता में आने के लिए एकजुट करने का आह्वान किया ।

गहलोत बोले-पुरानी बातें भूल जाओ और माफ करो : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को विधायकों को रात्रि भोज दिया था और शुक्रवार को पार्टी के पदाधिकारियों को लंच दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुरानी बातें भूल जाओ और माफ करो । मैं पहले भी आपका अभिभावक था और आगे भी रहूंगा । उधर, माकन ने प्रदेश कांग्रेस के एक साल के कामकाज की बुकलेट जारी की, जिसे सीएम ने सराहा ।

34 कंपनियों ने तोड़े इंटरनेट लाइसेंस नियम। इन कंपनियों पर अन्य कंपनियों को इंटरनेट सेवाओं की दोबारा बिक्री का आरोप है। दूरसंचार राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान ने यह जानकारी दी।

न्यूज गैलरी

बारामुला में ग्रेनेड हमला, चार जवान घायल

श्रीनगर : बारामुला में शुक्रवार दोपहर को ग्रेनेड हमले में चार सीआरपीएफ जवानों सहित पांच लोग जख्मी हो गए। हमले की जिम्मेदारी लश्कर के हिट स्क्वाड कहे जाने वाले आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने ली है। सुरक्षाबलों ने हमले में लिप्त आतंकियों की धरपकड़ के लिए इलाके की घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चला रखा है। (राब्यू)

केदारनाथ-पंचकेदार मंदिर के संरक्षण को बनेगी समिति

देहरादून : उत्तराखंड में केदारनाथ और पंचकेदार मंदिर समूहों के संरक्षण के लिए 'पंचकेदार सेक्रेड लैंड स्केप समिति' का गठन किया जाएगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में पूर्व राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजय भी मौजूद थे। (राब्यू)

जहां मौका मिलेगा फहराऊंगा तिरंगा : जयराम

धर्मशाला : खालिस्तान समर्थक की धमकी पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को जहां भी मौका मिलेगा, तिरंगा फहराएंगे। डरने की कोई बात नहीं है। किसी संगठन या व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, इसकी जानकारी नहीं है। सच्चाई क्या है, यह बारीकी से जांच का विषय है। (जासं)

महाकाल मंदिर में शनि, रवि व सोमवार को नई व्यवस्था

उज्जैन: मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में प्रशासन ने शनिवार, रविवार व सोमवार के लिए नई दर्शन व्यवस्था लागू की है। इसके तहत मंदिर में प्रवेश के रास्तों को बदला गया है। (नईदुनिया)

सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना वसूलने का दिया आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) दीपक मिश्रा की नियुक्ति को 2017 में चुनौती देने वाली याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता से पांच लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया जाए। स्वामी ओम (अब दिवंगत) और मुकेश जैन ने 2017 में वर्तमान प्रधान न्यायाधीश द्वारा अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने की परंपरा पर सवाल उठाया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने जैन की ओर से दाखिल जुर्माना घटाने की याचिका पर संज्ञान लिया और कहा कि उन्होंने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के खिलाफ फिर कुछ निराधार आरोप लगाए हैं। (प्रेट्र)

फिर निजी पर भारी पड़े सरकारी स्कूल

केंद्रीय विद्यालय व केंद्रीय तिब्बती स्कूलों का सौ फीसद रहा परिणाम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा जारी 12वीं के परिणामों में सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन अच्छा रहा। केंद्रीय विद्यालय व केंद्रीय तिब्बती स्कूलों का परिणाम सौ फीसद रहा है, जबकि जवाहर नवोदय विद्यालय, सरकारी विद्यालय व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के परिणामों का फीसद क्रमशः 99.94, 99.72 और 99.48 रहा है। वहीं निजी स्कूलों के छात्रों का परिणाम 99.22 फीसद रहा है। गत वर्ष भी सरकारी स्कूलों का परिणाम निजी स्कूलों से अच्छा रहा था। पिछले वर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय का परीक्षा परिणाम सबसे ज्यादा 98.70 फीसद रहा था। केंद्रीय विद्यालय 98.62 फीसद व केंद्रीय तिब्बती स्कूलों का 98.23 फीसद था। सरकारी विद्यालय का 94.94 फीसद जबकि निजी विद्यालयों का 88.22 फीसद रहा था।

जोनवार पास फीसद	
त्रिवेंद्रम	99.89
पश्चिमी दिल्ली	99.84
पूर्वी दिल्ली	99.84
बेंगलुरू	99.83
चेन्नई	99.77
भुवनेश्वर	99.55
पंचकुला	99.54
चंडीगढ़	99.47
पुणे	99.35
भोपाल	99.34
गुवाहाटी	99.31
अजमेर	99.29
नोएडा	99.02
पटना	98.91
देहरादून	98.64
प्रयागराज	98.59



छात्राओं ने फिर बाजी मारी...बारहवीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद कुछ इस तरह खुशी का इजहार करती छात्राएं • ध्रुव कुमार

पास फीसद और रैंकिंग में दिल्ली ने मारी छलांग

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली ने पास फीसद और रैंकिंग दोनों में छलांग मारी है। पिछले साल की तुलना में दिल्ली के परीक्षा परिणाम में पांच फीसद से ज्यादा का उछाल आया है। इस बार पश्चिमी और पूर्वी दिल्ली जोन का पास फीसद 99.84 फीसद है। जबकि पिछले साल पश्चिमी दिल्ली जोन का पास फीसद 94.61 और पूर्वी दिल्ली जोन का 94.24 फीसद था। पश्चिमी जोन के परीक्षा परिणाम में 5.23 और पूर्वी जोन के में 5.6 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।

14,30,188 कुल पंजीकृत छात्र
13,69,745 कुल रेगुलर छात्र
13,69,745 इतने छात्रों का परिणाम जारी हुआ
12,96,318 पास हुए
60,443 प्राइवेट और पत्राचार छात्र
65,184 परिणाम अभी जारी होना है
99.37 % पास हुए

लड़कियों और लड़कों का परिणाम
99.67% लड़कियां
99.13% लड़के

1,50,152 छात्रों को मिले 90 फीसद से अधिक अंक
70,004 छात्रों को मिले 95 फीसद से ज्यादा अंक

देशभर में ऐसा रहा प्रदर्शन	
केंद्रीय विद्यालय	100
केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	100
जवाहर नवोदय विद्यालय	99.94
सरकारी स्कूल	99.72
सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल	99.48
निजी स्कूल	99.22

नोट- परिणाम फीसद में

विशेष अधिकार वालों का पास %	
साल 2021	99.59
साल 2020	94.43
साल 2019	95.99

ट्रांसजेंडर का पास फीसद	
साल 2021	100
साल 2020	78.95
साल 2019	94.97

कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम

साल	कुल छात्र	परिणाम(%)
2021	6,149	0.47
2020	1,50,198	7.88
2019	1,138,705	8.02

प्राइवेट व पत्राचार के छात्रों की होगी परीक्षा

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

बोर्ड ने प्राइवेट और पत्राचार के छात्रों का परिणाम नहीं जारी किया है। इनकी आफलाइन परीक्षा होगी। देशभर में कुल 60,443 छात्र प्राइवेट और पत्राचार के हैं। इनकी परीक्षा भी 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होगी।

योग्य छात्रों के काटने पड़े अंक : रिवर्स माडरेशन की वजह से कई योग्य छात्रों के अंक काटने पड़े। दिल्ली के एक स्कूल की प्रिंसिपल नीता अरोड़ा ने कहा कि ऐसे मेधावी छात्रों को नुकसान हुआ, जो सभी विषयों में 100 फीसद लक्ष्य कर रहे थे। उन्होंने 10वीं और 11वीं में समान सफलता हासिल की, लेकिन 12वीं का परिणाम उनके अपने प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि संदर्भ साल (रेफरेंस ईयर) के टापर के प्रदर्शन पर आधारित था।

हिमाचल में सड़क पर टूटा पहाड़

आफत ▶ सिरमौर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा, 150 मीटर हिस्सा ध्वस्त

जागरण संवाददाता, धर्मशाला

हिमाचल के सिरमौर जिले में पांवटा साहिब-शिलाई-हाटकोटी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरा पहाड़ दरक गया। कमराऊ के नजदीक बड़वास में सड़क का डेढ़ सौ मीटर का हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे भूस्खलन हुआ। हालांकि मार्ग पर हल्की दरारें दिखने के बाद दोनों किनारों पर लोगों ने वाहन रोक दिए थे, जिससे जानी नुकसान होने से बच गया, लेकिन मार्ग के दोनों तरफ पांच घंटे तक हजारों लोग फंसे रहे। इसके बाद, जिला प्रशासन ने दूसरे रास्ते से ट्रैफिक को डायवर्ट किया।

पांवटा साहिब-शिलाई-हाटकोटी राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन दिनों सड़क को चौड़ा करने का काम चल रहा है। पहाड़ी की कटिंग के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह मलबा गिर रहा है। इस मार्ग को बहाल करने में काफी समय लग सकता है, क्योंकि अब भी यहां भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन के बाद उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पांवटा साहिब व शिलाई के अधिकारियों से स्थिति का जायजा लिया। सतौन से कमराऊ व शिलाई-हाटकोटी की तरफ जाने के लिए पांवटा साहिब से वैकल्पिक मार्ग कफोटा-वाया जाखना जोंग-किलौर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उपायुक्त ने पुलिस को भूस्खलन की जगह दोनों तरफ 200-200 मीटर पहले बैरिकेड लगाने का कहा है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। मंडी जिले में मनाली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सात मील में भूस्खलन से यातायात बाधित हो गया है। वैकल्पिक मार्ग मंडी-कमांद-बजौरा पर भी कटौला में पेड़ गिरे हैं। इससे सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। किसान की मुश्किल बढ़ गई है।



हिमाचल प्रदेश में मूसलधार बारिश और भूस्खलन की वजह से भारी क्षति हुई है। शुक्रवार को मंडी में कार पार्किंग की शेड पर एक दीवार गिर गई। इससे नीचे खड़ी कई गाड़ियां दब गईं। एएनआइ

पहाड़ी से गिरे पत्थर लगने से जेसीबी खाई में गिरी, एक की मौत : चंबा जिले के तीसा उपमंडल के तहत चांजू-टिकरीगढ़ मार्ग पर कठवाड घार के समीप पहाड़ी से गिरे पत्थर लगने से जेसीबी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 50 वर्षीय केशव राम की मौत हो गई। जेसीबी मारे गए व्यक्ति का बेटा विशाल चला रहा था। पत्थर लगने से जैसे ही जेसीबी सड़क किनारे पहुंची तो बेटे ने छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली।

आखिरी उम्मीद तक तलाशेंगे जिंदगी के निशां

जासं, किश्तवाड़ : जम्मू में हंजर हादसे को हुए तीसरा दिन भी बीत गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और खोजी कुत्तों की टीमें, पुलिस, प्रशासनिक अमला और स्थानीय लोग बादल फटने से लापता 19 जिंदगियों की तलाश में जुटे रहे। जहां उम्मीद की एक भी किरण बाकी थी, लेकिन हाथ सिर्फ मायूसी ही आई। शनिवार सुबह फिर जिंदगी की निशां तलाशे जाएंगे।

लाहुल के घेपन झील ट्रैक से तीन पर्यटक लापता

मनाली, जासं : लाहुल घाटी के घेपन झील ट्रैक से तीन पर्यटक लापता हो गए हैं। ये सिस्सू के निजी होटल में ठहरे थे। 27 जुलाई को सिस्सू से घेपन झील की ओर रवाना हुए थे। इन्होंने 29 को लौटना था। पुलिस के अनुसार, निकुंज जयसवाल पुत्र धन प्रकाश जायसवाल, आरओबी 24 लिग्निट शक्तिनगर बीकानेर (राजस्थान) दो दोस्तों के साथ घेपन झील ट्रैक पर गए थे।

नालों पर सीढ़ी और झूला पुल से रेस्क्यू किए 73 लोग

जागरण संवाददाता, मंडी

बादल फटने से बाढ़ का दंश झेलने वाले लाहुल-स्पीति जिले में राहत व बचाव कार्य तेजी आई है। नालों पर सीढ़ी व झूला पुल बनाकर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। शुक्रवार को शांशा नाले पर सीढ़ी व झूला लगाकर 73 लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें जिला मुख्यालय केलंग पहुंचाया वहां से गंतव्य के लिए रवाना किया गया। हालांकि तोजिंग व ब्रह्मगंगा नाले में बहे 11 लोगों का तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को लाहुल स्पीति नहीं पहुंच पाए। मौसम उनकी राह में बाधा बन गया। रोहतांग दर्रे पर घनी धुंध व लाहुल में बारिश की वजह से हेलीकाप्टर सुंदरनगर से उड़ान नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री को सुबह आठ बजे सुंदरनगर से लाहुल जाना था। वहां बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वे करना था। उदयपुर में फंसे पर्यटक एयरलिफ्ट नहीं हो सके। शिमला से हेलीकाप्टर मौसम की वजह से लाहुल नहीं पहुंच गया। लाहुल स्पीति में हिमाचल सहित नौ राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश के 241 पर्यटक व लोग विभिन्न क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। इनमें 209 लोग हिमाचल के सात जिलों, 32 पर्यटक आठ राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश का है। शनिवार को बाकी बचे लोगों को हेलीकाप्टर और अस्थायी पुलों के सहारे रेस्क्यू किया जाएगा।



लाहुल स्पीति के शांशा पुल की जगह सीढ़ियों से बनाए अस्थाई पुल से रेस्क्यू करते पुलिस व होमगार्ड और दमकल विभाग के कर्मी।

डूबने से बचाएगा 'लाइफबाय'

सौरभ शुक्ला, लखनऊ : बाढ़ और नदी में डूबने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए एसडीआरएफ (राज्य आपदा मोचन बल) का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके लिए 36 लाइफबाय उपकरण खरीदने की तैयारी है। रिमोट से संचालित लाइफबाय से नदी में डूब रहे तीन से चार लोगों को एक साथ बचाया जा सकेगा। अंग्रेजी के यू आकार के लाइफबाय में बैटरी और अत्याधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरण लगे हैं। बचाव दल इसे पानी में फेंक देगा। लाइफबाय रिमोट के माध्यम से डूब रहे लोगों के पास पहुंचेगा।

कटिहार के मेयर हत्याकांड में मां-बेटी सहित चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कटिहार

बिहार में कटिहार के महापौर (मेयर) शिवराज पासवान की हत्या के मामले में नामजद 11 आरोपितों में भाजपा विधायक के भतीजे का नाम भी शामिल है। शिवराज के भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपित कुमकुम श्रीवास्तव, उसकी बेटी मनीषा श्रीवास्तव, पिंकू पासवान और शुभम पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि गुरुवार रात गोली मारकर शिवराज पासवान की हत्या कर दी गई थी।

शुक्रवार को एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। घटनास्थल के निकट रेलवे ट्रैक के पास से बदमाशों द्वारा फेंकी गई पिस्तौल के अलावा हत्या में प्रयुक्त चार बाइक बरामद की गई हैं। उनमें एक बुलेट भी है, जो आरोपित सन्नी श्रीवास्तव की बताई जा रही। अब तक की जांच के मुताबिक हत्या का कारण पहले से चला आ रहा विवाद है। हालांकि, पुलिस दूसरे पहलुओं पर भी तफ्तीश कर रही। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि शिवराज के काल डिटेल खंगाले जा रहे हैं।

एक ही परिवार के पांच सदस्य नामजद: आरोपितों में एक ही परिवार के पांच सदस्य हैं। कुमकुम श्रीवास्तव, उसके पति टुनटुन श्रीवास्तव, बेटी मनीषा श्रीवास्तव के साथ दो पुत्र सन्नी श्रीवास्तव और गोल्डी श्रीवास्तव शामिल हैं। आरोपितों में कोढ़ा की भाजपा विधायक कविता पासवान के जेठ के बेटे नीरज पासवान भी नामजद है। एसपी ने बताया कि नीरज फरार है।

मेयर की हत्या के बाद चिराग ने लगाया पासवान जाति को निशाना बनाने का आरोप

राज्य ब्यूरो, पटना : लोजपा (चिराग) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कटिहार के महापौर (मेयर) शिवराज पासवान की हत्या की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पासवान जाति को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि उक्त वारदात इस बात की प्रमाण है किस तरीके से बिहार में अपराधियों का मन बढ़ता जा रहा है।

फतेहपुर के एडीजे की कार में इनोवा चालक ने मारी टक्कर

जासं, कौशांबी

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में अपर जिला जज मोहम्मद अहमद खान की कार में गुरुवार शाम एक इनोवा चालक ने टक्कर मार दी। एडीजे ने इनोवा चालक व उसमें सवार तीन अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

मोहम्मद अहमद खान फतेहपुर जनपद के पाक्सो एक्ट न्यायालय में अपर जिला जज हैं। गुरुवार को वह प्रयागराज गए थे। वापस लौटते समय शाम करीब साढ़े छह बजे वह जैसे ही कोखराज थाना क्षेत्र के चाकवन चौराहा के समीप पहुंचे थे, तभी पीछे से आ रही इनोवा ने रोकने का प्रयास किया। न रुकने पर उनकी आल्टो कार में टक्कर मार दी। सेंट्रों क्षतिग्रस्त हो गई जबकि एडीजे व उनके गनर बाल-बाल बच गए। गाड़ी रोकने के बाद उनके गनर ने इनोवा चालक को पकड़ लिया जबकि उसके साथ रहे अन्य तीन लोग भाग निकले।

जमानत खारिज करने पर मिली थी धमकी : एडीजे ने बताया कि 2020 में उन्होंने एक मुस्लिम युवक की जमानत खारिज कर दी थी। उसी समय उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। जिस व्यक्ति की जमानत बरेली में खारिज की गई थी, उसे कौशांबी जिले का बताया जा रहा है। पूछताछ में आरोपित चालक ने अपना नाम मोहम्मद उमर निवासी शहजादपुर बताया। सीओ सिराथू योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि तहरीर के आधार पर इनोवा चालक व तीन अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हालांकि एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने इसे दुर्घटना बताकर ट्वीट किया है।

गनर ने कहा, दो बार गाड़ी में मारी टक्कर: एडीजे के गनर ने बताया कि उनकी आल्टो कार का इनोवा चालक काफी दूर से पीछा कर रहा था। चाकवन चौराहा तक इनोवा के चालक ने उनकी कार में दो बार टक्कर मारी। दोनों बार टक्कर उसी साइड में मारी गई, जिधर एडीजे बैठे थे।

वारदात

अब तक की जांच में सामने आया है कि ओवरटेक के दौरान हादसे में एडीजे की कार क्षतिग्रस्त हुई। इस पर एडीजे ने इनोवा चालक से क्षतिग्रस्त वाहन की मरम्मत के लिए रुपये मांगे। रुपये लेनदेन की बात नहीं बनी तो उन्होंने तहरीर थाने में दी।

-राधेश्याम, पुलिस अधीक्षक

50 टीमें छान रहीं खाक, जज की हत्या की गुत्थी अनसुलझी

जागरण टीम, धनबाद

▶ हत्या में इस्तेमाल आटो और दो गिरफ्तारी से ज्यादा कुछ हाथ नहीं आया

▶ आटो चालक ने दुहराया कि शराब के नशे में गलती से लगी थी टक्कर

जज उत्तम आनंद की हत्या के दो दिन बाद भी पुलिस मामले को सुलझा नहीं पाई है। केस की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की 50 टीमें दिन रात मेहनत कर रही हैं, मगर सफलता के नाम पर एक आटो की बरामदगी और दो आरोपितों राहुल वर्मा व लखन वर्मा की गिरफ्तारी से अधिक कुछ हाथ नहीं आया है। हत्या क्यों हुई और किसने करवाई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। देश भर में इस हत्या को लेकर आक्रोश है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक मामले पर नजर बनाए हुए है, यही वजह है कि पुलिस इस मामले में फूंक-फूंक कर कदम उठा रही है।

सात घंटे तक एडीजी ने किया मंथन : मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए डीजीपी के स्तर पर बनाई गई एसआइटी के नेतृत्व कर रहे अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) संजय आनंद लाटेकर ने गुरुवार को सारे पहलुओं पर समीक्षा की। एसएसपी कार्यालय में लगातार सात घंटे की समीक्षा के बाद संजय आनंद लाटेकर ने कहा कि अभी कुछ भी ठोस बताने की हालत में नहीं है। इस मसले को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस कटिबद्ध है। सारे पहलुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। जल्द ही सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे।

स्वीकारा कि उसके आटो की टक्कर से जज मारे गए : एसआइटी में शामिल अधिकारियों ने आरोपित लखन वर्मा और राहुल वर्मा से पूछताछ की। उन लोगों ने पुरानी कहानी दोहराई। लखन ने स्वीकारा कि जज की मौत उसकी आटो के टक्कर से ही हुई है। घटना के पहले धनबाद स्टेशन रोड के पास झोपड़ी नुमा होटल में उन लोगों ने रात भर शराब पी थी। सुबह आटो लेकर निकले तो दुर्घटना हो गई। लोगों की पिटाई के डर से वे भाग गए थे। हालांकि पुलिस के गले यह थ्योरी उतर नहीं रही है। आटो चोरी करना, जानबूझकर धक्का मारना फिर 25 किमी दूर गाड़ी ले जाकर उसे छिपा देना एक नशेड़ी के लिए संभव नहीं।

जज उत्तम आनंद के भाई बोले, मेरे साथ दुर्घटना महज एक संयोग

जागरण संवाददाता, हजारीबाग : दिवंगत जज उत्तम आनंद के छोटे भाई अधिवक्ता सुमन शंभू भी कुछ दिन पहले दुर्घटना के शिकार हुए थे। वे इसे महज एक संयोग मानते हैं। दुर्घटना के संबंध में बताया कि आटो घर के पास ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इससे उनके पैर में चोट लग गई थी। इसमें कोई साजिश नहीं थी। उन्होंने हजारीबाग में भी किसी प्रकार की रंजिश से इन्कार किया है। बड़े भाई जज उत्तम आनंद के लिए उन्होंने फिर से सीबीआई जांच की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों के लिए सुरक्षा की मांग सरकार से की है।

नई पहल

देश के पहले डाल्फिन रिसर्च सेंटर का बिहार के मंत्री ने किया शुभारंभ, बिहार में सबसे अधिक 1465 गांगेय डाल्फिन, शो की कवायद

संरक्षित होंगी गांगेय डाल्फिन, शोध के लिए बनेगी नहर

जागरण संवाददाता, पटना

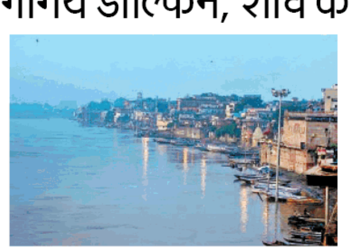
राष्ट्रीय जल जीव घोषित गांगेय डाल्फिन को संरक्षित किया जाएगा। इन पर शोध के लिए गंगा या कोसी नदी के पास दो-तीन किलोमीटर की नहर बनाई जाएगी। इसमें 10-15 डाल्फिन को रखकर उनकी हर गतिविधि पर शोध किया जाएगा।

उक्त बातें बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार ने कहीं। वह पटना साइंस कालेज में देश के पहले डाल्फिन रिसर्च सेंटर के उद्घाटन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि समुद्री डाल्फिन की तरह गांगेय डाल्फिन का शो आयोजित होगा। इसकी संभावना तलाशी जा रही है। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। छात्र-शिक्षकों से रिसर्च सेंटर को लेकर राय भी मांगी। कहा कि डाल्फिन रिसर्च सेंटर की किसी प्रकार की परेशानी को एक सप्ताह के अंदर दूर किया जाएगा।

इस अवसर पर प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि डाल्फिन रिसर्च सेंटर की नींव रखी गई है। इसके लिए 30 करोड़ से नया भवन बनेगा। सेंटर का कार्य कैसे किया जाए, इसको लेकर जल्द बैठक की जाएगी।

1994 से प्रयास को अब सफलता : डाल्फिन मैन के नाम से विख्यात माता वैष्णो देवी विवि जम्मू के कुलपति व पद्मश्री प्रो. आरके सिन्हा ने कहा कि शोध केंद्र के लिए 1994 से प्रयास कर रहा हूं। इसके लिए नेपाल, गोमुख, गंगा सागर, ब्रह्मपुत्र व विदेश का भ्रमण कर डाल्फिन की गतिविधियों को देख रहा हूं। लैब बनने से इसपर शोध हो सकेगा। इसके जेनेटिक्स को लेकर भी शोध हो सकेगा। इन्हें बचाने के लिए जन-जागरूकता की जरूरत है।

बिहार में सबसे अधिक डाल्फिन : डाल्फिन रिसर्च सेंटर के अंतरिम निदेशक व जुलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के विज्ञानी गोपाल शर्मा ने बताया कि देशभर में सबसे अधिक गांगेय डाल्फिन बिहार में हैं। 2018 में हुए सर्वेक्षण में 1465 गिनती की गई।



गांगेय डाल्फिन का शो आयोजित करने पर होगा विचार। फाइल फोटो

2 से तीन किलोमीटर की नहर बनाई जाएगी गंगा या कोसी के पास

10 से 15 डाल्फिन को रख उनकी गतिविधियों पर किया जाएगा शोध

30 करोड़ से बनेगा नया भवन, सेंटर की पूरी कार्य योजना को लेकर जल्द होगी बैठक

कई वन्य जीवों का होगा संरक्षण

डाल्फिन रिसर्च सेंटर अभी पटना साइंस कालेज स्थित पद्मश्री प्रो. आरके सिन्हा के लैब में संचालित होगा। इसमें काफी उपकरण हैं। सेंटर में कई अन्य वन्य जीवों का संरक्षण होगा। इसमें डाल्फिन, घड़ियाल, कछुआ, छल्ला, मंगोलिया, पेंटेड स्टोर्क, बड़ा एवं छोटा गरुड़, मगरमच्छ आदि वन्य जीवों का संरक्षण किया जाएगा।

कारगिल में वीरों की रणभूमि में पहुंची विजय मशाल

राज्य ब्यूरो, जम्मू

50 साल पहले लड़े गए युद्ध में शोरबत ला दर्रे को बचाया था भारतीय सेना

लद्दाख स्काउट्स के साथ सेना की मद्रास सैपर्स यूनिट के जवानों ने पहुंचाई मशाल

करीब 17730 फीट की ऊंचाई पर स्थित है शोरबत ला दर्रा। यह भी कारगिल में एक आम दर्रे की तरह है, लेकिन इस दर्रे में बहादुरी के कई किस्से छिपे हैं। कारगिल युद्ध की तरह 50 साल पहले शोरबत ला दर्रे में पाकिस्तान से लड़ी गई जंग में भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस व कुर्बानी देकर दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाया था। भारत-पाक युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष में विजयमशाल सोमवार को वीरों की रणभूमि में पहुंचीं। इस मौके पर हर जवान और अधिकारी का सीना गर्व से चौड़ा हो उठा।

पूर्व सैनिक शेरिंग डोरजे कहते हैं कि भारतीय जवानों ने करारी शिकस्त देकर शोरबत ला को दुश्मन से बचाया था। इस दौरान कई लद्दाखी सैनिकों ने वीरगति पाई थी। युद्ध में लद्दाख स्काउट्स के साथ सेना की मद्रास सैपर्स यूनिट ने अहम भूमिका निभाई थी। दोनों यूनिटों के अधिकारियों और जवान ने स्वर्णिम विजय मशाल को कठिन सफर तय कर शोरबत ला ले जाया। शहादत देने वाले जवानों को सलामी दी गई। उन पूर्व सैनिकों के योगदान को याद किया जिन्होंने शून्य से नीचे के तापमान में देश की खातिर जान हथेली पर ले दुश्मन से लोहा लिया था। सेना की विजय लद्दाख के शहीदों को सम्मानित करने को दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंचेगी। लेह में 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ युद्ध में हिस्सा ले चुके पूर्व सैनिकों को सम्मानित करेंगे।

डेल्टा प्लस वैरिएंट के 70 मामले मिले

संसद में सरकार ▸ वायरस के 58,240 नमूनों का अनुक्रम किया गया

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में अब तक कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वैरिएंट के 70 मामले पाए गए हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।

सिंह ने एक लिखित जवाब में कहा कि अब तक कोरोना वायरस यानी सार्स-कोव-2 के 58,240 नमूनों का अनुक्रम और इनमें से 46,124 नमूनों का विश्लेषण किया गया है। इनमें से 17,169 नमूनों में डेल्टा वैरिएंट पाया गया है जिसे देश में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। सिंह ने कहा कि 28 प्रयोगशालाओं के संगठन इनसाकाग द्वारा नमूनों की जीनोम अनुक्रमण किया गया है, जिसमें 23 जुलाई तक कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वैरिएंट के 70 मामले मिले हैं। डेल्टा वैरिएंट में बदलाव के बाद ही डेल्टा प्लस वैरिएंट बना है, हालांकि, डेल्टा की तरह यह ज्यादा संक्रामक नहीं है।

मंत्री ने बताया कि अल्फा वैरिएंट के 4,172, बीटा के 217 और गामा वैरिएंट का सिर्फ एक केस मिला है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा 23 मामले मिले हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में 11, तमिलनाडु में 10, चंडीगढ़ में चार और केरल एवं कर्नाटक में इसके तीन-तीन मामले पाए गए हैं।



केरल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच टीका लगवाने की लोगों में होड़ मची हुई है। शुक्रवार को राजधानी तिरुअनंतपुरम में एक टीकाकरण केंद्र पर टीके की खुराक के लिए भारी भीड़ नजर आई। प्रेट्र

बिना फोटो पहचान पत्र के भी 3.8 लोगों का टीकाकरण: स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने सदन को लिखित उत्तर में बताया कि 26 जुलाई तक बिना फोटो पहचान पत्र वाले 3.8 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ है। बिना फोटो पहचान पत्र के पात्र लाभार्थियों के टीकाकरण के लिए केंद्र ने जरूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि देश में जितने भी लोगों को टीका लगाया जाता है, उनका कोविन प्लेटफार्म पर पंजीकरण होता है।

वैक्सीन को लेकर भ्रांतियों को तुरंत दूर करती है सरकार: पवार ने बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रांतियों को तुरंत दूर किया जाता है। उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा कि देश में टीकाकरण तेजी से चल रहा है। जनवरी में 2.35 लाख डोज प्रतिदिन लगाई जा रही थीं, जिनकी संख्या अब बढ़कर 39.89 लाख प्रतिदिन हो गया है।

देश के 63 जिलों में कोई ब्लड बैंक नहीं : स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सदन को बताया कि देश के 63 जिलों में एक भी ब्लड बैंक नहीं है। 3,500 लाइसेंसधारी ब्लड बैंक हैं।

केरल में थम नहीं रहे कोरोना के मामले

जेएनएन, नई दिल्ली : केरल में कोरोना संक्रमण के मामले नियंत्रण में नहीं आ रहे। राज्य में लगातार चौथे दिन 22 हजार से ज्यादा मामले पाए गए जो देश भर में सामने आए कुल नए मामलों के आधे हैं। प्रतिदिन होने वाली मौतों की संख्या भी सौ से ऊपर बनी हुई है। केरल से ज्यादा मौतें सिर्फ महाराष्ट्र में ही हो रही हैं। लेकिन अगर आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो केरल की स्थिति गंभीर नजर आ रही है। कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने राज्य के लोगों से कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 44 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें से 22 हजार केस अकेले केरल से हैं। इस दौरान हुईं 555 मौतों में से भी केरल में 128 मौतें हुई हैं। केरल के हालात के चलते सक्रिय मामले भी लगातार तीन दिनों से बढ़ रहे हैं। पहले सक्रिय मामले चार लाख से नीचे आ गए थे और अब एक बार फिर चार लाख को पार कर गए हैं।

बच्चों के लिए टीका जल्द आने की उम्मीद बढ़ी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना महामारी के कारण बच्चे लंबे समय से स्कूलों से दूर हैं। उनकी जिंदगी घर की चारदीवारी व मोबाइल स्क्रीन तक सिमट गई है। तीसरी लहर की आशंका भी बनी हुई है। अच्छी बात यह है कि बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए दूसरी डोज देने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इससे बच्चों के लिए टीका जल्द आने की उम्मीद बढ़ गई है।

ट्रायल के दौरान पहले किशोरों को टीका देकर सुरक्षा का आकलन किया गया था। इसके बाद छह से 12 साल की आयु के बच्चों और अंत में दो से छह साल के बच्चों को टीका दिया गया। गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में दो से छह साल की उम्र के बच्चों को दूसरी डोज दी गई। इसके बाद ट्रायल का काम पूरा हो गया है। ट्रायल के दौरान बच्चों को टीके का प्रभाव भी देखा जा रहा है।

अगस्त के अंत तक या सितंबर के मध्य तक ट्रायल की अंतरिम रिपोर्ट आ सकती है। हालांकि, अंतिम रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा, लेकिन अंतरिम रिपोर्ट से पता चल सकेगा कि टीका बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है। इसके बाद उनके लिए टीके का इमरजेंसी इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। देश के छह अस्पतालों में 525 बच्चों पर यह ट्रायल चल रहा है। इसके तहत बच्चों को तीन उम्र वर्ग (12 से 18, छह से 12 व दो से छह) में बांटकर ट्रायल किया जा रहा है। एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डा. संजय राय के नेतृत्व में नौ जून को ट्रायल शुरू हुआ था।

डाक्टर कहते हैं कि ट्रायल के दौरान एक आयु वर्ग के बच्चों पर टीके की सुरक्षा का आकलन करने के बाद ही दूसरी आयु वर्ग के बच्चों को टीका दिया गया है। इसलिए उम्मीद है कि सुरक्षा के पैमाने पर बच्चों के लिए भी टीका खरा उतरेगा। टीका लगने के 28 दिन, 56 दिन, 118 दिन व 208 दिन पर बच्चों के ब्लड सैंपल लेकर एंटीबाडी जांच भी की जाएगी।

जिंदगी का टीका

- कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए बच्चों को दूसरी डोज देने की प्रक्रिया हुई पूरी
- अगस्त के अंत या सितंबर के मध्य में आ जाएगी ट्रायल की अंतरिम रिपोर्ट



देश में कोरोना की स्थिति

24 घंटे में नए मामले	44,230
कुल सक्रिय मामले	4,05,155
24 घंटे में टीकाकरण	51.83 लाख
कुल टीकाकरण	45.60 करोड़

शुक्रवार सुबह 08 बजे तक कोरोना की स्थिति

नए मामले	44,230
कुल मामले	3,15,72,344
सक्रिय मामले	4,05,155
मौतें (24 घंटे में)	555
कुल मौतें	4,23,217
ठीक होने की दर	97.38 फीसद
मृत्यु दर	1.34 फीसद
पाजिटिविटी दर	2.44 फीसद
जांचें (गुरुवार)	18,16,277
कुल जांचें (गुरुवार)	46,46,50,723

किस राज्य में कितने टीके

महाराष्ट्र	5.90 लाख
उत्तर प्रदेश	5.88 लाख
गुजरात	3.05 लाख
राजस्थान	2.31 लाख
बिहार	1.73 लाख
हरियाणा	1.18 लाख
पंजाब	1.11 लाख
उत्तराखंड	0.72 लाख
छत्तीसगढ़	0.69 लाख
झारखंड	0.60 लाख
हिमाचल	0.51 लाख
जम्मू-कश्मीर	0.41 लाख
मध्य प्रदेश	0.29 लाख

कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट देते दो कर्मचारी रंगे हाथों दबोचे

जागरण संवाददाता, कठुआ

- दूसरे राज्यों के लोगों को जम्मू-कश्मीर में आने के लिए 500 रुपये में देते थे फर्जी रिपोर्ट
- स्वास्थ्य विभाग के दोनों कर्मचारियों को सीएमओ कार्यालय में अटैच किया गया

जम्मू-कश्मीर के सबसे संवेदनशील लखनपुर मुख्य प्रवेश द्वार पर जिला स्वास्थ्य विभाग के दो कर्मचारियों को दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों से कोरोना जांच की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट जारी करने के आरोप में पकड़े गए हैं। लखनपुर रेड जोन में है। पुलिस ने दोनों कर्मचारियों को विभागीय कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया है। दोनों कर्मचारियों को लखनपुर से हटाकर सीएमओ कठुआ अटैच किया गया है।

लखनपुर में फर्जी जांच रिपोर्ट देने की शिकायतें पुलिस को काफी दिन मिल रही थीं। इसकी सूचना पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाई। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों कर्मचारियों को रिश्वत लेकर फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट देते रंगे हाथों पकड़ लिया। ये दोनों स्वास्थ्य कर्मी बिना कोरोना टेस्ट कराए ही 500 रुपये रिश्वत लेकर नेगेटिव रिपोर्ट जारी करते थे। दोनों कर्मी पिछले आठ माह लखनपुर में विशेष ड्यूटी के लिए तैनात किए गए थे। इनमें एक जूनियर लैब टेक्नीशियन राज कुमार शामिल है, जो लखनपुर से पहले प्राथमिक सेंटर रामकोट में तैनात था। दूसरा कर्मचारी जूनियर फार्मासिस्ट रोहित मेहरा यहां से पहले धनु परोल सब सेंटर में तैनात था। पहले इन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। हालांकि बाद में सीएमओ कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। इसके साथ ही जांच शुरू कर दी गई है।

> लखनपुर में कोरोना जांच केंद्र में तैनात स्वास्थ्य विभाग के दो कर्मी यात्रियों से फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट जारी करने के एवज में रिश्वत लेते हुए पकड़े हैं। उन्हें वहां से हटाकर कार्यालय में अटैच कर जांच करने के आदेश दिए गए हैं। -डा. अशोक चौधरी, सीएमओ, कठुआ

हरिद्वार के चेक पोस्ट पर प्रशासन ने खड़े किए गंगा जल के टैंकर

जागरण संवाददाता, हरिद्वार

कोविड के खतरे को देखते हुए कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित है। बावजूद इसके बाहरी राज्यों से कांवड़ यात्री पुलिस-प्रशासन को चकमा देकर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्री हरिद्वार न पहुंचे और बार्डर पर ही उनको गंगाजल उपलब्ध हो जाए, इसके लिए प्रशासन ने नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत यात्रियों को सीमा पर ही गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा। यात्रियों को बार्डर पर आधा लीटर गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने हर बार्डर पर नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। साथ ही, बार्डर पर हर जगह गंगाजल वितरण के लिए दो अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है।

मंडावर और काली नदी चेकपोस्ट: यहां पर प्रशासन ने टैंकर की व्यवस्था की है। बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को टैंकर से गंगाजल दिया जा रहा है। साथ ही, उन्हें सम्मानपूर्वक वापस लौटाया जा रहा है। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक मंडावर और काली नदी चेकपोस्ट से करीब 40 श्रद्धालुओं को गंगा जल दिया गया।

बीरपुर और गोकलपुर चेक पोस्ट: इस चेक पोस्ट पर शुक्रवार को कोई भी श्रद्धालु नहीं पहुंचा। हालांकि प्रशासन ने यहां पर भी टैंकर की व्यवस्था की थी।

नारसन चेकपोस्ट: नारसन चेक पोस्ट पर प्रशासन ने गंगा जल का एक टैंकर खड़ा किया है। एसपी देहात प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि कांवड़ यात्रियों को सम्मानपूर्वक गंगाजल देकर वापस भेजा जा रहा है। किसी को भी सीमा के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है।

खानपुर-पुरकाजी चेकपोस्ट: खानपुर-पुरकाजी बार्डर पर शुक्रवार दोपहर तक भी गंगा जल का टैंकर नहीं पहुंचा, जिस कारण कांवड़ यात्रियों को गंगा जल नहीं मिल पाया। इन यात्रियों को बगैर गंगा जल के ही वापस लौटा दिया गया। हालांकि दोपहर के बाद सीमा पर टैंकर पहुंच गया था। दोपहर बाद आने वाले कांवड़ यात्रियों को गंगा जल देकर वापस भेजा गया।

उपाय

- कांवड़ यात्रियों को बार्डर से ही गंगा जल देकर सम्मानपूर्वक लौटाया जा रहा वापस
- केवल चिड़ियापुर बार्डर पर नहीं है गंगा जल की व्यवस्था
- खानपुर-पुरकाजी चेक पोस्ट पर दोपहर बाद पहुंचा टैंकर

चिड़ियापुर चेक पोस्ट

चिड़ियापुर चेकपोस्ट पर प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों के लिए गंगाजल की व्यवस्था नहीं की है। इस कारण कांवड़ यात्रियों को बगैर गंगाजल के ही लौटना पड़ा। जल संस्थान के एई मदन सेन वर्मा ने कहा कि श्यामपुर समेत 11 स्थानों पर टैंकर के माध्यम से गंगाजल मुहैया कराया जा रहा है। जब उनसे चिड़ियापुर में टैंकर नहीं होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में पता किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के टीकाकरण अभियान को केंद्र ने सराहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- देश में टीके की सबसे अधिक डोज लगाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश
- दिसंबर तक राज्य में सभी वयस्कों के टीकाकरण को लेकर केंद्र आश्वस्त

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के टीकाकरण अभियान की सराहना की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महिलाओं के लिए विशेष 'पिंक बूथ' और क्लस्टर अप्रोच जैसे नए उपायों के कारण प्रदेश में टीकाकरण अभियान को गति मिली है। उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की सबसे ज्यादा डोज लगाई गई हैं।

उत्तर प्रदेश में टीकाकरण की धीमी रफ्तार और यहां कोरोना के खिलाफ संपूर्ण टीकाकरण में तीन साल का समय लगने की अटकलों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शुरू में वैक्सीन की कमी के कारण भले ही उत्तर प्रदेश में कम डोज लग रही थीं, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ने के साथ-साथ टीकाकरण की रफ्तार में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार की शाम को सात बजे तक उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की 4.75 करोड़ से अधिक डोज लग चुकी हैं। इनमें से डेढ़ करोड़ से अधिक डोज अकेले जुलाई महीने में लगाई गई हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उत्तरप्रदेश के टीकाकरण अभियान के तहत उठाए कदमों से साफ है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के बावजूद प्रदेश वैक्सीन की उपलब्धता के अनुरूप दिसंबर तक सभी वयस्कों के टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी 19.95 करोड़ है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्राजील और रूस जैसे कई देशों से अधिक है। जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से भले ही उत्तर प्रदेश में टीकाकरण अभी दूसरे राज्यों की तुलना में कम नजर आ रहा है, इसकी गति सबसे तेज है। उप्र की तरह ही अन्य राज्यों को भी काम करने की सलाह दी गई है।

राष्ट्रीय फलक

'किसी जाति की श्रेणी बदलने का अधिकार राज्य को नहीं'

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की खटवे जाति को अनुसूचित जाति में चौपाल के रूप में शामिल किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी जाति की श्रेणी को बदलने का अधिकार राज्य को नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। अदालत जानना चाहती है कि किसी जाति की श्रेणी बदलने का अधिकार राज्य को कैसे हो सकता है, जबकि संविधान में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं।

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने देवेंद्र रजक की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को उक्त निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि 16 मई, 2014 के एक निर्णय में बिहार सरकार ने खटवे जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया था।

प्रेस को चुप रहने का आदेश नहीं दे सकते : कोर्ट

राज्य ब्यूरो, मुंबई

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की एक मानहानि याचिका पर शुक्रवार को अंतरिम आदेश सुनाते हुए बांबे हाई कोर्ट ने कहा कि प्रेस को पूरी तरह से चुप रहने का आदेश हम नहीं दे सकते। शिल्पा ने पोर्नोग्राफी मामले में अपने पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद उनके बारे में अखबारों में लिखी जा रही खबरों और यूट्यूब पर अपलोड किए जा रहे वीडियो पर रोक लगाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति गौतम पटेल ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा यूट्यूब पर अपलोड किए गए तीन वीडियो को हटाने और उन्हें पुनः अपलोड न करने की हिदायत दी। पटेल का मानना था कि ये वीडियो न सिर्फ अपमानजनक हैं, बल्कि खबरों की दृष्टि से इनमें कोई पड़ताल भी नहीं की गई है। कोर्ट ने कहा कि प्रेस की आजादी और निजता के अधिकार में संतुलन बना रहना चाहिए। लेकिन शिल्पा शेट्टी की याचिका के दूसरे हिस्से पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि मीडिया पर प्रतिबंध लगाना खतरनाक हो सकता है। अच्छी और बुरी पत्रकारिता की एक सीमा है, जो प्रेस की आजादी के बहुत करीब है। शिल्पा ने अपनी याचिका में अखबारों में प्रकाशित जिन लेखों को अपमानजनक एवं मानहानिकारक बताया था, कोर्ट ने उन्हें ऐसा नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मीडिया आपके बारे में अच्छा ही अच्छा लिखे या अच्छा नहीं लिख रहा है, तो कुछ न लिखे। यह कैसे संभव है? शिल्पा ने अपनी याचिका में भी जिक्र किया था, जिसमें लिखा था कि पुलिस के छापे के दौरान शिल्पा अपने पति पर चिल्लाईं और लड़ीं। कोर्ट ने कहा कि यदि यह रिपोर्ट पुलिस सोर्सेज को आधार बनाकर लिखी गई है तो यह मानहानिकारक कैसे हो सकती है?

राज कुंद्रा का मामला

> आपने (शिल्पा शेट्टी ने) अपनी जिंदगी खुद चुनी है। यह सब उसी जिंदगी का हिस्सा है। आपकी जिंदगी माइक्रोस्कोप से ही देखी जाएगी।
>
> -हाई कोर्ट की टिप्पणी

राज कुंद्रा पर आन लाइन गेम के जरिये भी फ्राड का आरोप

राज्य ब्यूरो, मुंबई: अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें अलग-अलग प्लेटफार्म्स पर प्रदर्शित करने के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चल रहे कारोबारी राज कुंद्रा पर अब आन लाइन गेम के जरिये भी बड़ा फ्राड करने का आरोप लग रहा है। यह आरोप मुंबई के भाजपा विधायक राम कदम ने लगाया है। राम कदम ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज कुंद्रा की कंपनी विआन इंडस्ट्रीज लि. ने गेम आफ डाट (जीओडी) नामक एक आनलाइन गेम शुरू किया था। इस गेम के लिए देश भर में डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करने के नाम पर करोड़ों रुपये जमा किए गए। फिर उन डिस्ट्रीब्यूटरों से हर तरह का संपर्क बंद कर दिया गया। राज कुंद्रा ने डिस्ट्रीब्यूटरों को लुभाने के लिए अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी के नाम का भी इस्तेमाल किया। सूत्रों के अनुसार कंपनी के प्रतिनिधि 25 लाख रुपये मांगते थे, लेकिन बाद में 10-15 लाख में भी डिस्ट्रीब्यूटर बना देते थे।

संरक्षण मांग रहे देशमुख की याचिका पर तीन अगस्त को सुनवाई

नई दिल्ली, एएनआइ : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई से संरक्षण की मांग कर रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट तीन अगस्त को सुनवाई करेगा।

जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसी तरह की याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए मामला तीन अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। महाराष्ट्र में विभिन्न बार से कथित वसूली के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) देशमुख के खिलाफ जांच कर रहा है। ईडी की ओर से जारी समन पर देशमुख अभी तक एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं।

इतालवी मैरीन मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित: सुप्रीम कोर्ट ने इतालवी मैरीन मामले की सुनवाई दो अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में दो मछुआरों के परिवारों को मुआवजा वितरण पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई कर रही थीं।

राजस्थान में प्रदर्शनकारी किसानों ने फिर भाजपा नेता से की मारपीट

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान के श्रीगंगानगर में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल के साथ मारपीट की। उग्र किसानों ने मेघवाल के कपड़े फाड़ दिए। किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करना पड़ा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी एक भाजपा नेता के साथ प्रदर्शनकारी किसानों ने ऐसा ही बर्ताव किया था।

जानकारी के अनुसार मेघवाल महंगाई और सिंचाई को लेकर भाजपा की जिला इकाई द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने शुक्रवार को श्रीगंगानगर पहुंचे थे। मेघवाल जैसे ही श्रीगंगानगर के महाराजा गंगासिंह चौक पर पहुंचे तो वहां मौजूद किसान उग्र हो गए। किसानों ने अचानक मेघवाल पर हमला बोल दिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हंगामा बढ़ा तो पुलिस मौके पर पहुंची और मेघवाल को किसानों के कब्जे से छुड़वाया। पुलिस के अनुसार किसान भाजपा के प्रदर्शन का माहौल बिगाड़ने के लिए जा रहे थे। इसी बीच उन्होंने मेघवाल को देख लिया और उन पर हमला बोल दिया। किसान तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मेघवाल पर हमले की निंदा की है।



श्रीगंगानगर में प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नेता कैलाश मेघवाल के कपड़े फाड़ दिए। एएनआइ

प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज राजद्रोह के केस नहीं होंगे रद

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा की गाड़ी पर पथराव करने के आरोपितों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने को चुनौती देने वाली याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की पीठ ने खारिज कर दिया। सरकार के इस कदम को किसानों को डराने का प्रयास बताते हुए हरियाणा प्रोग्रेसिव किसान यूनियन ने याचिका दायर की थी। याचिका में इस कानून की वैधता पर सवाल उठाए थे। याची ने कहा था कि यह कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का हनन करता है। याची ने बताया कि 11 जुलाई को 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों पर एफआइआर दर्ज कर राजद्रोह की धारा जोड़ी गई थी।

किसी की इच्छा के खिलाफ दान लेना अवैध : कलकत्ता हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

फैसला

- विश्व भारती ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान के लिए प्रोफेसरों का काटा था वेतन
- एक प्रोफेसर ने विश्व भारती के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका

किसी की इच्छा के विरुद्ध दान लेना अवैध है। संबंधित व्यक्ति की इच्छा के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए। यह बात कलकत्ता हाई कोर्ट ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के संबंध में एक फैसले में कही।

दरअसल, विश्व भारती के अधिकारियों ने पिछले साल बंगाल में आए भीषण चक्रवात एम्फन से प्रभावितों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान करने का निर्देश जारी किया था। निर्देश में कहा गया था कि सभी प्रोफेसरों को एक दिन का वेतन राहत कोष में जमा करना अनिवार्य है। सुदीप्त भट्टाचार्य नाम के एक प्रोफेसर ने अधिकारियों के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। उनके अनुसार विश्व भारती विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उनकी इच्छा की परवाह किए बिना उनका वेतन जबरन काटा है। गत दिनों मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने वादी की याचिका पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि दान के लिए बलपूर्वक वेतन नहीं काटा जा सकता है।

इसके अलावा यह निर्णय कविगुरु रवींद्रनाथ टैगोर की विश्व भारती की संस्कृति और परंपरा के विपरीत है। इसके लिए उन्होंने विवि प्रशासन को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि बिना किसी की मर्जी या राय के दान नहीं लिया जा सकता है। उद्देश्य नेक ो तो भी दान के लिए दबाव नहीं दिया जा सकता है।

बाबा रामदेव के जवाब के बगैर बिना नहीं बढ़ेगी कार्यवाही : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान एलोपैथी के संबंध में दिए गए बयान के खिलाफ डाक्टरों के सात संघों की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि बाबा रामदेव के जवाब के बिना कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देंगे। पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब डाक्टरों के संघों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें प्रतिवादी के जवाब के बिना जिरह की अनुमति दी जाए। वहीं, रामदेव की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, अदालत ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। याचिका दायर करने वालों में पटना ऋषिकेश और भुवनेश्वर के तीन रेजिडेंट डाक्टरों के संघों के साथ ही एम्स, चंडीगढ़ का एसोसिएशन आफ रेजिडेंट डाक्टर्स व अन्य हैं।

तीसरे पक्ष के कहने पर एफआइआर रद नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कोरोना टीकाकरण नीति पर सवाल उठाने वाले पोस्टरों के मामले में दर्ज एफआइआर रद करने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इन्कार कर दिया। कोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल कर एफआइआर रद करने की मांग कर रहे याचिकाकर्ता से कहा कि तीसरे पक्ष के कहने पर एफआइआर रद नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि इससे आपराधिक कानून में गलत नजीर बनेगी। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि इस याचिका के खारिज होने का उन लोगों पर असर नहीं पड़ेगा जो वास्तव में प्रभावित हैं और कोर्ट में केस रद करने के लिए याचिका दाखिल करते हैं।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ के समक्ष अपनी याचिका पर स्वयं बहस कर रहे वकील प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर केसों के जो विवरण मांगे थे, वे उन्होंने दाखिल कर दिए हैं। इस पर पीठ ने कहा कि जिन केसों का विवरण आपने कोर्ट को दिया है कोर्ट उन केसों का ब्योरा कैसे जांचेगा। तीसरे पक्ष कहने पर एफआइआर रद नहीं हो सकती। इससे आपराधिक कानून में बहुत गलत नजीर बनेगी। ऐसा सिर्फ अपवाद के तौर पर किया जा सकता है। कोर्ट का नकारात्मक रुख देखते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी जो कोर्ट ने दे दी। याचिका में कहा गया था कि टीकाकरण नीति के बारे में पोस्टर लगाने में लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि पुलिस को केस दर्ज नहीं करने का सामान्य आदेश जारी नहीं किया जा सकता। आप ऐसे मामले बताएं जिनमें केस दर्ज हुए हैं।

विज बोले, दूसरों की आजादी को बाधित न करें आंदोलनकारी

जागरण टीम, चंडीगढ़

कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों पर हरियाणा सरकार भले ही कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही, लेकिन उन्हें सही राह पर आने का बार-बार मौका दे रही है। प्रदर्शनकारी भी सरकार के इस लचीलेपन का लगातार फायदा उठाने में लगे हैं। कभी वह भाजपा नेताओं का घेराव करते हैं तो कभी जजपा नेताओं के घर के आगे डेरा डाल देते हैं।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कहा कि किसान संगठनों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन इस आंदोलन की वजह से दूसरे लोगों की आजादी को बाधित करने का कोई अधिकार नहीं है। विज ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों को मर्यादा में रहकर आंदोलन करने का आह्वान कर रही है, लेकिन वह लगातार अपनी सीमा पार कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान में हर किसी को आने-जाने का अधिकार है। ऐसे में यदि जींद की सर्वखाप पंचायत भाजपा या जजपा नेताओं के आने जाने पर रोक लगाने का फैसला लेती है तो यह पूरी तह से गलत है।

आइटी रिफंड मद में 43,991 करोड़ रुपये जारी

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने रिफंड मद में इस वर्ष 26 जुलाई तक 21.03 लाख से अधिक करदाताओं को 43,991 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए हैं। इसमें से व्यक्तिगत आयकर रिफंड मद में 13,341 करोड़ रुपये और कारपोरेट रिफंड मद में 30,651 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। विभाग के अनुसार करीब 19.90 लाख व्यक्तिगत करदाताओं को अब तक रिफंड जारी किए गए हैं। (प्रेट्र)



भारतीय इकानमी तेज गति से विकास को तैयार है। इसमें ऊर्जा की मांग बढ़ेगी और घरेलू खनन व उत्पादन बढ़ाने की जरूरत होगी।
– हरदीप सिंह पुरी
पेट्रोलियम मंत्री

सेंसेक्स	52,586.84	▼ 66.23
निफ्टी	15,763.05	▼ 15.40
सोना प्रति दस ग्राम	₹47,442	▲ ₹294
चांदी प्रति किलोग्राम	₹66,104	▼ ₹170
डॉलर	₹74.42	▲ ₹0.13
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 75.89	

जून में करीब नौ फीसद रही कोर सेक्टर की विकास दर

रिकवरी
- पहली तिमाही के दौरान 25.3 फीसद का इजाफा
- इसमें कोयला, कच्चे तेल, सीमेंट, रिफाइनरी, खाद आदि शामिल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2021) के दौरान कोर सेक्टर में पिछले वर्ष समान तिमाही के मुकाबले 25.3 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि यह बढ़ोतरी पिछले साल अप्रैल-जून के दौरान देशव्यापी लाकडाउन की वजह से कोर सेक्टर के खराब प्रदर्शन की वजह से हैं।

पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कोर सेक्टर में 23.8 फीसद की गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं, इस वर्ष जून में कोर सेक्टर के उत्पादन में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 8.9 फीसद का इजाफा रहा। कोर सेक्टर में कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, खाद, स्टील, सीमेंट एवं बिजली शामिल हैं।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जून में स्टील का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। स्टील के उत्पादन में समीक्षाधीन अवधि के दौरान 25 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस वर्ष पहली तिमाही में भी स्टील के उत्पादन में सबसे अधिक 86 फीसद का इजाफा रहा। वहीं, जून में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 20.6, बिजली का 7.2, कोयले का 7.4, सीमेंट का 4.3, खाद का दो और रिफाइनरी उत्पाद का 2.4 फीसद बढ़ा।

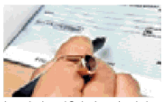
हालांकि कच्चे तेल के उत्पादन में पिछले साल जून के मुकाबले 1.8 फीसद की गिरावट दर्ज की गई। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में खाद का उत्पादन पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले 1.7 फीसद और कच्चे तेल का 3.4 फीसद गिरा।

कल से छुट्टी के दिन भी मिलेगी सैलरी, होगी चेक क्लियरिंग

आरबीआइ ने एनएसीएच को सातों दिन चालू रखने का फैसला लिया

बिलासपुर, नईदुनिया : किसी व्यक्ति या संस्था को चेक जारी करने वालों को अब सावधानी बरतनी होगी। अगर वे यह सोचकर अवकाश के दिनों का चेक जारी करेंगे कि उसका भुगतान बैंक खुलने के बाद ही होगा, तो उन्हें इसकी पेनाल्टी लग सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) द्वारा पहली अगस्त से लागू किए जा रहे बदलावों के तहत एक बड़ी सुविधा यह मिलने वाली है कि अब अवकाश के दिनों में भी चेक की क्लियरिंग होगी और वेतन-पेंशन का भुगतान होगा।

आरबीआइ ने नेशनल आटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) को पहली अगस्त से 24 घंटे सातों दिन चालू रखने का फैसला लिया है। यह नियम सभी सरकारी और निजी बैंकों में लागू होगा। आरबीआइ के इस निर्णय से वेतन और पेंशनभोगियों को बड़ा फायदा होगा। जिन ग्राहकों की लोन की ईएमआइ जा रही है, उन्हें और चेक जारी करने वालों को सतर्क रहना होगा। अब तक यह होता था कि अगर किसी लोन की ईएमआइ के भुगतान की तिथि को कोई अवकाश होता था तो अकाउंट से ईएमआइ की रकम बैंक के अगले कार्यदिवस में कटती थी। ऐसे में अगर ग्राहक के अकाउंट में ईएमआइ कटने के दिन पूरी रकम नहीं होती थी, तो उसके पास विकल्प होता था कि वह बैंक के अगले कार्यदिवस से पहले फोन या नेट बैंकिंग से अकाउंट में रकम डाल सकता था और उसकी ईएमआइ रुकती नहीं थी। अब उसी दिन ईएमआइ कटने से उसे यह वक्त नहीं मिलेगा। यही चेक जारी करने वालों के मामले में भी होगा।



वेतन और पेंशनभोगियों को इस फैसले से होगा फायदा • फाइल फोटो

आरबीआइ के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चार जून को यह घोषणा की थी। वर्तमान में इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम छुट्टी के दिनों में काम नहीं करता है। बैंकों में दो-तीन दिन का अवकाश हो जाता है या किसी अन्य वजह से बैंक बंद रहते हैं तो वेतन-पेंशन समेत अन्य मदों की रकम खाते में आने में देरी हो जाती है।

फाइनेंस और मेटल शेयरों में सुस्ती से गिरे बाजार

मुंबई, प्रेट्र : कारोबार के आखिरी घंटों में बिकवाली के चलते घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक गिरकर बंद हुए। फाइनेंस व मेटल शेयरों में सुस्ती का असर सकल बाजार पर दिखा। इससे बीएसई का 30-शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 66.23 अंक यानी 0.13 फीसद फिसलकर 52,586.84 पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) का 50-शेयरों वाला निफ्टी सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में 15.40 अंक यानी 0.10 फीसद गिरकर 15,763.05 पर स्थिर हुआ।

सेंसेक्स पैक में शुक्रवार को सर्वाधिक 2.5 फीसद का नुकसान बजाज फाइनेंस के शेयरों में दिखा। एसबीआइ, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स व एक्सिस बैंक के शेयर भी गिरे।

हालांकि सन फार्मा, टेक महिंद्रा, पावरग्रिड, बजाज आटो, एनटीपीसी और एचसीएल टेक के शेयरों में निवेशकों ने खरीदारी की।

केवाईसी अपडेट आग्रह के फर्जी मैसेज से बचें

नई दिल्ली, प्रेट्र : मोबाइल आपरेटर्स के संगठन सीओएआइ ने ग्राहकों को केवाईसी अपडेट कराने वाले संदेशों को लेकर चेतावनी दी है। सेल्यूलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआइ) ने शुक्रवार को कहा कि ग्राहकों के मोबाइल फोन पर ऐसे संदेश और काल आ रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि अगर वे केवाईसी प्रक्रिया दोबारा पूरी नहीं करेंगे तो उनका सिम कार्ड बंद किया जा सकता है। सीओएआइ के अनुसार, ये सभी संदेश व काल फर्जी हैं। ग्राहक इस जाल में नहीं फंसें।

उद्योग संगठन ने कहा, फर्जी गतिविधियां चलाने वाले लोग टेलीकाम ग्राहकों को काल या संदेश भेजकर उनके सिम कार्ड बंद कर देने की धमकी दे रहे हैं। अगर ग्राहक उनके निर्देशों का पालन शुरू कर देते हैं, तो उनके फोन का पूरा डाटा कापी या चोरी हो सकता है। इस झांसे में आने वाले ग्राहक बड़े वित्तीय जोखिम में फंस सकते हैं, क्योंकि फर्जीवाड़ा करने वाला व्यक्ति फोन के आंकड़ों से बैंक अकाउंट का परिचालन कर सारी रकम निकाल सकता है।



टेलीकाम उद्योग की संस्था ने ग्राहकों को किया सतर्क • फाइल फोटो

सीओएआइ के महासचिव एसपी कोचर ने एक बयान में कहा कि ऐसे संदेश और काल यह फर्जी दावा करते हैं कि ग्राहकों की केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है या उन्हें दोबारा अपडेट कराने की जरूरत है। ऐसे संदेशों में एक नंबर पर काल करने या फोन पर कोई खास एप डाउनलोड करने को कहा जाता है।

इंडियन आयल को तीन गुना लाभ, पर पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं घटाएगी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन आयल कारपोरेशन (आइओसी) का मुनाफा अप्रैल-जून, 2021 तिमाही में 5,41.37 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है। यह लाभ पिछले वर्ष समान अवधि के दौरान हासिल 1,910.84 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब तीन गुना है। इसके बावजूद कंपनी ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अपनी तरफ से कटौती की संभावना से इन्कार किया है। कंपनी ने परोक्ष रूप से कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा टैक्स में कटौती से ही आम ग्राहकों को राहत मिल सकती है।

वैसे, कंपनी के शुद्ध मुनाफे में यह बढ़ोतरी प्रोडक्ट की अधिक बिक्री से नहीं, बल्कि सस्ता क्रूड खरीदने और महंगी दरों पर पेट्रोल-डीजल बेचने से हुई है। पेट्रोलियम उत्पाद जिस समय बिक्री के लिए तैयार होते हैं, उस दिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम के आधार पर उनकी खुदरा कीमत निर्धारित की जाती है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड लगातार महंगा होता है तो कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाती हैं। आइओसी के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य से जब यह पूछा गया कि इतना मुनाफा होने के बाद आम लोगों को पेट्रोल व डीजल की कीमतों में राहत कब मिलेगी। उन्होंने कहा, दाम में 45-50 फीसद हिस्सा टैक्स का होता है। 21 जुलाई को पेट्रोल की बिक्री कोरोना संकट से पहले वाली स्थिति में पहुंच गई है। डीजल की बिक्री कोरोना पूर्व के मुकाबले अभी 88 फीसद ही है।



कंपनी के चेयरमैन ने कहा – दाम का बड़ा हिस्सा सरकारों के खाते में जाता है •

पेट्रोनास के साथ पेट्रोल पंप खोलेगी आइओसी

जाब्यू, नई दिल्ली: आइओसी ने मलेशिया की पेट्रोलियम कंपनी पेट्रोनास संग मिलकर गैस व दूसरे ईंधन की रिटेलिंग कारोबार में उतरने की घोषणा की है। अभी दोनों के बीच एलएनजी आयात करने के लिए बराबर हिस्सेदारी वाला संयुक्त उद्यम है। अब उन्होंने इंडियन आयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड (आइपीपीएल) के नाम से एक नया संयुक्त उद्यम स्थापित किया है, जो रिटेल कारोबार करेगी। यह संयुक्त उद्यम भारत के अलावा दूसरे देशों में भी फ्यूल रिटेलिंग में उतरने की मंशा रखता है। भारत में प्राकृतिक गैस की खपत बढ़ने की संभावना को देखते हुए कंपनी ने यह फैसला किया है।

काटन और यार्न निर्यात पर रोक लगाने की मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : गारमेंट निर्यातकों ने काटन और यार्न के निर्यात पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। कारोबारियों का कहना है कि गारमेंट के लिए जरूरी काटन और यार्न जैसे कच्चे माल के भारी निर्यात से घरेलू बाजार में लागत बढ़ रही है। ऐसे में निर्यातक बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं।

भारत सबसे अधिक काटन बांग्लादेश और चीन को निर्यात करता है और ये दोनों देश गारमेंट के अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। काटन सीजन 2021-22 में भारत ने 54.83 लाख गांठ काटन का निर्यात किया है। इनमें से 22 लाख गांठ चीन को निर्यात किया गया। बांग्लादेश को लगभग 25-27 लाख गांठ का निर्यात किए जाने का अनुमान है। गारमेंट निर्यातकों ने बताया कि निर्यात में भारी वृद्धि के चलते काटन की कीमत इस वर्ष जनवरी के 43,300 रुपये प्रति कैंडी (355 किलोग्राम) से बढ़कर इस माह 56,600 रुपये प्रति कैंडी पर पहुंच गई। पिछले छह माह में काटन के विभिन्न प्रकारों की कीमतों में 30 से 60 फीसद की वृद्धि हुई है। गारमेंट निर्यातकों के मुताबिक यहां भारत से 75 फीसद गारमेंट निर्यात का कच्चे माल काटन है।

अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अधिकारी व गारमेंट निर्यातक ललित ठुकराल ने बताया कि घरेलू स्तर पर काटन की कीमत बढ़ रही है। बांग्लादेश निर्यात होने वाले काटन का मूल्य घरेलू मूल्य से कम है क्योंकि निर्यात के लिए कीमत तीन माह पहले निर्धारित होती है। ऐसे में बांग्लादेश की गारमेंट निर्यात लागत भारत के मुकाबले कम होती है। गरीब देशों की श्रेणी में होने की वजह से बांग्लादेश को यूरोप व अन्य विकसित देशों में शुल्क में भी छूट मिली हुई है।

केंद्र ने कहा-बिजली चोरी रोकने का रोडमैप दिसंबर तक दें डिस्काम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) को दो टूक कह दिया है कि अगर उन्हें 3.30 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय स्कीम का फायदा उठाना है तो बिजली वितरण व्यवस्था में बदलाव का एजेंडा 31 दिसंबर, 2021 तक भेजना होगा। इसमें डिस्काम को नुकसान घटाने का फार्मूला और वितरण व्यवस्था सुधारने के लिए तकनीक के इस्तेमाल जैसी जानकारियां देनी होंगी। डिस्काम को यह भी बताना होगा वह इस रोडमैप पर किस तरह से आगे बढ़ेंगे। बिजली मंत्री आरके सिंह ने स्पष्ट कहा है कि डिस्काम को होने वाली हानि में बिजली चोरी की बड़ी हिस्सेदारी है। इस पर काबू पाए बिना उन्हें केंद्रीय मदद नहीं मिलेगी।

शुक्रवार को बिजली मंत्री ने सभी राज्यों के डिस्काम प्रमुखों और बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। यह बैठक हाल में केंद्र सरकार की तरफ से घोषित 3.30 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के मामले में भी थी। इसमें सिंह ने राज्यों से कहा कि जैसे-जैसे उनकी डिस्काम में सुधार होता जाएगा, उन्हें केंद्र से वित्तीय मदद मिलती जाएगी। अगर वितरण व्यवस्था में सुधार की गति मंद पड़ती है तो वित्तीय मदद भी घटा दी जाएगी। इसका मकसद जल्द से जल्द अंतरराष्ट्रीय स्तर की बिजली वितरण व्यवस्था स्थापित करना है, ताकि हर घर व हर संस्था को निर्बाध तरीके से 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो सके।



डिस्काम को होने वाले नुकसान में बिजली चोरी की है बड़ी हिस्सेदारी • फाइल फोटो

निर्देश
- बिजली मंत्री ने कहा-जैसे-जैसे सुधार होता जाएगा, वित्तीय मदद मिलती जाएगी
- सरकार 2024 तक टीएंडडी लास घटाकर 15% करने का लक्ष्य लेकर चल रही

सिंह ने कहा कि पिछले साथ-आठ वर्षों में राज्यों ने बिजली वितरण में होने वाली हानि को रोकने में कुछ सफलता हासिल की है, लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना शेष है। 2012-13 में देश टीएंडडी लास 25.5 फीसद था, जो 2019-20 में 21.8 फीसद था। इस तरह के आंकड़े संतोषजनक नहीं है। सरकार 2024 तक टीएंडडी लास घटाकर 15 फीसद करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

नवाब खानदान की संपत्ति बंटवारे में आपत्तियां दाखिल

रामपुर: नवाब खानदान की संपत्ति बंटवारे को लेकर दो पक्षकारों की ओर से शुक्रवार को आपत्ति दाखिल की गई, जबकि अन्य पक्षकारों को और समय दे दिया गया। रामपुर में नवाब खानदान की 2,600 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति के बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी गई है। जिला जज ने 15 जुलाई को विभाजन योजना पेश की थी। साथ ही कहा था कि यदि किसी को आपत्ति है तो 15 दिन के अंदर दाखिल कर दे। शुक्रवार को मोहम्मद अली खां उर्फ मुराद मियां और उनकी बहन निगहत बी की ओर से उनके अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल की। (जासं)

दुष्कर्म के आरोप में बीएसएफ जवान गिरफ्तार

कोलकाता : बांग्लादेशी महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। महिला गैरकानूनी तरीके से सीमा पार करके भारत में दाखिल हुई थी, जिसे लेकर पूछताछ करने की आड़ में जवान पर बंगाल के सीमावर्ती उत्तर 24 परगना जिले में स्थित बीएसएफ शिविर में उसके साथ दुष्कर्म का आरोप है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गायघाटा थाने में पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बीएसएफ के आरोपित सब इंस्पेक्टर को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। (राब्यू)

विदेशी महिला से छेड़छाड़ में बाबा के खिलाफ मामला दर्ज

ऋषिकेश : ऋषिकेश में पोलैंड की एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला ने जालंधर (पंजाब) में एक कथित बाबा पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। जालंधर से मामला ऋषिकेश के थाना मुनिकीरेती को स्थानांतरित किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, पोलैंड की यह महिला अपने एक मित्र के साथ पिछले साल भारत आई थी। इस दौरान वह मुनिकीरेती के तपोवन क्षेत्र में रुकी थी। यहां वह किसी याहू बाबा उर्फ शौर्य वर्धन पांडे के संपर्क में आई। महिला का आरोप है कि धर्मशाला व अन्य स्थानों पर जाने के दौरान बाबा ने उसके साथ अश्लील हरकत की। (जासं)

एक्सिस बैंक के मैनेजर ने की आइसीआइसीआइ में लूटपाट

- एक करोड़ का लोन चुकाने के लिए दिया वारदात को अंजाम
- लुटेरों ने महिला अधिकारी को मार डाला, एक अन्य को किया घायल

पालघर, प्रेट्र : महाराष्ट्र के पालघर जिले में दो लोगों ने आइसीआइसीआइ बैंक में लूटपाट की। इस दौरान उन्होंने बैंक की महिला अधिकारी को मार डाला, जबकि उसकी सहयोगी को घायल कर दिया। हालांकि, भागने के क्रम में लोगों ने एक हमलावर को पकड़ लिया। पकड़ा गया अनिल दुबे पहले इसी ब्रांच में मैनेजर था। आइएएनएस के अनुसार, फिलहाल वह नईगांव एक्सिस बैंक का ब्रांच मैनेजर है। पुलिस ने बताया कि दुबे ने एक करोड़ रुपये लोन लिया था। कर्ज चुकाने के प्रयास में उसने बैंक लूटने की साजिश रची।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइसीआइसीआइ बैंक की विरार शाखा में गुरुवार रात साढ़े आठ बजे घटी। उस समय बैंक में सिर्फ ये दोनों महिलाएं ही काम कर रही थीं।

विरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक सुरेश वराडे ने बताया कि दो आरोपितों में एक अनिल दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह पहले उसी ब्रांच में मैनेजर था, जहां यह घटना घटी। उन्होंने कहा, दोनों आरोपित बैंक में घुस गए और असिस्टेंट मैनेजर योगिता वर्तक और कैशियर श्रद्धा देवरुखकर को चाकू दिखाकर धमकाया। आरोपितों ने उनसे नकदी और गहना अपने हवाले कर देने को कहा और लूट का माल लेकर फरार होने लगे। उसी समय दोनों महिलाओं ने अलार्म बजा दिया और आरोपितों को रोकने की कोशिश की। नाराज हमलावरों ने दोनों कर्मचारियों को चाकू से गोद दिया। वहां पहुंचे लोगों ने दुबे को पकड़ लिया, जबकि उसका सहयोगी भागने में कामयाब रहा। लोग दोनों घायलों को लेकर अस्पताल गए, जहां डाक्टरों ने योगिता को मृत घोषित कर दिया।

फिल्म में काम दिलाने के नाम पर महिला से छेड़छाड़, चार गिरफ्तार

ठाणे, प्रेट्र : महिला कलाकार को कथित तौर पर धमकाने और छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने एक महिला और तीन अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। कासारवडवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

पुलिस अधिकारी ने बताया, आरोपितों ने पीड़ित महिला से कहा कि उसका चयन एक हिंदी फिल्म के लिए किया गया है। उन्होंने महिला से ठाणे के एक फार्म हाउस में मिलने के लिए कहा। गुरुवार की शाम चारों आरोपित कार में सवार हुए और महिला के साथ फार्महाउस की ओर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने गलत तरीके से महिला को छुआ। अपनी बात मनवाने के लिए उसकी तरफ हथियार भी तान दी। फार्महाउस पहुंचने के बाद महिला ने साहस दिखाते हुए इसकी जानकारी मनसे कार्यकर्ताओं को भेज दी। मनसे कार्यकर्ता फार्महाउस पर पहुंच गए और आरोपितों को पकड़ लिया। आरोपितों की पहचान राहुल तिवारी, कंचन यादव, राकेश यादव और बीरलाल यादव के रूप में की गई है।

मुफ्त बिरयानी की मांग कर फंसीं आइपीएस

राज्य ब्यूरो, मुंबई: पुणे की एक आइपीएस अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी से मुफ्त बिरयानी की मांग कर बुरी तरह फंस गई हैं। उनकी आडियो क्लिप वायरल होने पर गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने पुणे के पुलिस आयुक्त को मामले की जांच करने के आदेश दे दिए हैं।

वायरल हो रही आडियो क्लिप में पुणे जोन-1 की पुलिस उपायुक्त अपने अधीनस्थ एक कर्मचारी से यह पूछती सुनाई दे रही हैं कि विश्रामबाग पुलिस थाना क्षेत्र में अच्छी बिरयानी कहां मिलती है? जब उनका अधीनस्थ कर्मचारी बताता है कि एक जगह देसी घी की बिरयानी अच्छी मिलती है, तो डीसीपी महोदया उसे बिरयानी लाने का आदेश देती हैं, और कहती हैं कि यदि वह पैसा मांगे तो क्षेत्रीय थानाध्यक्ष से बात कर लेना। अधीनस्थ पुलिसकर्मी बताता है कि बाहर से खाना मंगाने पर वे लोग हमेशा भुगतान करते हैं, तो डीसीपी महोदया गरम होकर कहती हैं कि अपने ही क्षेत्र में मुझे पैसे देने पड़े तो क्या फायदा।

पान मसाला निर्माता समूह के 400 करोड़ के अवैध धन का पता चला

- कानपुर, दिल्ली, नोएडा में 31 ठिकानों पर हुई कार्रवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र: आयकर विभाग ने छापा मारकर पान मसाला बनाने वाले कंपनी समूह के 400 करोड़ रुपये से ज्यादा के अवैध लेन-देन का पता लगाया है। समूह का कारोबार उत्तर भारत में फैला हुआ है। यह जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीटीबीटी) ने दी है।

सीटीबीटी के अनुसार आयकर विभाग ने गुरुवार को कंपनी के कानपुर, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और कोलकाता के 31 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह समूह रियल एस्टेट के धंधे में भी शामिल है। शुरुआती जांच में समूह के 400 करोड़ रुपये से ज्यादा के अवैध लेन-देन का पता चला है। सीटीबीटी ने समूह की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। सीटीबीटी आयकर विभाग की नीति निर्धारक संस्था है। बताया गया है कि समूह ने पान मसाला बेचकर और रियल एस्टेट से अकूत संपत्ति बनाई है। इसके बाद अर्जित धन 115 शेल कंपनियों (कागजों पर बनी कंपनियां) में लगाया गया। आयकर विभाग ने 52 लाख रुपये नकद और सात किलोग्राम सोना भी जब्त किया है। धन के अवैध लेन-देन के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ये दस्तावेज गुप्त स्थानों पर छिपाकर रखे गए थे।

एसएससी सदस्य के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा

भुवनेश्वर, जासं : आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एसएससी) के सदस्य पीएस बिरंचि साहू के ठिकानों पर शुक्रवार को सतर्कता विभाग ने छापेमारी की। कटक एवं भुवनेश्वर स्थित उनके कुल छह ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। सतर्कता विभाग के एसपी आर प्रकाश ने बताया दो मंजिले दो इमारत के साथ नौ जगहों पर जमीन है। घर से विदेशी नोट के भी बंडल मिले हैं। साहू के साले के घर से 13 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

खेल जागरण

नए लुक में नजर आए धौनी

संजीव रंजन • रांची

बदलाव
- प्रसिद्ध हेयर स्टाइलिस्ट आलिम खान ने दिया है यह नया स्टाइल
- युवा कर रहे पसंद, नया लुक बटोर रहा सुर्खियां

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी मैदान में रहें या बाहर, चर्चा में बने रहते हैं। धौनी के जबरदस्त प्रशंसक होने के कारण वह जो भी नया करते हैं, वो वायरल हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण के साथ ही उनके बाल चर्चा का विषय रहे हैं। यहां तक पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी धौनी के बालों की तारीफ की थी।

अब हाल ही में धौनी ने फिर एक अलग हेयर स्टाइल अपनाया है। धौनी का यह नया हेयर स्टाइल प्रसिद्ध हेयर स्टाइलिस्ट आलिम खान ने दिया है। धौनी के हेयर स्टाइल के साथ उनकी दाढ़ी को भी नया लुक दिया गया है। आलिम ने धौनी की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की और प्रशंसकों को इंटरनेट मीडिया पर उनका यह लुक काफी पसंद आ रहा है। धौनी के इस हेयर कट का नाम है फाक्स हाक। इंटरनेट मीडिया पर धौनी पीले रंग की टी शर्ट पहने नजर आ रहे हैं। उनके साथ आलिम खान भी हैं। धौनी अब तक अपने बालों को कई लुक दे चुके हैं।



नए लुक्स फाक्स हाक में कुछ इस तरह दिख रहे हैं महेंद्र सिंह धौनी • ट्विटर

डिकवेला, मेंडिस, गुणतिलका पर एक साल का प्रतिबंध

कोलंबो, प्रेट्र : श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने पिछले महीने इंग्लैंड के दौरे पर कोविड-19 प्रोटोकाल का उल्लंघन करने के लिए शुक्रवार को सीनियर खिलाड़ियों कुशल मेंडिस, निरोशन डिकवेला और दनुष्का गुणतिलका पर एक साल के प्रतिबंध के साथ एक करोड़ श्रीलंकाई रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के दौरान किसी ने इन तीनों को डरहम की सड़कों घूमते हुए कैमरे में कैद कर लिया था। उन्होंने टीम के बायो-बबल (कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए सुरक्षित माहौल) को तोड़ा था। इसके बाद उन्हें दौरे के बीच में घर वापस भेज दिया गया था। उन्हें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली अनुशासनात्मक समिति का भी सामना करना पड़ा, जिसने डिकवेला के लिए 18 महीने के प्रतिबंध, मेंडिस और गुणतिलका के लिए दो साल के प्रतिबंध की सिफारिश की थी। समिति ने हालांकि शुक्रवार को उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलने पर छह महीने और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। उनकी बाकी एक साल की सजा को निलंबित कर दिया गया है।

इथियोपिया के धावक ने जीता पहला स्वर्ण

ओलिंपिक डायरी

टोक्यो, एपी : इथियोपिया के धावक सेलेमोन बारेगा ने शुक्रवार को टोक्यो ओलिंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा का पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में यह जीत हासिल की। बारेगा ने विश्व चैंपियन और विश्व रिकार्डधारी युगांडा के जोशुआ चेपटेगई को पछाड़ते हुए 27 मिनट 43.22 सेकेंड में जीत दर्ज की। चेपटेगई ने 27 मिनट 43.63 सेकेंड के समय से रजत, जबकि उनके हमवतन जैकब किपलिमो ने कांस्य पदक जीता। ब्रिटेन के मो फराह ने पिछले दो ओलिंपिक में इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन इस बार वह ब्रिटिश टीम में जगह नहीं बना सके थे।

दक्षिण अफ्रीका की तैराक ने बनाया विश्व रिकार्ड: दक्षिण अफ्रीका की ततयाना शोएनमेकर ने तैराकी की व्यक्तिगत स्पर्धा में विश्व रिकार्ड बनाया। उन्होंने महिलाओं की 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में दो मिनट 18.95 सेकेंड का समय निकालकर दो मिनट 19.11 सेकेंड का डेनमार्क की रिक्के मोलेर पीडरसन का रिकार्ड तोड़ा, जो उन्होंने बार्सिलोना में 2013 विश्व चैंपियनशिप में बनाया था। अमेरिका की लिली किंग को रजत व एनी लेजर को कांस्य पदक मिला।

क्रिकेटर मिशेल स्टार्क के छोटे भाई ने ओलिंपिक फाइनल में बनाई जगह : क्रिकेट के मैदान में जहां बड़े भाई मिशेल स्टार्क तेज रफ्तार गेंदों से कहर बरपाते हैं तो वहीं टोक्यो ओलिंपिक में उनके छोटे भाई और एथलीट ब्रेंडन स्टार्क भी चर्चा में हैं। ऊंची कूद प्रतियोगिता में 2.28 मीटर की छलांग के साथ ब्रेंडन फाइनल में प्रवेश कर गए हैं, जो रविवार को खेला जाएगा।

टेनिस डबल्स में स्वर्ण व रजत दोनों पदकों पर क्रोएशिया का कब्जा : टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष डबल्स फाइनल यादगार रहा, क्योंकि 113 साल के बाद फाइनल में दोनों टीमें एक ही देश से थीं। वह भी ऐसे देश की जोड़ी जिसके किसी खिलाड़ी ने टेनिस में पहले स्वर्ण या रजत पदक नहीं जीता। इस मैच में क्रोएशिया की निकोला मेक्टिक और मेट पाविक की जोड़ी ने हमवतन मारिन सिलिक व इवान डोडिग को 6-4, 3-6, 10-6 से हराया।

ओलिंपिक में लगा थूक का अंबार

एक शीशी में एक मिलीलीटर थूक, रोजाना 30,000 शीशियां और ओलिंपिक खत्म होने तक लगभग 5,00,000 मिलीलीटर (करीब 500 लीटर) से ज्यादा थूक, ओलिंपिक के बीच कोरोना मामलों पर काबू रखने के लिए रोजाना हो रही जांच के ये कुछ आंकड़े हैं। ओलिंपिक के दौरान रोजाना करीब 30,000 लोग छोटी-छोटी प्लास्टिक की शीशियों में थूक के नमूने दे रहे हैं, जो करीब एक मिलीलीटर होता है। इनमें दुनिया भर से खेलों में भाग लेने आए लोग शामिल हैं। आठ अगस्त को ओलिंपिक खत्म होने तक करीब पांच लाख शीशियों में पांच लाख मिलीलीटर थूक जमा हो जाएगा। इस थूक को ट्यूबों में जमा करके बारकोड लगाकर रखा जा रहा है, जिनके नतीजों में संशय होता है, उनकी दोबारा जांच होती है। यहां जांच नाक में एक स्टिक डालकर नहीं की जा रही, जो कोरोना जांच का प्रचलित एक अन्य तरीका है। अभी तक खेलों से जुड़े 220 लोग संक्रमित पाए गए हैं।

दैनिक जागरण
जीवन की दिशा बदलनी है तो कर्म की दिशा बदलिए

अराजकता को प्रोत्साहन

कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में देश को शर्मसार करने वाली हिंसा को अंजाम देने वालों के प्रति पंजाब सरकार की मेहरबानी हैरान करने वाली भी है और परेशान करने वाली भी। पंजाब सरकार इस हिंसा में शामिल तत्वों को न केवल कानूनी सहायता देने की तैयारी में है, बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता देने का भी मन बना रही है। यह और कुछ नहीं अराजकता को प्रोत्साहन देने वाला काम है। इससे खराब बात और कोई नहीं कि अराजक तत्वों को कोई राज्य सरकार इस तरह पुरस्कृत करे। 26 जनवरी को कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर दिल्ली में तथाकथित किसानों ने ट्रैक्टर रैली के नाम पर जैसी भद्दी हरकत की थी, उसे देश भूल नहीं सकता। इस पावन दिन दिल्ली में जो कुछ हुआ था, उसे हिंसा के नंगे नाच के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। इस घटना ने यही बताया था कि ट्रैक्टर रैली निकालने वालों के मन में न तो गणतंत्र दिवस के प्रति कोई मान-सम्मान था और न ही संविधान के प्रति। यह घटना इसीलिए हुई थी, क्योंकि किसान नेता अपनी जिद पर उतर आए थे। यह मानने के भी अच्छे-भले कारण हैं कि देश को नीचा दिखाने वाली यह घटना किसान नेताओं के उकसावे पर ही हुई थी।

माना कि पंजाब में विधानसभा चुनाव निकट हैं और राज्य सरकार किसानों को रिझाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह लोकलाज छोड़कर अराजकता के आरोपितों के साथ खड़ी नजर आए। ऐसा करना एक बेहद बुरी परंपरा की नींव डालना है। पंजाब सरकार को कानून के शासन और संवैधानिक मर्यादा की तनिक भी परवाह है तो उसे इस मामले में आगे बढ़ने से बाज आना चाहिए। उसे जितनी जल्दी यह आभास हो जाए तो अच्छा कि इसके नतीजे खुद उसके लिए अच्छे नहीं होंगे। इससे वैसे तत्वों को बल मिलेगा, जो जोर-जबरदस्ती और हिंसा के जरिये अपनी मांगें मनवाने की कोशिश में रहते हैं। यह पहली बार नहीं जब पंजाब सरकार संकीर्ण राजनीतिक कारणों से अराजकता में लिप्त तत्वों का तुष्टीकरण करने की कोशिश करती दिख रही हो। यह जगजाहिर है कि उसने ऐसा ही रवैया तब अपनाया था, जब पंजाब के किसान रेल पटरियों पर बैठे थे या फिर जब मोबाइल टावर नष्ट किए जा रहे थे। दुर्भाग्य से इस मामले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार भी पीछे नहीं। यह किसी से छिपा नहीं कि वह किसान आंदोलन से जुड़े मामलों की सुनवाई में किस तरह अपने खास वकील नियुक्त करना चाहती है। इसका मकसद अराजकता के आरोपितों की सहानुभूति हासिल करना और खुद को उनका हितैषी साबित करना ही है।

पुरुषार्थ को प्रणाम

हरियाणा सरकार ने लघु उद्यमियों को प्रति यूनिट दो रुपये सस्ती बिजली देने का फैसला कर उनके पुरुषार्थ और पराक्रम को प्रणाम किया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने तय किया है कि डी श्रेणी के ब्लाक में 40 किलोवाट और सी श्रेणी के ब्लाक में 30 किलोवाट या उससे कम लोड लेने वाले उद्यमियों को सस्ती बिजली तब तक उपलब्ध कराई जाती रहेगी, जब तक संबंधित उद्यम चलते रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके लिए उद्यमियों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। बिजली कंपनियां स्वतः बिल में अनुदान की राशि समायोजित कर लेंगी। लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को यह लाभ देना तर्कसंगत है, क्योंकि लघु उद्यमी अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में अपने उद्योगों का संचालन करते हैं। वह न केवल अपने उद्योग के स्वामी होते हैं, अपितु उनसे दूसरे लोगों की रोजी-रोटी भी चलती है और वे भी अपने उन अन्य कामगारों की भांति स्वयं भी उसी भाव से काम करते हैं।

राज्य के लगभग हर नगर-उपनगर में हजारों लघु और सूक्ष्म उद्यम हैं, कहीं पर भी देखा जा सकता है कि इन उद्योगों को संचालित करने वाले उद्यमी सुबह अन्य कामगारों की तरह अपना भोजन लेकर आते हैं। कामगार भले आठ बजे चले जाएं, लेकिन उद्यमी सुबह दस बजे आते हैं तो रात आठ बजे के बाद ही घर जाते हैं। वे अपने उद्योगों के माध्यम से अपने लिए तो रोजगार सृजित करते ही हैं, आठ दस लोगों को प्रत्यक्ष और लगभग इतने ही लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इसलिए उन्हें यह सुविधा देना एक अच्छा फैसला है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि किसी ने गलत तथ्यों के आधार पर सस्ती बिजली पाने की सुविधा प्राप्त की है तो उसे 12 प्रतिशत प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर के साथ समायोजित राशि लौटानी पड़ेगी। इसके साथ ही उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसा करना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह की सुविधाओं के दुरुपयोग की बात नई नहीं है, जैसे प्रदेश में सस्ती बिजली की व्यवस्था किसानों के लिए है, लेकिन उसका लाभ नेता रूपी कथित किसान लेते हैं। हरियाणा सरकार की यह पहल अपेक्षा के अनुरूप आकार लेती है तो निःसंदेह लाभदायक सिद्ध होगी और इससे अन्य राज्य भी प्रेरणा ले सकेंगे, जिसके व्यापक लाभ देखने को मिलेंगे।

बंगाल में लोकतंत्र का जनाजा



प्रकाश सिंह

ऐसे कदम उठाने की सख्त आवश्यकता है, जिनसे वैसी घटनाओं की किसी अन्य प्रदेश में पुनरावृत्ति न हो जैसी बंगाल में देखने को मिलीं



अवधेश राजपूत

'यह बड़ी विडंबना है कि रवींद्रनाथ टैगोर के प्रदेश में, जहां प्रख्यात कवि ने यह कल्पना की थी कि मस्तक हमेशा ऊंचा रहेगा, मस्तिष्क भयमुक्त होगा और जहां समाज टुकड़ों में नहीं विभक्त होगा, उसी राज्य में हजारों लोगों के साथ हत्या, दुष्कर्म, पलायन और धमकी इत्यादि की घटनाएं पिछले कुछ महीने में हुई हों।' इन शब्दों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने बंगाल में चुनाव बाद की हिंसक घटनाओं की जांच का निष्कर्ष निकाला है। विडंबना यह है कि ममता सरकार इस निष्कर्ष को सिरे से खारिज कर रही है। अभी दिल्ली आईं ममता बनर्जी ने चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं को भाजपा का ड्रामा करार दिया। ज्ञात हो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशानुसार एनएचआरसी ने बंगाल में चुनाव पश्चात हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सात टीमों ने बंगाल के सभी जनपदों का दौरा कर मामलों की गहराई से पड़ताल की। समिति को कुल 1,979 शिकायतें मिली थीं, जिनमें करीब 15,000 व्यक्ति प्रभावित हुए थे। जांच से जो तथ्य आए हैं, उन्हें किसी भी चश्मे से देखा जाए, वे अत्यंत भयावह हैं। देश में चुनावों के दौरान अनियमितताओं की शिकायत तो हम हमेशा से सुनते आए हैं, परंतु चुनाव परिणाम प्राप्त होने के बाद हिंसा के लिए कुख्यात प्रदेशों में भी शांति हो जाती थी और लोग नई सत्ता को स्वीकार कर लेते थे। किसी ने पक्ष में वोट डाला हो या विपक्ष में, बाद में कोई मारपीट नहीं होती थी। इसके उलट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने छांट-छांटकर उन लोगों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई की, जिन्होंने अन्य पार्टी को वोट दिया।

एनएचआरसी की रिपोर्ट के अनुसार 'बहुत बड़ी संख्या में आपराधिक तत्वों, जिन्हें राज्य का संरक्षण प्राप्त था, ने सुनियोजित और व्यापक पैमाने पर हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया।' प्रतिशोध की भावना से हिंसा हुई, जिसमें सत्तारूढ़ दल द्वारा मुख्य प्रतिस्पर्धी दल को निशाना बनाया गया, जिससे हजारों लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ और उन्हें भयंकर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सदस्यों को यह देखकर दुख हुआ कि इन घटनाओं की स्थानीय नेताओं द्वारा निंदा करना तो छोड़िए, बल्कि मौके पर भी नहीं गए और ऐसे कोई कदम नहीं उठाए, जिससे लोगों का कष्ट कम हो सके। लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। पुलिस के बारे में लिखा है कि वह या तो लापरवाह थी या इन सब कृत्यों में उसकी मिलीभगत थी। फलस्वरूप तृणमूल कांग्रेस के अराजक तत्वों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। संपूर्ण प्रदेश से जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उनमें अधिकतम कूचबिहार (322) से मिलीं। दूसरे स्थान पर बीरभूम (314) रहा। इन शिकायतों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो हत्या की 29 घटनाएं थीं, दुष्कर्म की 12, गंभीर चोट की 391, आगजनी की 940 और धमकी की 562। जांच कमेटी ने पाया कि पुलिस ने बहुत सी शिकायतों को दर्ज नहीं किया और जो शिकायतें दर्ज हुईं, उनमें घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए गिरफ्तारियां बहुत कम हुईं। बहुत से मामलों में सही धाराएं नहीं लगाई गईं और ऐसा प्रतीत हुआ कि अपराध को कम करके दर्ज किया गया। सभी एफआइआर में 9,304 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए। इनमें केवल 1,354 (14 प्रतिशत) की गिरफ्तारी की गई। इन गिरफ्तारियों में 1,086 (80 प्रतिशत) को जमानत मिल गई। कुल मिलाकर आरोपित व्यक्तियों में केवल तीन प्रतिशत जेल में पाए गए, शेष 97 प्रतिशत खुले घूम रहे। समिति ने लिखा है कि यह तंत्र का मखौल उड़ाने जैसा था। प्रख्यात दार्शनिक लॉक के अनुसार जब कानून का राज समाप्त होता है तो अत्याचार की शुरुआत होती है। कुछ ऐसा ही नजारा समिति को बंगाल में दिखा।

देश में पुलिस की आज जो दुर्दशा हो रही है, वह सर्वविदित है। हम अंग्रेजों को औपनिवेशिक पुलिस बनाने का दोष देते हैं, पर हमारे नेताओं ने तो उसका राजनीतिकरण और कुछ हद तक आपराधीकरण भी कर दिया है। हाल में हमने देखा कि महाराष्ट्र में वहां का शासकीय तंत्र कैसे पुलिस से व्यापक पैमाने पर धन की उगाही करा रहा था। अब बंगाल का नमूना हमारे सामने है, जहां सत्ताधारी दल ने मतदाताओं के उस वर्ग पर, जिसने उसके विरुद्ध मत दिया था, कहर ढाया।

बंगाल की जो भी आलोचना हो रही है, वह सही है। आवश्यकता अब इसकी है कि कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं, जिनसे वहां जैसी घटनाओं की किसी अन्य प्रदेश में पुनरावृत्ति न हो। सबसे पहले तो संविधान की सातवीं अनुसूची में संशोधन कर पुलिस को समवर्ती सूची में लाया जाए। इससे प्रदेश स्तर पर पुलिस का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसे रोकने में सहायता मिलेगी। पुलिस को और आधुनिक बनाने की दिशा में भी केंद्र सरकार ठोस कदम उठा सकेगी। प्रधानमंत्री ने देश को 'स्मार्ट पुलिस' यानी एक ऐसी पुलिस जो संवेदनशील, गतिशील, जवाबदेह, त्वरित कार्रवाई में दक्ष और तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो, का सपना दिखाया था। आवश्यकता है इस सपने को साकार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की। सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा कि उसने 2006 में पुलिस सुधार संबंधी जो निर्देश दिए थे, उन्हें धरातल पर लागू करने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए। यह खेद का विषय है उसके निर्देशों की प्रदेश सरकारें खुल्लमखुल्ला उल्लंघन कर रही हैं।

बंगाल की ममता बनर्जी सरकार भले ही एनएचआरसी की रिपोर्ट को खारिज करे, परंतु इस संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता। उसकी जांच टीम ने लिखा है कि बंगाल में विधि का शासन के बजाय शासक का विधान है। उसने चेतावनी के रूप में यह भी कहा कि यदि इस चिंताजनक रुझान को रोका नहीं गया तो शायद यह बीमारी, जिसमें सरकारी तंत्र की पूरी ताकत सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति में लगा दी जाती है, अन्य प्रदेशों में भी फैल जाए। यदि ऐसा हुआ तो बंगाल की तरह अन्यत्र भी लोकतंत्र का जनाजा निकल जाएगा। सच्चाई तो यह है कि यह बीमारी कमोबेश कई राज्यों में फैल चुकी है और पानी सिर से ऊपर गुजरने की स्थिति में है।

(लेखक उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे हैं)

response@jagran.com

पहाड़ों से छेड़छाड़ के घातक नतीजे



पंकज चतुर्वेदी

इस पर गौर नहीं किया जा रहा है कि नष्ट किए गए पहाड़ों के साथ उससे जुड़ा पूरा पर्यावरणीय तंत्र ध्वस्त होता है

बरसात के मौसम में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन जनित घटनाएं बहुत आम होती जा रही हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र के कई गांवों में बरसात तबाही लेकर आई। पहाड़ों की गोद में बसे कई गांव देखते ही देखते नजरों से लुप्त हो गए। महाराष्ट्र के रायगढ़ के महाड़ में पहाड़ खिसका और बस्ती मलबे में बह गई। रत्नागिरी के पोसरे बोद्धवाड़ी में भी तबाही हुई। राज्य के करजात, दाभोल, लोनावला आदि में पहाड़ सरकने से खूब नुकसान हुआ। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ के मलबे ने कई गांवों को बर्बाद कर दिया। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और सिलीगुड़ी से भी ऐसी ही खबरें हैं कि पहाड़ों का सीना काटकर जो सड़कें बनाई गई थीं, अब वहां बरसात के बाद मलबा बिछ गया है। ऐसी घटनाएं अभी बारिश के तीन महीनों में खूब सुनाई देंगी। जब कहीं मौत होगी तो कुछ मुआवजा बांटा जाएगा, लेकिन तबाही के असल कारणों को कुछ लोग जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। सुना है कि महाराष्ट्र सरकार अब पहाड़ के तले बसे गांवों को अन्यत्र बसाने की तैयारी कर रही है।

पहाड़ खिसकने के पीछे असल कारण उस बेजान खडी संरचना के प्रति बेपरवाही ही होती है। पहाड़ खिसकने की त्रासदी का सबसे खौफनाक मंजर अभी कुछ साल पहले उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा के मार्ग पर देखा गया था। देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए जंगल, पानी बचाने की तो कई मुहिम चल रही हैं, लेकिन मानव जीवन के विकास की कहानी के आधार रहे पहाड़-पठारों के नैसर्गिक स्वरूप को उजाड़ने पर कम ही विमर्श हो रहा है। समाज और सरकार के लिए पहाड़ अब जमीन या धनार्जन का माध्यम बनकर रह गए हैं और पहाड़ अपने और समाज को सहेजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

हजारों-हजार साल में गांव-शहर बसने का मूल आधार वहां पानी की उपलब्धता होता था। पहले नदियों के किनारे सभ्यता आई, फिर ताल-तलैयों के तट पर बस्तियां बसने लगीं। किसी भी आंचलिक गांव को देखें, जहां नदी का तट नहीं है, वहां कुछ पहाड़ और पहाड़ के निचले हिस्से में झील तथा उसे घेरकर बसी बस्तियों का ही भूगोल दिखेगा। वहां के समाज ने पहाड़ के किनारे बारिश की हर बूंद को सहेजने तथा पहाड़ पर नमी को बचाकर रखने की तकनीक सीख ली थी। हरे-भरे पहाड़, खूब घने जंगल वाले पहाड़ जिन पर जड़ी-बूटियां, पक्षी और जानवर होते थे।



प्रकृति के कोप को आमंत्रण देतीं मानवीय गतिविधियां। फाइल

जब कभी पानी बरसता तो पानी को अपने में समेटने का काम वहां की हरियाली करती, फिर बचा पानी नीचे तालाबों में जुट जाता। भरी गर्मी में भी वहां की शाम ठंडी होती और कम बारिश होने पर भी तालाब लबालब।

बीते चार दशकों में तालाबों की जो दुर्गति हुई सो हुई, पहाड़ों पर हरियाली उजाड़ कर झोपड़-झुग्गी उगा दी गईं। नंगे पहाड़ पर जब पानी गिरता है तो सारी पहाडी काट देता है। अब तो पहाड़ों में पक्की सड़कें भी बनाई जा रही हैं। पहाड़ को एक बेकार-बेजान संरचना समझकर खोदा जा रहा है, लेकिन यह ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि नष्ट किए गए पहाड़ के साथ उससे जुड़ा पूरा पर्यावरणीय तंत्र ध्वस्त होता है। अब गुजरात से देश की राजधानी को जोड़ने वाली 692 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वतमाला को ही लें। अदालतें बार-बार चेतावनी दे रही हैं कि पहाड़ों से छेड़छाड़ मत करो, लेकिन बिल्डर लाबी सब पर भारी है। कभी सदानीरा कहलाने वाले इस इलाके में पानी का संकट खड़ा हो गया है। सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, हिमालय, कोई भी पर्वतमालाएं लें, खनन ने पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रेल मार्ग या हाईवे बनाने के लिए पहाड़ों को मनमाने तरीके से बारूद से उड़ाने वाले इंजीनियर इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि पहाड़ स्थानीय पर्यावास, समाज, अर्थव्यवस्था, आस्था और विश्वास का प्रतीक होते हैं। पारंपरिक समाज भले ही इतनी तकनीक न जानता हो, लेकिन इंजीनियर तो जानते हैं कि धरती के दो भाग जब एक-दूसरे की तरफ बढ़ते हैं या सिकुड़ते हैं तो उनके बीच का हिस्सा संकुचित होकर ऊपर की ओर उठकर पहाड़ की शक्ल लेता है। जाहिर है कि इस तरह की संरचना से छेड़छाड़ के भूगर्भीय दुष्परिणाम उस इलाके के कई-कई किलोमीटर दूर तक हो सकते हैं। पुणे जिले के मालिण गांव से कुछ ही दूरी पर एक बांध है। उसके निर्माण में वहां की पहाड़ियों पर बारूद का खूब इस्तेमाल हुआ। जुलाई 2014 को यह गांव पहाड़ लुढ़कने से पूरा तबाह हो गया। यह जांच का विषय है कि इलाके के पहाड़ों पर हुई तोड़फोड़ का इस भूस्खलन से कहीं कुछ लेना-देना था या नहीं?

किसी पहाड़ी की तोड़फोड़ से इलाके के भूजल स्तर पर असर पड़ने, कुछ झीलों का पानी पाताल में चले जाने की घटनाएं तो होती ही रहती हैं। यदि गंभीरता से देखें तो मनुष्य के लिए फिलहाल पहाड़ों का छिन्न-भिन्न होता पारिस्थितिकी तंत्र चिंता का विषय ही नहीं है। इसका विमर्श कभी पाठ्य पुस्तकों में होता ही नहीं है। आज हिमालय के ग्लेशियर और वहां के पर्यावरण को बचाने के लिए तो सरकार सक्रिय हो गई है, लेकिन देश में हर साल बढ़ते बाढ़ और सुखाड़ वाले इलाकों में पहाड़ों से छेड़छाड़ पर कहीं गंभीरता नहीं दिखती। पहाड़ नदियों के उद्गम स्थल हैं। पहाड़ नदियों का मार्ग हैं। पहाड़ों पर हरियाली न होने से वहां की मिट्टी तेजी से कटती है और नीचे आकर नदी-तालाब में गाद के तौर पर जमा होकर उसे उथला बना देती है। पहाड़ पर हरियाली बादलों को बरसने का न्योता होती है। पहाड़ अपने करीब की बस्ती के तापमान को नियंत्रित करते हैं। वे मवेशियों के चरागाह होते हैं। पहाड़ गांव-कस्बे की पहचान हुआ करते हैं। बहुत कुछ कहा जा सकता है इन मौन खड़े छोटे-बड़े पहाड़ों के लिए, लेकिन अब यह जरूरी है कि उनके प्राकृतिक स्वरूप को अक्षुण्ण रखने के लिए कुछ किया जाए।

(लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्मनियंत्रण

मनुष्य अपनी उन्नति का कारक और निर्धारक स्वयं है। उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। लक्ष्य के प्रति समर्पण ही उसे इतिहास रचने की ओर उन्मुख करता है। हमारे भीतर आत्मबल का निर्माण आत्मनियंत्रण से होता है। आत्मनियंत्रण ही हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। आत्मनियंत्रण का अधिष्ठान धैर्य, संयम एवं समर्पण है। इन्हीं गुणों से आत्मनियंत्रण को परिभाषित किया जा सकता है। आत्मनियंत्रण जिस व्यक्ति के भीतर होता है, वह आत्मशक्ति को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। यही आत्मशक्ति हमें हमारे ध्येय को प्राप्त करने में सहायक बनती है। जब हम स्वयं के नियंत्रण में होते हैं तो वही करते हैं जो श्रेष्ठ होता है। जो स्वयं के अथवा सामने वाले के हित में होता है। नियंत्रण सृजन का कारक है। नियंत्रणहीन वस्तु अथवा व्यक्ति सदैव विपदा को आमंत्रित करते हैं। जब तक पतंग नियंत्रण में होती है तो वह नई ऊंचाइयों को प्राप्त करती है। जैसे ही पतंग उड़ाने वाले का उससे नियंत्रण हट जाता है अथवा डोर टूट जाती है तो पतंग अवनति को प्राप्त होकर फट जाती है। ठीक इसी तरह यदि हम स्वयं पर नियंत्रण खो देते हैं तो हमारी अवनति निश्चित है।

आत्मनियंत्रण के बल पर ही हमारा मन नियंत्रण में आएगा और हमारा व्यक्तित्व प्रखर होगा। हम आत्मिक रूप से सशक्त होंगे। हमारे चरित्र में भटकाव नहीं रहेगा। हमारी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। आत्मनियंत्रण का मार्ग हमारे मन से होकर गुजरता है। यदि हमारे भीतर मन को नियंत्रित करने की सामर्थ्य है तो निश्चित ही हम स्वयं पर नियंत्रण कर लेंगे। हम जब भी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस समय आत्मनियंत्रण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नए कार्य को प्रारंभ करने में कठिनाई आ सकती है। यदि हमारा मन स्थिर होगा तो हमारे संकल्प भी मजबूत होंगे और हम कार्य को सिद्धि तक पहुंचा सकते हैं। हम योग-साधना के माध्यम से भी आत्मनियंत्रण का अभ्यास कर सकते हैं।

ललित शौर्य

आम आदमी के साहित्यकार

योगेश कुमार गोयल

स्मरण

प्रेमचंद की रचनाएं मानवीय संवेदनाओं और सरोकारों से जुड़ी रहीं तो वे आम आदमी को अपने बहुत करीब लगती हैं

आज मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जन्मतिथि है। उपन्यास सम्राट और कालजयी कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित प्रेमचंद को आम आदमी का साहित्यकार भी कहा जाता है। चूंकि उनकी अधिकांश रचनाएं आम जनजीवन और सरोकारों से ही जुड़ी रहीं तो वे आम आदमी को अपने बहुत करीब लगती हैं। उन्होंने गरीब-गुरबों की पीड़ा को न केवल समझा, बल्कि अपनी रचनाओं के जरिये उसका निदान बताने का प्रयास भी किया। उनके सृजन संसार में आम आदमी की भावनाओं, समस्याओं तथा संवेदनाओं का मार्मिक शब्दांकन मिलता है। आज जब हमारे समाज का एक वर्ग खुद को हाशिये पर महसूस कर रहा हो और उसके जीवन में दुश्वारियां बढ़ती जा रही हों तो प्रेमचंद साहित्य और प्रासंगिक हो उठता है।

निःसंदेह प्रेमचंद हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर हैं। मौजूदा पीढ़ी के लेखक भी उन्हें 'भूतो न भविष्यति' वाली श्रेणी का साहित्यकार मानते हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने समाज को सदैव रूढ़िवादी परंपराओं और कुरीतियों से निकालने का प्रयास किया। प्रेमचंद की लेखनी न सिर्फ दासता के विरुद्ध आवाज बनकर मुखर हुई, बल्कि उन्होंने लेखकों के उत्पीड़न के खिलाफ भी अलख जगाई। वह सही मायनों में 'कलम के सिपाही' थे। गद्य साहित्य की शायद ही कोई ऐसी विधा हो, जिन्हें प्रेमचंद की कलम ने झंकृत और चमत्कृत न किया हो। यह भी किसी परीकथा से कम नहीं कि जिन प्रेमचंद की गिनती हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में होती है, उनके साहित्यिक सफर की शुरुआत उर्दू के माध्यम से हुई थी। वर्ष 1909 में कानपुर के 'जमाना प्रेस' से उर्दू में ही उनका पहला कथा संग्रह 'सोज ए वतन' प्रकाशित हुआ था, जिसकी सभी प्रतियां ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर ली थीं। उर्दू में वह 'नवाब राय' के नाम से लिखते थे। जमाना के संपादक मुंशी दयानारायण ने उन्हें परामर्श दिया कि भविष्य में अंग्रेज सरकार के कोप से बचने के लिए वह नवाब राय के बजाय प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू करें, जबकि उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उनके बारे में सुमित्रानंदन पंत ने कहा था कि प्रेमचंद ने नवीन भारतीयता और नवीन राष्ट्रीयता का समुज्ज्वल आदर्श प्रस्तुत कर महात्मा गांधी के समान ही देश का पथप्रदर्शन किया है।

आदर्शों के पैमाने पर प्रेमचंद की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। उन्होंने जिन मूल्यों की पैरवी की, अपने जीवन में उनका पालन भी किया। वह विधवा विवाह के पक्षधर थे। पहली पत्नी के निधन के बाद समाज के विरुद्ध जाकर उन्होंने वर्ष 1905 में शिवरानी नामक बाल विधवा से विवाह किया। वैसे तो उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में लेखन कार्य आरंभ कर दिया था, लेकिन उनके लेखन में परिपक्वता शिवरानी से विवाह के पश्चात ही आई थी। शिवरानी ने ही बाद में उनकी जीवनी भी लिखी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

आलोचना नहीं परिश्रम से निकलेगा हल

एमजे अकबर लिखित आलेख 'भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता' को पढ़ा। आलेख में उन्होंने भारतीय लोकतंत्र से जुड़ी सामान्य विशिष्टताओं के रेखांकन का प्रयास किया है, परंतु इस क्रम में वह कतिपय वैचारिक विचलन के शिकार हुए हैं। उदाहरण के लिए, उनके अनुसार भारत की एक बड़ी आबादी आज भी चौथी दुनिया में रहने को अभिशप्त है तथा आधुनिक मशीनों के फायदे उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। यह गलत बात है। आधुनिक तकनीक और मशीनें जाति और धर्म से परे प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित कर रही हैं। यह समझने की जरूरत है कि कुछ दिनों अथवा वर्षों में इच्छित सामाजिक-राजनीतिक लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। किसी भी राष्ट्र के लिए सामाजिक बराबरी हासिल करना उसका अंतिम लक्ष्य और आदर्श होता है। यह सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो अगले पचास अथवा सौ सालों के बाद भी नहीं रुकने वाली। यदि किसी पंक्ति में खड़े कुछ व्यक्तियों के शरीर पर गर्म शाल नहीं है तो हम उनके लिए भी उसकी व्यवस्था करेंगे, मेहनत करेंगे, न कि उन्हें भला-बुरा कहेंगे जिन्होंने उसे हासिल किया है। जिन 16 प्रतिशत लोगों के अति उपभोग का जिक्र लेखक ने किया है, वे वही लोग हैं, जिन्होंने खूब मेहनत की है और टैक्स देकर देश की आर्थिक तरक्की में योगदान कर रहे हैं। मौजूदा केंद्र सरकार ने अपने सात वर्षों से अधिक के शासनकाल में विशेषकर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए तमाम योजनाएं चलाई हैं, जिनका पर्याप्त लाभ भी लाभार्थियों को मिल रहा है। इसे कोई नहीं झुठला सकता, लेकिन समस्या बड़ी है तो उसके समग्र समाधान के लिए समय भी देना होगा। आलोचना करने अथवा तंज कसने की बजाय क्यों नहीं हम ज्ञान आधारित, परिश्रम आधारित और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के निर्माण की बात करते हैं, ताकि तमाम राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इनमें गरीबी की समस्या का निवारण भी शामिल है।

चंदन कर्ण, झारखंड

मेलबाक्स

आतंक का खात्मा जरूरी

अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के हटते ही तालिबानी आतंकवाद ने पुनः पैर पसार लिए हैं। यहां पर बढ़ता तालिबानी आतंक न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। अफगानिस्तान में पनपते आतंकवाद को पर्दे के पीछे से पाकिस्तान द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने अपना दोहरा रूप दिखा रहे पाकिस्तान को एक बात शीघ्र समझ लेनी चाहिए कि आतंक को पालने का उसका यह दांव खुद उसके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। आतंकवाद के प्रसार से फिलहाल अफगानिस्तान सरकार बेबस नजर आ रही है। आतंकियों के बढ़ते वर्चस्व व अस्थिरता के कारण यहां पर महिलाओं का जीना मुश्किल हो गया है। कई जगहों पर महिलाओं ने तालिबानी शोषण के खिलाफ हथियार तक उठा लिए हैं। यह समय बढ़ते आतंकवाद पर काबू करने का है। विश्व के सभी बड़े राष्ट्रों को मिलकर आतंकवाद के खात्मे के प्रयास करने चाहिए।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला गांव

हड़ताल नहीं है समाधान

ऐसे समय में जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लोगों को एक दूसरे के मदद की जरूरत है, उत्तर प्रदेश में एंबुलेंस कर्मियों का हड़ताल करना उचित नहीं है। कोरोना से पूरी तरह से निपटने के लिए चिकित्सा से जुड़े लोगों की भूमिका काफी अहम है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। स्वास्थ्यकर्मियों के योगदान के बिना कोरोना पर विजय पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर ऐसे नाजुक समय में चिकित्सा से जुड़े लोग हड़ताल पर जाएंगे तो देश की चिकित्सा व्यवस्था का धराशायी होना निश्चित है। अफसोस की बात है कि इन दिनों हड़ताल और धरना एक फैशन बन गया है, जिसमें समय और पैसे दोनों का नुकसान होता है। हमें समझना होगा कि किसी भी समस्या का निदान तोड़फोड़ और धमकी से नहीं होता। इसका सबसे सर्वोत्तम उपाय है बातचीत। इसलिए अगर किसी को भी सरकार से कोई समस्या है तो बातचीत से उसका हल ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए न कि हड़ताल पर बैठने की।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

10 हजार वैसे लोग जो कोविड रोधी टीके की दोनों खुराके ले चुके है, उनमें से महज दो से चार लोग ही संक्रमित पाए गए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार।

आजकल

भारत के वैध क्षेत्र पर पाक का अवैध चुनाव

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में गुलाम कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए हैं और इसमें उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुमत मिला है। हालांकि भारत ने गुलाम कश्मीर में कराए गए इस चुनाव को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। भारत का कहना है कि इस क्षेत्र में अपने अवैधानिक आधिपत्य को वैध बनाने के लिए पाकिस्तान ने चुनाव की आड़ ली है। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली करने के लिए भी उसे साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है



विवेक ओझा
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार



गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की रणनीति को नाकाम करने में जुटा है भारत। इंटरनेट मीडिया

हाल ही में पाकिस्तान की ओर से गुलाम कश्मीर में कराए गए चुनाव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी को भले ही बहुमत हासिल हुआ हो, लेकिन भारत सरकार ने इस चुनाव को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुलाम कश्मीर में कराए गए तथाकथित चुनाव और साथ ही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तर्क को भी खारिज कर दिया है। हालांकि इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के एक शीर्ष राजनयिक को तलब कर गुलाम कश्मीर में हाल में संपन्न चुनावों पर भारत की टिप्पणियों को 'खारिज' किया है।

अब सवाल यह उठता है कि इमरान खान को गुलाम कश्मीर में चुनाव कराने की क्या जरूरत पड़ गई। दरसअल इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ जिन क्षेत्रों से विरोध के स्वर उन्हें सुनाई दिए उनसे कठोरता से निपटने की कोशिश पाक सरकार ने की है। इमरान खान को बीते दिनों गुलाम कश्मीर से निरंतर उठने वाले गंभीर विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा है। गुलाम कश्मीर क्षेत्र के साथ इमरान ने अन्य पाकिस्तानी क्षेत्रों के मुकाबले भेदभाव किया है। इमरान खान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर को ध्यान में रखते हुए कुछ खास फैसले किए हैं। पिछले वर्ष इमरान सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान को गुलाम कश्मीर में प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देने की घोषणा की थी। इससे पूर्व इमरान सरकार ने फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया (फाटा) का विलय खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में संविधान संशोधन के जरिये किया था, क्योंकि इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के विरोधी मौजूद थे। फाटा क्षेत्र में पख्तून राष्ट्रवाद की लहर व्याप्त रही है जिसके चलते वहां के लोग अपने लिए नागरिक अधिकारों की मांग पाक सरकार से करते रहे हैं। लेकिन पाक सरकार ने इस क्षेत्र की स्वायत्तता, राष्ट्रवादी मानसिकता को खत्म कर उसे पाकिस्तान के एक पूर्ण राज्य में विलय कर उसके अर्धस्वायत्त जनजातीय क्षेत्र की पहचान को खत्म कर दिया। पाक ने बीते साल गिलगिट-बाल्टिस्तान में भी विधानसभा चुनाव कराया था, जिसका भारत ने विरोध किया था।

पाकिस्तान की सक्रियता के कारण : गुलाम कश्मीर की जनता पाकिस्तानी सेना की ओर से जबरन भूमि कब्जे, इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के अभाव, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी, आइएसआइ द्वारा लोगों पर छापेमारी से त्रस्त रही है। यहां सर्वाधिक बिजली बनने के बावजूद लोगों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं होती और उसे बाहर बेच दिया जाता है। गुलाम कश्मीर में पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन होते रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भारत तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद की मांग करते रहे हैं। गुलाम कश्मीर में पिछले साल एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार तनवीर अहमद ने पाकिस्तानी झंडा उतार दिया था जिसके बाद उसे सुरक्षा एजेंसियां उठा कर ले गईं। महंगाई से जुड़े विरोध प्रदर्शनों पर गुलाम कश्मीर में स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश पाकिस्तान द्वारा दिए गए। इन सब कारणों से वहां स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पों का दौर शुरू हो चुका है। गुलाम कश्मीर क्षेत्र में कश्मीरी छात्र संगठनों ने भी पाक सेना का विरोध करना शुरू कर दिया है। गुलाम कश्मीर में इमरान खान की पार्टी की सरकार बनने से अब वहां चीन की परियोजनाओं के खिलाफ आवाजें उतनी आसानी से नहीं उठ पाएंगी, क्योंकि इमरान चीन को स्वाभाविक मित्र मानते हुए उसके हक में काम करने को आमादा हैं।

जम्मू कश्मीर के संबंध में भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दौरान की गई विभिन्न पहल और उन पर अमल को पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाया है। भारत द्वारा पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करना, सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र का दर्जा वापस लेना, अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करना, जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करते हुए लेह लद्दाख की प्रशासनिक स्थितियां बदल देना, जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए सक्रिय होना, मीरपुर मुजफ्फराबाद को भारत के नक्शे में दिखाना, गुलाम कश्मीर क्षेत्र में परिसीमन के लिए मांग करना आदि न जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं जिससे पाकिस्तान को लगातार यह भय बना रहा है कि गुलाम कश्मीर में भारत कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक न खेल दे ताकि पाक के सभी नापाक मंसूबे धरे के धरे रह जाएं। लद्दाख में जिस तरह अवसंरचनाओं के विकास का काम भारत द्वारा किया जा रहा है उससे चीन और पाकिस्तान दोनों ये सोचने लगे हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान से गुजरने वाले चीन पाक आर्थिक गलियारे का भविष्य क्या होगा? भारत की रणनीति भी है कि गुलाम कश्मीर क्षेत्र के पास ऐसा विकास कार्य हो जिससे वहां की जनता यह सोचने को विवश हो जाए कि हम भी ऐसे ही सुशासन के हकदार हैं, न कि पाकिस्तान की ज्यादती के। पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर या बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों को हमेशा भारत विरोध की प्रयोगशाला के रूप में ही अधिक इस्तेमाल कर इन क्षेत्रों के साथ ठीक वैसा ही भेदभावमूलक बर्ताव किया जैसा उसने पिछली सदी के सातवें दशक तक पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) के साथ किया था। पूर्वी पाकिस्तान के संसाधनों और अर्थव्यवस्था को आज के पाकिस्तान ने निचोड़ कर रख दिया था और उस क्षेत्र के विकास की खबर केवल इसलिए नहीं ली कि वह अपेक्षाकृत उदार सहिष्णु प्रदेश था।

पाकिस्तान जैसे देशों को समझना चाहिए कि किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करना, उसका अपने में विलय करना कोई महान काम नहीं है जब तक कि उस क्षेत्र का विलय या अधिग्रहण वैध, कानूनी और स्थापित प्रतिमानों के अनुरूप न हो। इससे भी बड़ी बात यह है कि अधिकृत क्षेत्र की जनता अगर मुफलिसी का जीवन गुजर बसर कर रही हो, स्थानीय लोगों के विकास और कल्याण का कोई ढांचा नहीं हो तो अच्छे शासन की मांग के नाम पर विरोध के सुर मजबूत होने स्वाभाविक हैं। यही गुलाम कश्मीर के साथ हो रहा है और पाकिस्तान अपने हित के लिए इसका दोहन कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की अवांछित गतिविधियों का जवाब देने के लिए कश्मीर में जिस तरह से भारत की एनआइए नए तरीके से सक्रिय हुई है उससे भी पाकिस्तान को अपना खेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मनी लांड्रिंग, फेक करेंसी, विस्फोटकों की जब्ती, टेरर फंडिंग के मुद्दों पर एनआइए ने पिछले दो वर्षों में जिस तरह से कश्मीर में काम किया है और अलगाववादियों व भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ जिस तरह सख्ती से निपटा जा रहा है, उससे भी पाकिस्तान घबराया हुआ है।

अनेक कारणों से बढ़ रहा पाक का मनोबल

भारत ने जब से जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करते हुए प्रशासनिक तौर पर इस क्षेत्र का पुनर्गठन किया है तब से भारत के इस निर्णय के विरोध में वैश्विक ध्रुवीकरण करने को आतुर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मामले पर भारत को घेरने की पुरजोर कोशिश में है। गुलाम कश्मीर और खासकर गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में चुनाव की बात हो, प्रांतीय दर्जा देने की बात हो या फिर वहां पाक प्रधानमंत्री और अन्य प्रभावी लोगों की यात्राएं हों, इन सबको ईंधन और ताकत निम्न बातों से मिला है ।

पहला, आर्गेनाइजेशन आफ इस्लामिक कोआपरेशन की मीटिंग्स और डिक्लेरेशंस में अनुच्छेद 370 को हटाने के निर्णय की इस्लामिक देशों द्वारा आपत्ति से पाकिस्तान को बल मिला है। इसी से उत्साहित पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कश्मीर के मुद्दे को उठाने और इस पर समर्थन हासिल करने के लिए इस्लामाबाद में अगले साल मुस्लिम राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक की घोषणा की है। दूसरा, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे देशों और क्षेत्रीय संगठनों द्वारा कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए सर्टिफिकेट जारी करना। तीसरा, चीन द्वारा गलवन घाटी, फिंगर क्षेत्र और नाकुला क्षेत्र में जिस तरह भारत के विरुद्ध गतिविधियों को अंजाम दिया गया है, उससे भी पाकिस्तान का मनोबल गुलाम कश्मीर क्षेत्र को लेकर बढ़ा हुआ है। जब तक पाकिस्तान के मन में यह विश्वास बना रहेगा कि अनुच्छेद 370 और कश्मीर के अन्य मसलों पर दुनिया के देश उसके साथ हैं और भारत विरोध में उसके सुर में सुर मिलाएंगे, तब तक वह गुलाम कश्मीर में दुस्साहस करना जारी रखेगा।

चौथा, दुनिया के कई ग्लोबल थिंक टैंक भी लगातार कश्मीर में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इंटरनेट की पाबंदियों, मानवाधिकार उल्लंघन पर रिपोर्ट देने के लिए आतुर रहे हैं। ये संगठन यह सिद्ध करने पर भी तुले रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र सबसे कमजोर है, क्योंकि ये अपने अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव करता है। ऐसे ग्लोबल थिंक टैंक कश्मीर के लेह-लद्दाख-कारगिल में विकास की नई सार्थक पहलों, जिनसे स्थानीय जनसंख्या के जीवन में गुणात्मक बदलाव आ रहा है, उसकी रिपोर्टिंग करते नजर नहीं आते। कश्मीर मुद्दे पर भारत की आलोचना करने वाला कोई भी 'ग्लोबल इंडिपेंडेंट थिंक टैंक' यह रिपोर्टिंग नहीं करता कि पाकिस्तान भारत में महिलाओं के जरिये हथियारों और जाली मुद्रा की तस्करी कराता है। कश्मीर की स्थानीय जनता खासकर वहां की महिलाओं के मन में सुरक्षा भाव भरने के लिए भारत सरकार, भारतीय सेना ने कश्मीर में 'राइफल वूमेन' के रूप में महिला सैन्य बल को वहां तैनात किया है जिसके सार्थक परिणाम नजर आए हैं। वहीं लद्दाख में उच्च शिक्षा को गति देने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी मिल गई है।

पांचवां, जबसे भारत के सत्ताधारी दल ने कश्मीर में गुलाम कश्मीर क्षेत्र के परिसीमन की मांग पर विचार करना शुरू किया है, तब से पाकिस्तान को इस बात का खौफ सता रहा है कि कश्मीर में उसके रेफरेंडम (जनमत संग्रह) कराने के लिए बनाई गई कुत्सित चालों का क्या होगा। उपरोक्त तमाम तथ्यों का आकलन करते हुए पाकिस्तान निरंतर गुलाम कश्मीर में चुनाव और जनमत संग्रह कराने का राग अलापता रहा है। भारत द्वारा पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने के प्रयासों से भी वह पूरी तरह से बौखलाया हुआ प्रतीत होता है।

खरी-खरी

चलो रे डोली उठाओ कहार...

डा. पिलकेंद्र अरोरा

देवता गण शयन में जा चुके हैं। शहनाइयां थम गई हैं, मगर फिर भी फिल्मी गीत- चलो रे डोली उठाओ कहार... लगातार मेरा पीछा कर रहा है। यूं गीत अप्रासंगिक है, क्योंकि अब न डोली है, न कहार, केवल दुल्हन है जो पिया मिलन की ऋतु में किसी ज्ञात वाहन में बैठ ससुराल जाती है। पर सच तो यह है कि आज भी डोलियां हैं, कहार हैं, बस उनके अर्थ बदल गए हैं! क्या धर्म! क्या राजनीति! क्या साहित्य! सर्वत्र आज भी कहार हैं, जो डोलियां उठा रहे हैं और जिन पर चढ़ दुल्हनें ससुराल जा रही हैं।

मिलिए, परमानंद से। बचपन से भैयाजी की सेवा में हैं। पार्टी की पर्चियां काट रहे हैं। हालांकि वे पूरी तरह से एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। वे कार्य कर रहे हैं और भैयाजी कर्ता बन रहे हैं। भैयाजी, राजधानी पहुंच रहे हैं। भैयाजी, शपथ ग्रहण कर रहे हैं। भैयाजी, सत्तानंद प्राप्त कर रहे हैं, पर परमानंद अभी तक भैयाजी की डोली ही उठा रहे हैं। उनका पूरा जीवन नारे लगाने, डंडे-झंडे उठाने और बैनर-पोस्टर टांगने में टंग रहा है।

और अब ध्यान से देखिए साहित्य के संगीन क्षेत्र को! गुरु के संग्रह पर संग्रह विमोचित हो रहे हैं और वे कार्ड ही बांट रहे हैं। गुरु, जुगाड़ से पुरस्कार कबाड़ कर नोट गिन रहे हैं, जबकि वे बेचारे बरसों से प्रेसनोट ही बना रहे हैं। गुरु के अभिनंदन समारोह हो रहे हैं और वे अभिनंदन पत्रों और ग्रंथों का बोझा ढो रहे हैं। गुरु के सम्मान में पत्र-पत्रिकाएं-पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन वे हैं कि बेचारे बधाइयां ही गा रहे हैं। गुरु, सेमिनारों-फेस्टिवलों में पत्र-पुष्प से पुष्पित हो रहे हैं, और वे ही कि उनकी अटैची बन अटैची उठाए चले जा रहे हैं। जहां एक ओर गुरु, कार्यक्रम में अध्यक्षीय भाषण दे रहे हैं, वहीं वे अब तक बात-बेबात तालियां ठोक रहे हैं। गुरु, यू-ट्यूब पर लाइव हो रहे हैं और वे वहां बस वाह-वाह चेप रहे हैं। गुरु फेसबुक पर अपनी खांसी-डकार तक पोस्ट कर रहे हैं और वे उसे भी लाइक, कमेंट और शेयर कर रहे हैं। गुरु, पद्मश्री के लिए साम, दाम, दंड, भेद एक कर रहे हैं और वे बिना दाम के उनकी चम्पी ही कर रहे हैं। गुरु, राज्यसभा में पहुंच रहे हैं यानी दुल्हन ससुराल पहुंच रही है और वे कहार बन डोली ही उठाते रह गए हैं।

ट्वीट-ट्वीट

राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ही भाजपा का स्वाभाविक विकल्प है। इसलिए कांग्रेस के नेता को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। क्षेत्रीय दलों की अगुआई में लड़कर नरेंद्र मोदी को परास्त नहीं किया जा सकता।
आचार्य प्रमोद@AcharyaPramodk



आखिरकार सच्चाई सामने आ गई कि दानिश सिद्दीकी की मौत किसी संघर्ष में नहीं हुई। असल में उनकी निर्मम हत्या की गई थी। उन्हें घसीटा गया, 20 गोलियां मारी गईं और फिर शरीर को विक्षत किया गया, क्योंकि वह एक भारतीय थे। उनकी मुस्लिम पहचान के भी कोई मायने न रहे। इसके बावजूद कुछ लोग यही कहेंगे कि उनकी हत्या तालिबान ने नहीं की, बल्कि वह युद्ध की भेंट चढ़ गए।
सुशांत सरीन@sushantsareen

दानिश सिद्दीकी की हत्या एक भारतीय होने के कारण ही की गई। याद रखिए कि यह मायने नहीं रखता कि भारत में आप कौन हैं, लेकिन देश से बाहर निकलते ही आपकी केवल भारतीय के रूप में एक ही पहचान शेष रह जाती है। इसलिए भारत के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करते हुए एहतियात बरतें। सिद्दीकी की मौत हम सबके लिए एक सबक है। साजिद यूसुफ@TheSkandar

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के बाद अब ओलिंपिक देखकर लग रहा है कि बेटी को खिलाओ। भारत की बेटियां शानदार खेल दिखा रही हैं। बेटे भी कुछ कर दिखाएं।
नवीन कपूर@IamNaveenKapoor

बिहार डायरी



आलोक मिश्रा
स्थानीय संपादक, बिहार

यहां तलाशने नहीं पड़ते राजनीतिक मुद्दे

यह बिहार की राजनीति की खासियत है कि जब कुछ न हो रहा हो तो भी राजनीति पकती रहती है। यहां हर पल राजनीति के लिए कोई न कोई मुद्दा मिल ही जाता है। कभी कभी तो एक साथ इतने मुद्दे मिल जाते हैं कि राजनीतिक दलों के सामने चयन का संकट उत्पन्न हो जाता है। इस समय जातीय जनगणना, सरकार के सहयोगी मुकेश सहनी की यूपी की राजनीति, नीतीश की चौटाला से संभावित मुलाकात जैसे मुद्दे राजनीतिक गलियारे में गर्मी पैदा किए हुए हैं।

अभी कुछ दिन पहले तक जातीय जनगणना की दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी। अचानक लोकसभा में केंद्र सरकार के एक मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जातीय जनगणना की कोई योजना नहीं है। देशभर में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन बिहार की राजनीति ने अगले ही दिन इसे लपक लिया। अब पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। सबसे पहले राजद ने इसे उठाया। फिर समर्थन में धुर विरोधी जदयू ने भी देरी नहीं की। उपेंद्र कुशवाहा, केसी त्यागी बोल ही रहे थे, तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मांग कर दी कि केंद्र जातीय जनगणना के लिए दोबारा सोचे। नीतीश की मांग पर अब तक केंद्र सरकार की कोई टिप्पणी नहीं आई है। लेकिन राजनीति चल पड़ी है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने प्रस्ताव दिया है कि नीतीश की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिले। उनसे जातीय जनगणना का आग्रह करे। तेजस्वी के इस प्रस्ताव के बाद शुक्रवार को विपक्ष ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री विपक्ष के साथ हैं और सहयोगी भाजपा चुप्पी साधे इसे देख रही है। चूंकि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से इस तरह की मांग दो बार सर्वसम्मति से की गई है, जिसे दोनों बार केंद्र सरकार को भेजा भी गया। इसलिए नीतीश पीछे भी नहीं हट सकते। वे सोमवार को इसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखने जा रहे हैं।



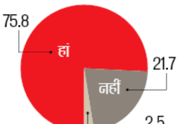
जातिगत जनगणना के मुद्दे पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र सौंपते तेजस्वी यादव सहित विपक्षी दलों के नेता। आइपीआरडी

असल में मंडल की धारा से निकली राजनीतिक पार्टियां जातीय जनगणना में संभावना देख रही हैं। उन्हें लग रहा है कि राम मंदिर निर्माण आंदोलन के चलते मंडल की राजनीति में आए बिखराव को फिर एक बार पुराने माडल पर लाने में इससे मदद मिलेगी। यह हो पाएगा या नहीं इसके बारे में फिलहाल कोई राय नहीं बनाई जा सकती है, फिर भी इन दलों के लिए यह मुद्दा अर्थहीन नहीं है। इसमें उन्हें लंबी लड़ाई की गुंजाइश दिख रही है। राजनीतिक दल नए सिरे से गोलबंदी की संभावना देख रहे हैं। ऐसी ही संभावना तलाशने बिहार विधानसभा चुनाव में चार सीटें लाकर राज्य सरकार में भागीदार वीआइपी (विकासशील इंसान पार्टी) के अध्यक्ष मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश चुनाव पर निगाहें लगा बैठे हैं। उन्होंने निषाद वोटों की गोलबंदी के लिए फूलनदेवी की प्रतिमा लगवाने की घोषणा कर दी। हालांकि लगने से पहले ही उनकी सारी मूर्तियां प्रशासन ने जब्त कर लीं और मंत्री मुकेश सहनी को वाराणसी हवाई अड्डे पर ही रोक कर कोलकाता रवाना कर दिया। इससे वे बहुत खिसियाए हुए हैं। इतने खिसियाए कि एनडीए विधायक दल की बैठक में भी अपनी टीम सहित शामिल नहीं हुए। वे एनडीए में उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं और मंत्री पद भी नहीं छोड़ना चाहते। दरअसल उनका प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखा भाजपा से गठबंधन कर कुछ सीटें हासिल कर पाएं। फिलहाल भाजपा भाव देती नहीं दिख रही।

नीतीश कुमार शुक्रवार को मानसून सत्र समाप्त होते ही दिल्ली रवाना हो गए। उनकी दो दिन की संक्षिप्त यात्रा में मुद्दा टटोलने की कोशिश शुरू हो गई है। असल में शनिवार को दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें यह माना जा रहा है कि केंद्र में मंत्री बनने के कारण वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नए अध्यक्ष की घोषणा होगी। सुगबुगाहट थी कि हाल ही में पार्टी में आए उपेंद्र कुशवाहा इस पद पर बैठ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारे में अब इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि चौंकाने वाले निर्णयों के लिए जाने जाने वाले नीतीश कहीं स्वयं न राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं। चूंकि नीतीश ने एक व्यक्ति एक पद के आधार पर विधानसभा चुनाव से पहले स्वयं यह पद छोड़ा था और आरसीपी को उत्तराधिकारी बनाया था, लिहाजा दोबारा उनकी ताजपोशी पर सवाल खड़े हो सकते हैं, इसलिए आगामी व्यवस्था होने तक का हवाला देकर ऐसा किया जा सकता है। यही नहीं, उसके बाद रविवार को उनकी मुलाकात ओमप्रकाश चौटाला के साथ भी है। मुलाकात भले ही चौटाला की सेहत का हाल लेने को लेकर बताई जा रही हो, लेकिन जातीय जनगणना जैसे मुद्दे पर मुखर नीतीश की इस मुलाकात को लेकर भाजपा के कान खड़े हो गए हैं। अगर नीतीश अध्यक्ष बनते हैं तो इस मुलाकात के अर्थ पर सभी की निगाहें रहेंगी।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या लोकसभा में पर्चे उड़ाने वाले सांसदों को निलंबित किया जाना चाहिए था?



सभी आकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या पेगासस जासूसी मामले पर संसद में चर्चा आवश्यक है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

सोचो कैसा चल रहा खतरनाक यह खेल,
पांच-पांच बच्चे जनो कर दो रेलमपेल।
कर दो रेलमपेल पैक हो जाए सीमा,
जहर दे रहे चर्च इस तरह धीमा-धीमा।
मिशनरियों का खेल- चलो भारत को नोचो,
इनकी गंदी चाल रोकने हित कुछ सोचो।
- ओमप्रकाश तिवारी

मंथन



रजित मेहता
एमडी व सीईओ, अंतारा

संक्रमण रोकने की साझा पहल

कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना सरकारों के लिए नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है

जब हम समय की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हैं तो कभी-कभी हमारे पास पूरे दम-खम से उस चुनौती का सामना करने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं होता है। किसी भी कीमत पर लड़ना और जीतना ही एकमात्र विकल्प होता है। कोविड महामारी के खिलाफ युद्ध के दौरान भारत भी इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहा है। कोविड के खिलाफ भारत द्वारा अपनाई गई रणनीति ने चाहे बेहतर परिणाम दिए हों, लेकिन वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट अभी भी बरकरार है।

देश का टीकाकरण कार्यक्रम अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कोविड के लिए वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह द्वारा शुरू की गई रणनीति इस प्रतिबद्धता के अनुरूप है। टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके बाद वरिष्ठ नागरिक और 45 वर्ष से ऊपर के वे लोग थे जो कुछ खास बीमारियों से पीड़ित थे। सरकार की वैक्सीन नीति ने लचीलापन दिखाते हुए इसमें निरंतर सामयिक बदलाव किया है।

केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क और बुनियादी ढांचे के माध्यम से टीकाकरण अभियान की शुरूआत की, जिसमें निजी स्वास्थ्य सेवा को शामिल करना इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने की दिशा में एक तार्किक कदम था। हालांकि अल्पावधि में, हमें अभी भी वैक्सीन के प्रति झिझक को कम करने की आवश्यकता है, जो टीकाकरण के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करने वाली एक विकट समस्या के रूप में सामने आई है। टीकाकरण के प्रति झिझक और प्रौद्योगिकी ने शुरू से ही भारत के टीकाकरण अभियान को झटके दिए हैं। टीकों का इतिहास उनके दुष्प्रभावों या एक नए टीके की अक्षमता पर भय और संदेह की कहानियों से भरा हुआ है। कोविड टीकों के मामले में भी अनुभव कुछ अलग नहीं है। यह सच है कि सामान्य समय में वैक्सीन के विकास और उपयोग के लिए तैयार होने में लगभग एक दशक का समय लगता है, जबकि कोरोनावायरस के टीके एक साल से भी कम समय में आ गए हैं। यह किसी चिकित्सीय चमत्कार से कम नहीं है।



सभी तक आसानी से पहुंचे कोरोना रोधी टीका। इंटरनेट मीडिया

यदि हमें वांछित दैनिक टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है तो टीके से जुड़ी हिचकिचाहट को दूर करना होगा। अस्पताल और सरकारें टीकाकरण के बाद होने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाओं (एडवर्स इफेक्ट फालोइंग इम्युनाइजेशन) के बारे में लोगों को जागरूक कर सकती हैं। टीकाकरण के बाद होने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाओं के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देशों की एक रूपरेखा और लागू करने के लिए एक प्राधिकरण, टीके के संबंध में झिझक पर काबू पाने की दिशा में हमारे प्रयासों को मजबूत करेगा। इतना ही नहीं, कोविड टीकों के बारे में मिथकों और आशंकाओं को कम करने के लिए एक खुला और अनुकूल दृष्टिकोण आवश्यक है। यह सही है कि टीके के लाभों को नकारा नहीं जा सकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि टीके की दोनों खुराक लेने के बाद 10 हजार में से केवल दो से चार लोग ही संक्रमित पाए गए। इन दिनों चिंता इसलिए बढ़ गई है कि इस वारयस के नए स्ट्रेन (प्रारूप) सामने आ रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन सुरक्षा पाने और टीकाकरण के बाद भी सैनिटाइजेशन और मास्क लगाए रखना जरूरी है।

यह सही है कि आपातकालीन उपयोग के लिए स्वीकृत होने से पहले कोरोना टीके ने सभी सुरक्षा मानदंडों को पूरा किया है और प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया है। कुछ सामान्य लक्षण जैसे हल्का बुखार, कमजोरी या सिरदर्द अन्य टीकों के भी लक्षण हैं। लिहाजा केवल कमजोर प्रतिरक्षा वाले या किसी भी टीके से पहले से एलर्जी की प्रतिक्रिया वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

वैक्सीन अभियान में व्यवधान : खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी और को-विन प्रणाली में गड़बड़ियां देश में टीकाकरण अभियान में शुरुआती धीमी गति के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, पूरी तरह से तकनीक पर आधारित होने के कारण भी इसकी राह में बाधाएं आई थीं। भारत में बुजुर्ग आबादी के लिए बुनियादी ढांचे की व्यापक कमी है। इसमें हमारे स्वास्थ्य देखभाल स्थल भी शामिल हैं। टीका लेने के लिए स्वयं को रजिस्टर करने और टीका लग जाने के बाद उसका प्रमाणपत्र हासिल करने जैसे काम पूरी तरह से डिजिटल होने से वैसे तो अधिकांश लोगों को सुविधा ही हुई है कि वे यह काम आसानी से घर बैठे या कामन सर्विस सेंटर आदि के जरिये कर रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों को अवश्य दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

वैक्सीनेशन केंद्र पर आन-द-स्पाट पंजीकरण का बड़ा जोखिम भीड़भाड़ और कोविड मानदंडों का पालन नहीं होने से जुड़ा है। ऐसे में अस्पतालों को भीड़ प्रबंधन के लिए कुछ अन्य व्यावहारिक उपायों के बारे में भी सोचना चाहिए। इसके लिए बड़े केंद्रों में ज्यादा भीड़ लगाने के बजाय लोगों को छोटे अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दोनों खुराकें लेने के बावजूद सावधानियों को कम नहीं करना चाहिए। टीकाकरण संक्रमण के प्रभाव को कम कर सकता है, लेकिन वैक्सीन ले चुका व्यक्ति भी कोरोनावायरस का वाहक बन सकता है और दूसरों को संक्रमित कर सकता है।

406 बाघ हैं उत्तराखंड में। संख्या के लिहाज से देश में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। बाघों की मौजूदगी 14 हजार फीट की ऊंचाई तक मिली है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 31 जुलाई, 2021

उत्तराखंड

स्थानीय निवासियों को रोजगार

प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय निवासियों को 70 फीसद रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर कवायद शुरू हुई है। विभागीय मंत्री ने 10 दिनों के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है। यह एक अच्छा कदम कहा जा सकता है, बशर्ते इस पर गंभीरता से काम हो। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब उद्योगों में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने की बात कही गई है। वर्ष 2006 में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश के सभी उद्योगों में 70 फीसद रोजगार स्थानीय निवासियों को ही देने के लिए नीति बनाई थी। व्यवस्था बनाई गई कि जो उद्योग इस मानक को पूरा नहीं करेगा, उससे सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। प्रदेश में उद्योगों को इस दौरान कई तरह की सुविधाएं मिल रही थीं, तो उन्होंने भी सरकार के आदेशों को गंभीरता से लिया। स्थानीय निवासियों को रोजगार मिला। नए उद्योगों में व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बाकायदा विभाग की तरफ से इसकी समय-समय पर जांच भी की गई। धीरे-धीरे यह व्यवस्था पटरी से उतरने लगी। प्रदेश में कई नए उद्योग स्थापित हुए, लेकिन इसका लाभ स्थानीय निवासियों को नहीं मिला। कई समीक्षा बैठकों में भी यह बात उठी। इनमें तकनीकी विशेषज्ञता का मसला उठाते हुए उद्यमी स्थानीय निवासियों को रोजगार देने से कदम पीछे खींचते रहे।

कोरोना के कारण घर लौटे प्रवासी रोजगार की तलाश में हैं। उद्योगों में स्थानीय निवासियों के संबंध में तय व्यवस्था को सख्ती से लागू कराकर इन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सकता है

यह बात सही है कि स्थानीय के नाम पर योग्यता से समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां समझने की बात यह है कि ऐसे पद सीमित होते हैं। ऐसे में 70 फीसद रोजगार की व्यवस्था को लागू कराने में शासन-प्रशासन तो विफल रहा ही, साथ ही सरकारों ने भी इसमें कोई खास रुचि नहीं दिखाई। सरकारें यदि इस मामले में गंभीर रहतीं तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी इन उद्योगों के जरिये रोजगार पा गए होते। उन्हें रोजगार की तलाश में प्रदेश से बाहर पलायन न करना पड़ता। बहरहाल, देर आए दुरुस्त आए। जिस तरह अब सरकार इस ओर गंभीरता दिखा रही है, उससे उद्योगों में स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलने की उम्मीद जग रही है। कोरोना संक्रमण के कारण अन्य राज्यों से घर वापस आए प्रवासियों को रोजगार दिलाने की दिशा में यह अहम कदम हो सकता है। सरकार को चाहिए कि वह इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में स्थापित सभी उद्योगों में स्थानीय कर्मचारियों के आंकड़े ले और फिर इन उद्योगों में स्थानीय निवासियों को रोजगार दिलाया जाए।

झारखंड

शिक्षा की गुणवत्ता

झारखंड एकेडमिक काउंसिल की दसवीं एवं बारहवीं का परिणाम काफी बेहतर रहा है। दसवीं में जहां लगभग 96 प्रतिशत विद्यार्थी सफल घोषित हुए हैं, वहीं इंटरमीडिएट विज्ञान में लगभग 87 प्रतिशत, वाणिज्य में 90 प्रतिशत तथा कला में 91 प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए हैं। इतनी संख्या में विद्यार्थियों का परीक्षा में सफल होना सुखद है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की राह निर्धारित करती है। लेकिन यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस वर्ष कोरोना के कारण परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई थीं और पिछली परीक्षाओं में प्राप्त अंकों तथा प्रायोगिक परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम जारी किया गया। राज्य सरकार के पास इस आधार पर परिणाम जारी करने के अलावा अन्य कोई विकल्प भी नहीं था। यह सभी जानते हैं कि नौवीं की परीक्षा संबंधित स्कूलों में ही होती है तथा स्कूल के शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हैं। भले ही जैक द्वारा प्रश्नपत्र भेजे जाते हैं, लेकिन कई स्कूलों में परीक्षा के नाम पर खानापूर्ति ही होती है। यह भी

दसवीं और बारहवीं में पास तो हो गए, लेकिन पूरी पढ़ाई नहीं होने और बिना परीक्षा अच्छे नतीजे आने से आशंका है कि अगली कक्षाओं के परिणाम न प्रभावित हों


छात्रों की पढ़ाई-लिखाई निर्बाध रूप से रहे जारी। फाइल

सही है कि स्कूल अधिसंख्य बच्चों को अधिक अंक देकर दसवीं में प्रोन्नत कर देते हैं। लगभग ऐसी ही स्थिति इंटरमीडिएट के परिणाम में भी लागू होती है।

ऐसे में दसवीं तथा बारहवीं में सफल होने के बाद भी विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर चिंता वाजिब है। कोरोना के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई भी पूरी तरह बाधित हुई है। भले ही बाद में स्कूल, कालेज खुले हों, लेकिन विद्यार्थियों की उपस्थिति काफी कम ही रही है।

पूरी पढ़ाई नहीं होने तथा बिना परीक्षा परिणाम जारी होने का प्रभाव अगली कक्षाओं के परिणाम पर भी पड़ सकता है। मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी पर भी इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि विद्यार्थी पिछली कक्षाओं में छूटी हुई भरपाई करें। इसमें संबंधित स्कूल व कालेजों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्हें इस आधार पर कक्षाएं तय करनी होगी जिससे पिछली कक्षाओं के विषयों की भी पढ़ाई कराई जा सके। विद्यार्थियों को भी अगली कक्षाओं में अधिक मेहनत करनी होगी। कोरोना संक्रमण के बावजूद किस तरह विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसपर मंथन कर आवश्यक निर्णय लेना होगा। उम्मीद है कि राज्य सरकार इन सभी पहलुओं पर विचार कर आवश्यक निर्णय लेगी।

उत्तर प्रदेश

एंबुलेंस की हड़ताल

उत्तर प्रदेश में एंबुलेंस चालकों, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (ईएमटी) समेत करीब 22 हजार कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। इन संविदा कर्मचारियों की कुछ मांगें जायज हो सकती हैं लेकिन, जिस तरह वे हठधर्मिता दिखा रहे हैं, उसे उचित नहीं कहा जा सकता है। आखिर उन्हीं की हड़ताल के कारण कई जिलों में मरीजों को समय से इलाज नहीं मिला और कुछ की मौत तक हो गई। रविवार रात से हड़ताल में शामिल 711 कर्मचारियों को कंपनी बर्खास्त कर चुकी है। इन्हीं लोगों के कारण एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम (एएलएस), 108 व 102 एंबुलेंस सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है। तमाम कोशिशों के बावजूद पूर्वांचल के 18 जिलों में एक भी एंबुलेंस अभी तक नहीं दौड़ सकी है। इस बीच 22 जिलों में शत प्रतिशत और 35 जिलों में 50 प्रतिशत तक एंबुलेंस सेवा बहाल होने के दावे जरूर किए जा रहे हैं।

कोरोना की तीसरी लहर की आहट के पहले एंबुलेंस जैसी आपात सेवाओं का ठप हो जाना


जीवन रक्षक व्यवस्थाओं का सुनिश्चित हो संचालन। फाइल

चिंताजनक है। यद्यपि एंबुलेंस सेवा का संचालन देख रही कंपनी जीवीकेईएमआरआइ के अल्टीमेटम के बाद गुरुवार शाम तक कुछ स्थिति सुधरी है लेकिन, हालात अभी सामान्य नहीं हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को देखना चाहिए कि आखिर एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एंबुलेंस सेवा प्रदान करने वाली कंपनी बदलने मात्र से कर्मचारी इतने उद्वेलित क्यों हो उठे। अधिकारी हड़ताल की आहट को पहले क्यों नहीं भांप सके। जांच होनी चाहिए कि जिस

सरकार को एंबुलेंस चालकों और मेडिकल टेक्नीशियन पर सख्ती दिखाते हुए नई भर्ती में और तेजी लानी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं फिर पटरी पर लौट सकें

जिगित्सा हेल्थ केयर को एंबुलेंस संचालन का जिम्मा हाल में सौंपा गया है, उसने प्रशिक्षण के नाम पर 20 हजार रुपये क्यों मांगे। उन्हें क्या सिखाना था, जिसे वे अभी तक नहीं जानते हैं। मानदेय भी पहले के मुकाबले क्यों घटाया गया। यहीं जवाब मिलेगा कि 250 एएलएस एंबुलेंस से जुड़े एक हजार कर्मचारियों के हड़ताल पर जाते ही अन्य एंबुलेंस सेवाओं के कुल 22 हजार कर्मचारियों का साथ कैसे मिल गया। बहरहाल, सरकार को हड़ताली एंबुलेंस चालकों और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन पर सख्ती दिखाते हुए नई भर्ती में और तेजी लानी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं फिर पटरी पर लौट सकें।

पंजाब

महत्व देने की मजबूरी

पंजाब में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे राजनीतिक दलों का रुझान इस बार अनुसूचित जाति की ओर बढ़ता जा रहा है। पहले सभी दलों ने यह एलान किया कि वे सत्ता में आए तो सरकार में शीर्ष पदों पर अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व देंगे। अकाली दल के बाद कांग्रेस ने भी यह एलान किया कि वह सत्ता में आई तो अनुसूचित जाति के विधायक को उप मुख्यमंत्री बनाएगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने तो मुख्यमंत्री का पद ही अनुसूचित जाति को देने का वादा किया है।

अब कांग्रेस सरकार ने भी अनुसूचित जाति कल्याण अध्यादेश लाने का फैसला करके पंजाब के इस बड़े वर्ग के आमजन के हित की बात की है। उम्मीद यही है कि यह अध्यादेश सरकार आगामी सत्र में ले आएगी और इस पर सर्वसम्मति भी बन जाएगी, क्योंकि कोई भी इस पर आपत्ति या विरोध जताकर इस वर्ग को नाराज नहीं करना चाहेगा। यह अध्यादेश पारित होकर कानून बन जाता है तो प्रदेश सरकार के वार्षिक बजट में अनुसूचित जातियों की आबादी के अनुपात में उनके कल्याण के लिए बजट का प्रविधान हो जाएगा। ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पर पंजाब की बड़ी आबादी को फायदा होगा। हालांकि अभी यह तय होना है कि सरकार कैसी कल्याण योजनाएं या कार्ययोजना इनकी भलाई के लिए बनाती है और उनका क्रियान्वयन कैसे होता है। इधर गुरुवार को सरकार ने यह बड़ा एलान किया, उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति के विधायकों की बैठक बुलाकर उनके मसलों पर चर्चा करके यह जता दिया कि संगठन भी उनकी चिंता करता है। यह माना जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हैं तो अनुसूचित जाति से एक मंत्री बनाने का दबाव उन पर रहेगा। इस तरह कांग्रेस के भीतर के भी दोनों ध्रुव अपने-अपने स्तर पर अनुसूचित जाति को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। राज्य में अनुसूचित जातियों की आबादी देश में सबसे ज्यादा 31.94 फीसद है। विधानसभा में 117 में से 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यानी यह वर्ग जिस भी ओर हुआ, उसकी सरकार बनना आसान होता है। मौजूदा समय में कांग्रेस के 23 विधायक अनुसूचित जातियों से हैं हालांकि उस अनुपात में मंत्री कम हैं। बोर्डों-निगमों के चेयरमैन पदों पर भी इन जातियों से कम नियुक्तियां होने की सुगबुगाहट होती रही है। अतः इस वर्ग की नाराजगी को दूर करना या आगामी सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का डंका पीटना सभी दलों की मजबूरी हो गया है। सत्ता का रास्ता शायद यहीं से गुजरता उन्हें प्रतीत होता है।

राज्य विधानसभा में 117 में से 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यानी सरकार गठन की भूमिका में इस वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है

प्रशिक्षु सैन्य अधिकारियों को ड्रोन तकनीक में दक्ष करेंगे आइआइटियंस

जागरण विशेष

आइआइटी के पूर्व छात्रों की संस्था यूनिसेड की पहल, इंडियन मिलिट्री अकादमी के साथ हुआ अहम करार

शशांक शेखर भारद्वाज • कानपुर

देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बनकर उभरे ड्रोन की तकनीक से सेना के प्रशिक्षु अधिकारी रूबरू होंगे। वह रोबोटिक्स, ड्रोन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत अन्य तकनीक में दक्ष होकर इनका संचालन और डिजाइनिंग करना सीखेंगे। उन्हें पारंगत करने का जिम्मा आइआइटियंस संभालेंगे। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) कानपुर के पूर्व छात्रों की संस्था यूनिट आफ साइंस एंड एजूकेशनल डेवलपमेंट (यूनिसेड) और इंडियन मिलिट्री अकादमी के बीच एक अहम करार हो चुका है। यह प्रशिक्षण आइआइटी कानपुर, दिल्ली, गुवाहाटी, रुड़की के विशेषज्ञ देंगे।

ड्रोन पर दी जाएगी सारी जानकारी: माहौल बिगाड़ने वाले अराजकतत्व और आतंकी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में आतंकी साजिश व हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया गया। इसको देखते हुए सेना में अहम जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार किए जा रहे जवानों के विशेष प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है। उन्हें ड्रोन के संचालन, उनको पहचानने और कार्यप्रणाली की जानकारी दी जाएगी। जवानों की मदद के लिए रोबोट भी तैयार किए जाएंगे। यह मेटल डिटेक्टर की तरह काम करके बारूदी सुरंग और अन्य तरह के बम को खोजने में मदद करेंगे। इंडियन मिलिट्री अकादमी में रोबोटिक्स और ड्रोन के लिए अत्याधुनिक लैब विकसित की जाएगी।

रेस्क्यू में काम आएगा रोबोट: रोबोट आपदा के समय राहत कार्यों में भी उपयोग किया जा सकेगा। तकनीक को जान कर प्रशिक्षु अपनी जरूरत के हिसाब से रोबोट बना सकेंगे। आइआइटी के विशेषज्ञ उन्हें पूरा प्रशिक्षण देंगे। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर मारक क्षमता में बढ़ोतरी कर सकेंगे। इससे रेस्क्यू के दौरान जल्द स्थिति संभालने में भी मदद मिलेगी।



यूनिसेड की लैब में तैयार ड्रोन • सौ. संस्थान

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान से जुड़ी है यूनिसेड

यूनिसेड आइआइटी के पूर्व छात्रों की संस्था है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पंजीकृत है। यह केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत कई आइआइटी से समन्वय के साथ काम करती है। इसके जरिए वह शोध के साथ तकनीकी प्रशिक्षण अभियान चलाती है। संस्था में नौ सदस्य हैं।


अवनीश त्रिपाठी

सरकारी व निजी संस्थानों से होगा करार

यूनिसेड के चीफ मेंटर अवनीश त्रिपाठी के मुताबिक इंडियन मिलिट्री अकादमी के प्रशिक्षु रोबोट व ड्रोन से जुड़ी तकनीक विकसित कर सकेंगे। उनके सहयोग के लिए कई सरकारी और निजी संस्थानों से करार किया जाएगा। प्रशिक्षु सर्विलांस और अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोटोटाइप विकसित कर सकेंगे।

"सेना के भावी अधिकारियों को अत्याधुनिक तकनीक का जल्द ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में वेबिनार पर भी चर्चा हुई है।
प्रो. हर्ष चतुर्वेदी, सेंटर फार एनर्जी हेड, आइआइटी गुवाहाटी


यूनिसेड की लैब • सौ संस्थान

इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

श्रद्धा का महासावन

शिव के गुणों को करें आत्मसात

सनातन मतावलंबियों के लिए सावन का महीना अत्यंत पवित्र है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। इसमें विधिपूर्वक शिवजी की आराधना करने से मनुष्य की मानसिक और शारीरिक विकृतियों का क्षय होता है, साथ ही उसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। सच्चे हृदय, भक्तिभाव से कोई भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र मिश्रित जल अर्पित करता है, उसकी हर कामना पूर्ण होती है। जहां सत्य है वहीं शिव हैं और जहां शिव हैं, वहां अनंत इच्छाओं की स्वतः पूर्ति हो जाती है। शिवपुराण के अनुसार गंभीर बीमारियों और मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र बहुत उपयोगी है। इस मंत्र के जप में इतनी शक्ति होती है कि मृत्यु के करीब पहुंच चुके व्यक्ति को जीवनदान मिल जाता है। व्यक्ति को शिव की तरह संस्कारी, त्यागी, अहंकारविहीन व दूसरों के कष्ट हरने का संकल्प लेने वाला होना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ के वशीभूत कभी न बनें। जीवन को सत्यम, शिवम, सुंदरम बनाना है तो जगद्गुरु शिव के स्वरूपों और गुणों को आत्मसात करना चाहिए। सावन के महीने में सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता होती है। भगवान शिव इस बात के भी प्रतीक हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी विसंगतियां हों, हमेशा सामान्य व्यवहार में ही मनुष्य को रहना चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना भी वैज्ञानिक आधार रखता है। महादेव ने जगत कल्याण के लिए विषपान किया था इसलिए दूध से उनका अभिषेक करने का विधान है। शिव की कृपा जीवन को सुखमय बनाती है। उनकी आराधना जरूर करनी चाहिए।


महंत नरेंद्र गिरि
अध्यक्ष, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, प्रयागराज

स्कैन करें और पढ़ें 'श्रावण मास' से संबंधित सभी सामग्री

रक्सौल में लगती है नोटों की मंडी, होता है लाखों का धंधा

विजय कुमार गिरि, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)

रक्सौल स्थित भारत-नेपाल सीमा पर मुद्रा विनिमय की वैध व्यवस्था नहीं होने से अवैध धंधा फल-फूल रहा है। यहां प्रतिदिन नोटों की मंडी लगती है। भारतीय और नेपाली नोटों के बदलने का खुलेआम अवैध धंधा होता है। कोरोना के कारण नेपाल की ओर से सीमा सील होने के बावजूद धंधे पर कोई असर नहीं है। इसमें दोनों देशों के लोग शामिल हैं।

रक्सौल सीमा पर करीब 70 अवैध मुद्रा विनिमय केंद्र हैं, जबकि 100 से अधिक लोग चलता-फिरता धंधा करते हैं। प्रतिदिन करीब 20 लाख का ट्रांजेक्शन होता है। इससे धंधेबाजों को डेढ़ लाख रुपये तक की कमाई होती है। धंधेबाज एक लाख नेपाली रुपये के बदले भारतीय करेंसी लेने पर पांच से सात हजार लेते हैं। इसके लिए किसी तरह के कागज की जरूरत नहीं, जबकि नेपाल में वैध रूप से अधिकतम 10 हजार रुपये बदलने की ही सुविधा है। कागजात भी देने पड़ते हैं। इस पर डेढ़ फीसद शुल्क लिया जाता है। अवैध रूप से भारतीय नोट बदलने पर धंधेबाज पांच फीसद लेते हैं। दिल्ली-काठमांडू को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर सुबह चार बजे नोटों की मंडी सज जाती है, जो रात नौ बजे तक चलती है। धंधेबाज छोटी-छोटी गुमटियों और पान, चाय व किराना दुकान की आड़ में नोट बदलने का काम करते हैं। बताया जाता है कि बड़े अधिकारियों के रक्सौल


रक्सौल सीमा पर काउंटर पर रखे नोटों के बंडल। जागरण

पहुंचने की सूचना धंधेबाजों तक पहले ही पहुंच जाती है। एक बड़े सिंडिकेट के माध्यम से धंधा चलता है। सफेदपोश लोगों के संरक्षण का भी इन्हें लाभ मिलता है।

यहां के धंधेबाज अवैध मुद्रा विनिमय केंद्र के अलावा हवाला कारोबार से भी जुड़े हैं। पिछले सात माह में सात करोड़ से अधिक कैश की बरामदगी हो चुकी है। एक दर्जन से अधिक भारतीय तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। स्थानीय थाने के प्रभारी शशिभूषण ठाकुर का कहना है कि अवैध विनिमय केंद्र के खिलाफ कार्रवाई होती है। पुलिस कार्रवाई की सूचना मिलते ही धंधेबाज नेपाल सीमा की ओर निकल जाते हैं। रक्सौल आव्रजन कार्यालय के प्रभारी अजय पंकज ने कहा कि यहां विदेशी मुद्रा परिवर्तन की किसी बैंक में सुविधा नहीं है। जरूरत पड़ने पर पटना से परिवर्तन कराया जाता है या फिर नेपाल में ही यह सुविधा मिलती। रक्सौल में मुद्रा परिवर्तन की सुविधा के लिए सरकार को पत्र लिखा है।

बस में हल की बेबस वृद्धा की पेंशन समस्या

राजीव शर्मा, आगरा

सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में आमतौर पर धारणा नकारात्मक ही होती है। फरियादियों को टरकाने के आरोप लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं, जो जिम्मेदारी से काम करने के साथ मानवीय दृष्टिकोण के चलते मिसाल बन जाते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उपनिदेशक विजय प्रताप यादव उनमें से ही एक हैं। वर्तमान में उन पर जिला समाज कल्याण अधिकारी का भी कार्यभार है। सिटी बस में सफर के दौरान ही यादव ने बेबस वृद्धा की पेंशन समस्या का समाधान कर दिया।

ईदगाह निवासी विजय प्रताप यादव गुरुवार सुबह सिटी बस से कार्यालय आ रहे थे। बस में उनकी बगल की सीट पर दो बुजुर्ग महिलाएं बैठी थीं। इनमें से नरीपुरा, भीमनगर निवासी शकुंतला की वृद्धावस्था पेंशन जनवरी, 2021 से रुकी हुई थी। दूसरी महिला पेंशन संबंधी आवेदन की प्रक्रिया जानने समाज कल्याण विभाग जा रही थी। कई चक्कर काटने के बाद भी दोनों महिलाओं की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। इससे आहत दोनों महिलाएं विभाग की उदासीनता को लेकर दर्द बयां कर रही थीं। उपनिदेशक ने शकुंतला से परेशानी का कारण पूछा, उन्होंने बताया कि दिसंबर, 2020 तक उन्हें पेंशन मिली थी, लेकिन जनवरी, 2021 से रुक गई है। उपनिदेशक ने वृद्धा के जरूरी दस्तावेज देखे, उन्हें स्कैन कर मोबाइल फोन से कार्यालय के संबंधित कर्मचारी को भेज दिया। दोनों महिलाओं के साथ जब तक वह कार्यालय पहुंचे, तब तक कर्मचारी पूरी जानकारी एकत्र कर चुका था। महिला का जिस बैंक में खाता था, वह पीएनबी में मर्ज हो गया था। इससे महिला का खाता लिंक नहीं हो पा रहा था, लिहाजा पेंशन रुक गई। उपनिदेशक ने तत्काल महिला का खाता अपडेट कराया, उनका कहना है कि अगले महीने से वृद्धा को पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। दूसरी वृद्धा को भी पेंशन संबंधी जानकारी दे दी गई। यादव का कहना है कि विभागीय वाहन उपलब्ध न होने के कारण वह सिटी बस या आटो से ही दफ्तर आते-जाते हैं। समाज कल्याण अधिकारी परितोष श्रीवास्तव के अवकाश पर होने के कारण उपनिदेशक, अल्पसंख्यक के पास ही उनका कार्यभार है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए भटक रहे सुंदरलाल बहुगुणा के स्वजन

जागरण संवाददाता, देहरादून

विश्वविख्यात चिपको आंदोलन के प्रणेता और प्रख्यात पर्यावरणविद् पद्मविभूषण सुंदरलाल बहुगुणा के स्वजन उन्हें मिलने वाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन हस्तांतरित कराने के लिए भटक रहे हैं। यह पेंशन उनकी पत्नी विमला बहुगुणा को हस्तांतरित होनी है।

स्व. बहुगुणा के पुत्र राजीव नयन बहुगुणा ने आरोप लगाया कि देहरादून के मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय ने पेंशन आवेदन के दस्तावेज ही खो दिए। अब अधिकारी उनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। सरकारी मशीनरी की उपेक्षा से खिन्न राजीव ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। दूसरी ओर देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने कहा कि मामले में मुख्य कोषाधिकारी से जवाब मांगा गया है।

पर्यावरण संरक्षण के पुरोधा सुंदरलाल बहुगुणा ने केवल स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई, बल्कि जीवनपर्यंत सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी संघर्ष करते रहे। इसी वर्ष 21 मई को उनका निधन हो गया। सिस्टम की बेरुखी से आहत राजीव नयन बहुगुणा का आरोप है कि मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय की लापरवाही से पेंशन के दस्तावेज गुम हुए हैं और अब अधिकारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। यहां तक कि दोबारा दस्तावेज जमा करने पर भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव (गृह) आनंद वर्धन ने बताया कि यह मामला संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका जल्द निस्तारण कराया जाएगा।

कम हो रहा इंजीनियरिंग का क्रेज, कालेजों में भर नहीं रहीं सीटें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कालेजों ने पिछले तीन साल में 5.5 लाख सीटें लौटाईं, अब सिर्फ 23 लाख सीटें बचीं
- 2014 में इंजीनियरिंग सीटों की कुल संख्या थी 32 लाख, सात साल में सबसे ज्यादा घटी सीटें

युवाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का क्रेज लगातार कम होता दिख रहा है। इसका अंदाजा इंजीनियरिंग की सीटों में पिछले कुछ सालों से लगातार हो रही कमी से भी लगाया जा सकता है। पिछले सात सालों में सबसे ज्यादा सीटें कम हुई हैं। इस साल भी तकनीकी संस्थानों में इंजीनियरिंग के विभिन्न कोर्स की करीब डेढ़ लाख सीटें कम हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014-15 में तकनीकी संस्थानों में इंजीनियरिंग के सभी कोर्सों में कुल सीटों की संख्या 32 लाख थी जो अब घटकर सिर्फ 23 लाख रह गई हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) के मुताबिक दाखिले में कमी के चलते तकनीकी संस्थान सीटों को लगातार वापस कर रहे हैं। इस साल भी 1.46 लाख सीटें वापस की गई हैं। इनमें सरकारी व निजी इंजीनियरिंग संस्थान दोनों ही शामिल हैं। शैक्षणिक सत्र वर्ष 2021-22 में सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों ने सबसे ज्यादा 1.20 लाख सीटें वापस की हैं। वहीं निजी कालेजों ने करीब 14 हजार सीटें वापस की हैं।

शिक्षा मंत्रालय की ओर से संसद को दी गई एक जानकारी में बताया गया है, कि पिछले तीन साल में साढ़े पांच लाख से ज्यादा सीटें वापस की गई हैं। इस बीच एआइसीटीई ने करीब एक लाख सीटें रद्द भी की हैं, क्योंकि कई सालों से इन सीटों के खाली होने के बाद भी संस्थान इन्हें वापस नहीं कर रहे थे। दरअसल सीटों की संख्या के हिसाब से संस्थानों को फैकल्टी का प्रबंध करना होता है।

नए इंजीनियरिंग कालेज खोलने पर रोक

इस बीच इंजीनियरिंग कालेजों के लगातार बंद होने और सीटों को वापस करने की होड़ को देखते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने वर्ष 2022 तक नए इंजीनियरिंग कालेजों को नहीं खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि इससे देश के अति पिछड़े जिलों को छूट दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सात सालों में देश के करीब 400 इंजीनियरिंग कालेज बंद हुए हैं। बावजूद इसके परिषद ने जो योजना बनाई है, उसके तहत नए इंजीनियरिंग कालेजों को खोलने व किसी भी कोर्सों की शुरू करने की अनुमति उनकी स्थानीय मांग को देखते हुए दी जाएगी।

2019 में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद चीन में फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। राजधानी बीजिंग समेत 15 और शहरों में अचानक बढ़े डेल्टा वैरिएंट के मामले बढ़ने लगे हैं।

आज फिर होगी भारत-चीन के सैन्य कमांडरों की वार्ता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- साढ़े तीन माह बाद होने वाली वार्ता में गोगरा, हाट स्प्रिंग का मुद्दा उठाएगा भारत
- वादे के बावजूद सेना को मई 2020 से पहले वाली स्थिति पर नहीं ले गया है चीन

भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडर शनिवार को वार्ता के लिए फिर आमने-सामने होंगे। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा का चीनी सेना द्वारा उल्लंघन करने के बाद यह दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच होने वाली 12वें दौर की वार्ता है। वैसे इसे लेकर माहौल बहुत सकारात्मक नहीं है, लेकिन भारत की तरफ से गोगरा व हाट स्प्रिंग के इलाकों का मुद्दा उठाया जाएगा, जहां चीन वादे के बावजूद अपनी सेना को मई 2020 से पहले वाली स्थिति पर ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ है। भारत लगातार कह रहा है कि जब तक चीन की सेना पहले वाली स्थिति में वापस नहीं होती है, तब तक सीमा पर शांति बहाली नहीं हो सकती।

शनिवार को सुबह 10.30 बजे एलएसी पर चीनी सीमा के भीतर स्थित मोल्दो में वार्ता की शुरुआत होगी। पूर्व की तीन-चार बैठकों की तरह इसके भी काफी लंबा चलने की उम्मीद है।

अभी तक दोनों पक्षों के बीच 11 दौर की सैन्य वार्ता हुई है और इससे पैंगोंग लेक के दोनों तरफ के इलाकों से सैनिकों की वापसी में मदद भी मिली है। इस बार करीब साढ़े तीन माह बाद बैठक हो रही है और इस देरी के पीछे वजह यह है कि चीन की तरफ से लगातार आनाकानी की जा रही है। फरवरी 2021 में पैंगोंग लेक के पास से सैनिकों की वापसी के बाद से चीन का रवैया बदला हुआ है। 14 जुलाई, 2021 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग ई के साथ मुलाकात में सैन्य वार्ता की तिथि जल्द तय करने की बात कही थी। एक घंटे की वार्ता में दोनों पक्षों ने कहा था कि एलएसी विवाद को लंबा खींचा जाना आपसी रिश्तों के हित में नहीं है।

एच-1बी वर्क वीजा आवेदकों को एक और मौका देगा अमेरिका

दूसरी लाटरी
- सैकड़ों भारतीय आइटी पेशेवरों के लिए एक और सुनहरा अवसर
- पंजीकरण की समय सीमा दो अगस्त से तीन नवंबर तक रहेगी

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका ने घोषणा की है कि वह एच-1बी वर्क वीजा के आवेदकों को दूसरा मौका देगा। यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेशन एंड सिटिजनशिप (यूएससीआइएस) इसके तहत उन योग्य आवेदकों को चयनित होने का मौका प्रदान करेगा जिन्हें पहली बार की लाटरी प्रणाली में नहीं लिया जा सका था। यह एक ऐसा कदम है जो सैकड़ों भारतीय आइटी पेशेवरों के लिए एक और सुनहरा अवसर होगा।

यूएससीआइएस ने एक बयान में कहा है कि इस साल की शुरुआत में बड़ी संख्या में एच-1बी वीजा जारी किए जाने के बाद यह फैसला किया गया। भारतीय आइटी पेशेवरों में प्रचलित एच-1बी वीजा, एक गैर-अप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विशिष्ट योग्यताओं वाले कार्यों के लिए विदेशी कर्मचारियों को रखने की अनुमति देता है। प्रौद्योगिकी कंपनियां, जिन्हें सैद्धांतिक या पेशेवर कौशल की आवश्यकता होती है, भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों लोगों को इसी वर्क वीजा के आधार पर रखती हैं।

यूएससीआइएस ने एक बयान में कहा कि हमने हाल ही में निर्णय लिया है कि हमें 2022 के वित्त वर्ष तक अतिरिक्त आवेदनों का चयन करने की जरूरत है। 28 जुलाई को हमने पहले गलत चयन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रानिक आवेदन जमा करने का विकल्प चुना था। 28 जुलाई को पंजीकरण की समय सीमा दो अगस्त से शुरू होती है और तीन नवंबर को बंद होगी। उन्होंने कहा, वैकल्पिक नोटिस शामिल करने के लिए अपडेट जानकारी के साथ इसे कब और कहां जमा करना है इसका विवरण लें। यूएससीआइएस से दूसरी लाटरी में जाने से भारतीय पेशेवरों समेत सैकड़ों आवेदकों के लिए एक विकल्प उपलब्ध होगा, जो पहले दौर में इसमें शामिल नहीं हो सके थे।

संघीय एजेंसी ने कहा,केवल वित्त वर्ष 2022 के लिए वैकल्पिक पंजीकरण वाले आवेदक ही एच-1बी वर्क वीजा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। वित्त वर्ष 2022 के लिए पंजीकरण करने वालों के लिए पहली आवेदन अवधि एक अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 तक थी। यूएससीआइएस ने कहा कि एच-1बी आवेदन एक वैध सेवा प्रदाता के पास और प्रासंगिक पंजीकरण नोटिस पर सूचीबद्ध समय सीमा के भीतर दायर किया जाना चाहिए। एच-1बी आवेदनों के लिए आनलाइन आवेदन उपलब्ध नहीं हैं। आवेदन लिखित रूप में किया जाना चाहिए और इसके साथ पंजीकरण विकल्प की एक प्रति शामिल होनी चाहिए।

अफगान सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में ढेर किए 100 आतंकी

- अफगानिस्तान के कई प्रांतों में तालिबान आतंकियों को बनाया गया निशाना


हेरात प्रांत में सुरक्षा बलों के साथ अफगान मिलिशिया भी मोर्चा संभाल रहे हैं। एएफपी

काबुल, आइएएनएस : अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच संघर्ष तेज हो गया है। अफगान सुरक्षा बलों ने कई प्रांतों में आतंकियों को निशाना बनाया। बीते 24 घंटे में 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया और करीब 90 को घायल कर दिया।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि हेरात प्रांत में सुरक्षा बलों के अभियान में 52 तालिबान आतंकी मारे गए और 47 घायल हो गए। यह अभियान प्रांतीय राजधानी हेरात सिटी और इसके आस-पास के जिलों में चलाया गया। सुरक्षा बलों के समर्थन में अफगान वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने कई जगहों पर हवाई हमले भी किए। अफगान रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसके अलावा हेरात के घुरियन जिले में 13 तालिबान आतंकी मारे गए और 22 घायल हो गए। यहां हवाई हमले में आतंकियों के सात वाहनों और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद को भी तबाह कर दिया गया। जबकि हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्कर गाह के बाहरी इलाकों में किए गए हवाई हमले में तालिबान के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। यहां भी कई आतंकियों के मरने और घायल होने की खबर है। इधर, कंधार प्रांत के झारी जिले में तालिबान आतंकियों के एक जमावड़े को निशाना बनाया गया। यहां हवाई हमले में 36 आतंकी के मरने और 20 के घायल होने की खबर है।

सुरक्षा बलों ने चलाया है अभियान : अमेरिकी बलों की वापसी शुरू होने के बाद से ही अफगानिस्तान में तालिबान अपना दायरा बढ़ा रहा है। इस आतंकी संगठन का देश के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा हो चुका है। इन जगहों से आतंकियों को खदेड़ने के लिए अफगान सुरक्षा बलों ने अभियान चला रखा है।

हेलमंद की राजधानी में घुसे आतंकी : समाचार एजेंसी रायटर के मुताबिक, हेलमंद की राजधानी लश्कर गाह में तालिबान आतंकी घुस गए हैं। यहां अफगान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लड़ाई चल रही है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि आतंकियों ने कई तरफ से लश्कर गाह पर हमला किया है। इसके चलते हजारों नागरिक जान बचाने के लिए शहर छोड़ रहे हैं।

अफगानिस्तान में दस हजार पाकिस्तानी आतंकी : एएनआइ के अनुसार, अफगान सरकार ने कहा, पाकिस्तान का एक संस्थान तालिबान आतंकियों को प्रशिक्षित कर रहा है। अफगानिस्तान में दस हजार से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी दाखिल हुए हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये आतंकी छद्म युद्ध को अंजाम देने के लिए भेजे गए हैं।

गुलाम कश्मीर पर और घिरे इमरान

आरोप ▸ विपक्षी दलों ने चुनाव को धांधली बताया

पीएमएल-नवाज करेगी विरोध-प्रदर्शन


प्रदर्शनकारियों की फाइल फोटो। इंटरनेट मीडिया

इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने प्रधानमंत्री इमरान खान पर हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर में हुए चुनावों में धांधली करने का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी ने इसके विरोध में इमरान सरकार के खिलाफ पूरे गुलाम कश्मीर में विरोध-प्रदर्शन करने का फैसला लिया है।

पाकिस्तानी अखबार डान की रिपोर्ट के अनुसार, पीएमएल-एन के महासचिव अहसान इकबाल ने कहा कि पहले उनकी पार्टी के प्रत्याशी अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिर पार्टी नेतृत्व आगे की रणनीति पर फैसला लेगा। इकबाल ने कहा कि गुलाम कश्मीर के चुनावों और सियालकोट के चुनावी नतीजों ने साबित कर दिया है कि पीएमएल-एन का यह कहना एकदम ठीक था कि पाकिस्तान में मौजूदा तहरीक-ए-इंसाफ सरकार पाकिस्तानी आवाम का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करती है। बल्कि यह बेईमानी और धांधली से बनी सरकार है। उन्होंने कहा कि इन दो चुनावों ने देश के खोखले लोकतांत्रिक ढांचे को उजागर कर दिया है। इस लोकतांत्रिक ड्रामे के मुख्य किरदार इमरान खान ही थे।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर में हुए तथाकथित चुनावों में इमरान खान की पार्टी को 25 सीटें जीतकर बहुमत मिला है। गुलाम कश्मीर की कथित विधानसभा में कुल 53 सदस्य हैं जिनमें से 45 का प्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन होता है।

इस बीच, भारत ने दो टूक शब्दों में पाकिस्तान से उसके कब्जे वाले गुलाम कश्मीर में हुए चुनाव को अवैध कब्जे पर फर्जी कवायद बताया है। साथ ही पाकिस्तानी प्रशासन के समक्ष इस बात को लेकर कड़ा विरोध किया है। भारत ने पाकिस्तान से कहा, वह अपने कब्जे वाले गुलाम कश्मीर को तत्काल प्रभाव से खाली कर दे, चूंकि यह भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि स्थानीय लोगों ने फर्जी चुनावों की इस नकली कवायद को सिरे से खारिज कर दिया है।

इमरान को चुनाव आयोग का नोटिस

- अपनी पार्टी पीटीआइ में चुनाव नहीं कराने पर 14 दिनों में देना होगा जवाब
- बताना होगा कि 13 जून को कराए जाने वाले चुनाव अब तक क्यों नहीं कराए गए


इमरान खान। (फाइल) एपी

इस्लामाबाद, प्रेट्र: पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के अध्यक्ष इमरान खान को पार्टी के संगठनात्मक चुनाव नहीं कराने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 215 (4) के तहत इमरान को 14 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में आयोग की ओर से और कड़े कदम उठाए जाने की चेतावनी भी दी गई है।

ज्ञात हो, इमरान ने हाल ही में चीन की एक दलीय कम्युनिस्ट शासन प्रणाली को अनूठा माडल करार दिया था। साथ ही कहा था कि चीनी माडल ने उस अवधारणा को खत्म कर दिया जिसमें कहा जाता है कि समाज में सुधार के लिए पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना ही बेहतरीन है।

चीनी सिस्टम को लेकर यह बयान देने वाले इमरान खान को अब अपनी ही पार्टी में लोकतंत्र नहीं होने को लेकर नोटिस मिला है। इमरान को एक पखवाड़े के अंदर बताना होगा कि पार्टी में जो आंतरिक चुनाव 13 जून को होने थे, उसे अब तक क्यों नहीं कराया गया।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पाक में सत्तारूढ़ इमरान खान की पार्टी के अतिरिक्त चुनाव आयोग ने दो अन्य पार्टियों को भी आंतरिक चुनाव नहीं कराने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें प्रतिबंधित तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी शामिल है।

यहां उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान चुनाव अधिनियम के तहत सभी राजनीतिक पार्टियों को समय-समय पर अनिवार्य रूप से पार्टी में आंतरिक चुनाव कराना आवश्यक है। चुनाव आयोग के नोटिस के अनुसार, इमरान खान 13 जून को पार्टी के अंदरूनी चुनावों का ब्योरा देने में नाकाम रहे।

ब्रिक्स ने आतंकवाद से लड़ाई की कार्य योजना को दिया अंतिम रूप

नई दिल्ली, प्रेट्र : आतंकवाद, कट्टरपंथ और आतंकी फंडिंग से निपटने के लिए ब्रिक्स देश अगले महीने होने वाली बैठक में एक कार्य योजना अपनाएंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि ब्रिक्स आतंकवाद-विरोधी संयुक्त कार्य समूह (सीटीडब्ल्यूजी) की 28 और 29 जुलाई को वर्चुअल बैठक में कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा, ब्रिक्स आतंकवाद-विरोधी संयुक्त कार्य योजना भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान प्रमुख योजनाओं में से एक है। इसे अगले महीने होने वाली ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में अपनाया जाएगा।

ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) दुनिया के पांच सबसे बड़े विकासशील देशों का एक समूह है। यह वैश्विक आबादी के 41 फीसद, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 24 फीसद और वैश्विक व्यापार के 16 फीसद का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ से निपटने में ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच गहरे सहयोग के लिए दृढ़ता से जोर देता रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीटीडब्ल्यूजी बैठक में ब्रिक्स देशों ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से खतरे पर विचारों का आदान-प्रदान किया और कार्य योजना के अनुरूप आतंकवाद विरोधी सहयोग और बढ़ाने का संकल्प लिया।

अफगान दुभाषियों को सुरक्षित निकालने के लिए पहली निकासी उड़ान अमेरिका पहुंची

- दो सौ अफगानों को एयरलिफ्ट करके लाया गया वाशिंगटन

वाशिंगटन, एपी: तालिबान के खिलाफ कार्रवाई में अमेरिकी सेना के साथ काम कर चुके दुभाषियों व अन्य लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमेरिका के इन मददगारों को लेकर पहला विमान शुक्रवार तड़के वाशिंगटन के डलास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। विमान में 221 अफगान नागरिक थे। यह जानकारी अमेरिकी सरकार के आंतरिक दस्तावेज व वाणिज्यिक फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस से मिली है।

रायटर के मुताबिक, अमेरिका के लिए काम करने वाले अफगानों को विशेष आव्रजन वीजा मुहैया कराया जा रहा है। इसके तहत अफगानी परिवारों को अमेरिका में बसाया जा रहा है। 'आपरेशन एलाइज रेफ्यूज' के तहत 50 हजार से अधिक लोगों को अमेरिका या किसी अन्य देश में बसाया जाएगा।

अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से रवाना होने के बाद तालिबान के प्रतिशोध की प्रबल आशंका है। इसीलिए पूर्व अनुवादकों और अन्य लोगों को अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट करना शुरू किया गया है। इसी के तहत पहली निकासी उड़ान से 57 बच्चों और 15 शिशुओं समेत 221 अफगानों को लेकर एक विमान वाशिंगटन के डलेस हवाई अड्डे पर उतरा। दुभाषियों के साथ उनके परिवार के सदस्य भी वापस लौट रहे हैं। अमेरिकी सरकार इस बात से भी सशंकित है कि आने वाले हफ्तों में पिछले अमेरिकी सुरक्षा बलों के अफगानिस्तान को छोड़ने के बाद अफगानिस्तानी सरकार और सेना उनके साथ कैसा सुलूक करेगी।



राजकुमारी का सैन्य प्रशिक्षण

अक्सर हमने सुना और कहानियों में पढ़ा होगा कि नाजों से पली राजकुमारियां बेहद कोमल होती हैं, लेकिन इस धारणा के उलट बेल्जियम की राजकुमारी एलिजाबेथ रायल मिलिट्री अकादमी में कठोर सैन्य प्रशिक्षण ले रही हैं। डच आफ ब्रेबेंट एलिजाबेथ सिंहासन के उत्तराधिकार की प्रथम पंक्ति में हैं। 25 अक्टूबर 2001 को जन्मी राजकुमारी को 21 जुलाई 2013 में ब्रेबेंट की उपाधि दी गई थी। वह रायल मिलिट्री स्कूल में सामाजिक और सैन्य विज्ञान की पढ़ाई कर रही हैं और इन दिनों कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में साधारण नागरिक की तरह सैन्य प्रशिक्षण ले रही हैं। पहाड़ों पर रस्सियों की मदद से कठिन चढ़ाई करना भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा है। रायटर

ओमान के निकट इजरायल के तेल टैंकर पर हमला, दो की मौत

- आत्मघाती ड्रोन से हमले के संकेत, ईरान पर शक
- मरने वाले चालक ब्रिटेन और रोमानिया के

दुबई, एपी : इजरायली अरबपति एयल ओफर के जोडैक ग्रुप की सहायक कंपनी जोडैक मैरीटाइम का तेल टैंकर ओमान के तट के निकट गुरुवार रात हमले का शिकार हो गया। हमले में चालक दल के दो सदस्य मारे गए हैं, जो ब्रिटेन व रोमानिया के हैं। हमले के समय मर्सर स्ट्रीट नाम का यह टैंकर अरब सागर में यात्रा कर रहा था। इस पर लाइबेरिया का झंडा लगा है। अमेरिका व इजरायल के अधिकारियों ने टैंकर पर आत्मघाती ड्रोन से हमले की आशंका जताई है और इसके लिए ईरान को जिम्मेदार बताया है। हालांकि अभी किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

इजरायल से संबंधित जहाजों पर जिस तरह से हाल के महीनों में हमले हुए हैं उससे इसे राजनीतिक कारणों से हुआ हमला माना जा रहा है। पूर्व हुए हमलों के लिए इजरायल ने ईरान को जिम्मेदार बताया था, जबकि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने वाले हमलों के लिए इजरायल को जिम्मेदार बताया था। तेल टैंकर पर हुए ताजा हमले से इलाके में तनाव बढ़ने की आशंका है। हमले की सूचना मिलने के बाद अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत मौके पर पहुंच गए और उन्होंने हमले का शिकार हुए तेल टैंकर को सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंचाया। हाल के वर्षों में इलाके के समुद्र में यह पहला जानलेवा हमला है।

ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड आपरेशंस ने कहा है कि घटना की जांच जारी है। बयान में किसी पर शक नहीं जताया गया है, लेकिन यह संकेत दिया गया है कि नजदीक ही एक अन्य जहाज के साथ भी ऐसी ही वारदात हुई है। दोनों मामलों की जांच की जा रही है। लंदन में स्थित कंपनी जोडैक मैरीटाइम ने कहा, तेल टैंकर मर्सर स्ट्रीट का संचालन जापान की कंपनी करती है। घटना के समय टैंकर खाली था। कंपनी ने कहा है कि हमला समुद्र में डकैती डालने जैसा है।

इजरायल में पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ की जांच शुरू

यरुशलम, प्रेट्र : इजरायल ने निगरानी साफ्टवेयर पेगासस को लेकर विवादों में आई इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी कंपनी के कई दफ्तरों पर पहुंचे और जायजा लिया। दुनिया की कई सरकारें जासूसी साफ्टवेयर पेगासस की ग्राहक हैं। उनके द्वारा इस साफ्टवेयर के जरिये कथित रूप से कराई गई जासूसी के चलते एनएसओ ग्रुप दुनिया के निशाने पर आ गया है।

इजरायली रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता के अनुसार, कंपनी पर लगे आरोपों की जांच के लिए कई एजेंसियों को लगाया गया है। इन एजेंसियों ने बुधवार को एनएसओ के दफ्तरों का निरीक्षण किया। हालांकि उन्होंने जांच के बारे में ज्यादा विवरण देने से इन्कार कर दिया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, जांच इस बात को लेकर केंद्रित है कि कहीं कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के निर्यात नियंत्रण विभाग से मिले परमिट और अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं किया है। इजरायली सरकार ने एनएसओ पर लगे आरोपों की समीक्षा के लिए गत सप्ताह एक समिति बनाई थी।

बता दें कि हाल में अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आई खबरों से सनसनी फैल गई कि पेगासस का इस्तेमाल कर भारत समेत कई देशों की सरकारें अपने यहां के नेताओं, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी करने में जुटी हैं। मीडिया में यहां तक खबर आई कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भी जासूसी की गई। इन खबरों के बीच, इजरायल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्ज ने बुधवार को पेरिस का दौरा किया और अपने फ्रांसीसी समकक्ष को भरोसा दिलाया कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।

कंपनी के दफ्तरों पर पहुंची इजरायली सुरक्षा एजेंसियां, लिया जायजा



पहले ही दे दी गई थी सूचना

समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार, एनएसओ ग्रुप ने बताया कि उसे पहले ही सूचना दे दी गई थी कि संवेदनशील साइबर निर्यात की निगरानी करने वाले रक्षा मंत्रालय के अधिकारी निरीक्षण करने आएंगे। साथ ही एनएसओ ने यह भी कहा कि कंपनी पूरी पारदर्शिता के साथ काम करती है।

फ्रांसीसी वित्त मंत्री के फोन की चल रही जांच

पेरिस, रायटर : फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रुनो ली माइरे के फोन की भी जासूसी होने की बात सामने आई है। पेगासस के जरिये जासूसी होने की पुष्टि करने के लिए उनके फोन की जांच की जा रही है। ब्रुनो ने फ्रांस इंटर रेडियो से शुक्रवार को कहा, 'हम इस समय जांच के दौर में हैं। मेरे भी फोन की जांच चल रही है।'

पेशावर में बारिश से राज कपूर व दिलीप कुमार की पुश्तैनी हवेलियां क्षतिग्रस्त

पेशावर, प्रेट्र : पाकिस्तान में मूसलधार बारिश के चलते विभिन्न इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। पेशावर जिले में भारी बारिश से कई पुरातात्विक इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। इनमें किस्सा ख्वानी बाजार स्थित प्रख्यात अभिनेता राज कपूर और दिलीप कुमार की पुश्तैनी हवेलियां भी शामिल हैं। पहले से जर्जर इन हवेलियों को पाकिस्तान सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था। दोनों भारतीय अभिनेताओं के सम्मान में इन हवेलियों को म्यूजियम में बदले जाने की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी थीं।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, अनवरत बारिश और जलभराव के बीच दिलीप कुमार व राज कपूर की हवेलियों के कुछ हिस्सों को क्षति पहुंची है। ध्यान रहे कि राज कपूर का देहावसान 1988 में हुआ था जब वह 64 वर्ष के थे, जबकि दिलीप कुमार का निधन लंबी बीमारी के बाद कुछ ही दिन पहले 98 वर्ष की आयु में हुआ था।

बाइडन बोले, कोरोना की वैक्सीन लगवाने वालों को दें 100-100 डालर


व्हाइट हाउस में संबोधित करते राष्ट्रपति जो बाइडन। एपी

अमेरिका में 24 घंटे में पाए गए 90 हजार से ज्यादा नए मामले

वाशिंगटन, एपी : कोरोना की दो लहरों का सामना करने वाले अमेरिका में इस खतरनाक वायरस का कहर फिर बढ़ रहा है। दैनिक मामलों में तेज उछाल दर्ज किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में 90 हजार से ज्यादा नए मामले पाए गए। पांच माह बाद इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित मिले हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने राज्यों से कहा, वे टीका लगवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने को कदम उठाएं। वैक्सीन लगवाने के लिए ऐसे लोगों को 100-100 डालर (करीब साढ़े सात हजार रुपये) का प्रस्ताव दें।

यह माना जा रहा है कि बाइडन ने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए यह नई योजना पेश की है। अमेरिका में हाल के हफ्तों में नए मामलों में तेज उछाल आया है। इसके लिए टीकाकरण की धीमी रफ्तार और कोरोना के डेल्टा वैरिएंट को कारण बताया जा रहा है। इसी कारण आधे से ज्यादा अमेरिकी राज्यों में नए मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका में 60 फीसद से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है।

जापान में मिले 3,300 नए मामले

जापान की राजधानी टोक्यो में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ओलिंपिक की मेजबानी कर रहे इस शहर में बीते 24 घंटे में 3,300 नए मामले पाए गए। यहां एक दिन पहले 3,865 केस मिले थे। नए मामलों में उछाल पर टोक्यो में इमरजेंसी का दायरा बढ़ा दिया गया है।

नोट और सिक्कों से कोरोना संक्रमण की आशंका नहीं

लंदन, आइएएनएस : एक अध्ययन में यह सामने आया है कि नोट या सिक्कों से कोरोना वायरस के फैलने की आशंका नहीं है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के विशेषज्ञों और जर्मनी की रूहर-यूनिवर्सिटी बोखम के शोधकर्ताओं ने नोट और सिक्कों से कोरोना वायरस के फैलने की संभावना का पता लगाने के लिए अध्ययन किया, जिसमें स्टेनलेस स्टील की सतह पर नोट, सिक्के व पीवीसी के बने बैंक क्रेडिट कार्ड रखे गए। विशेषज्ञों ने इन्हें कोविड-19 के लिए जिम्मेदार सार्स-कोव-2 वायरस से संक्रमित कराया। शोध में पाया गया कि स्टील की सतह पर तो वायरस सात दिनों तक रहा, लेकिन नोट और सिक्कों पर दो से छह दिन में गायब हो गया। तांबे के सिक्के पर मात्र एक घंटे ही टिक सका। अतः नोट या सिक्कों से सार्स-कोव-2 वायरस फैलने का खतरा न के बराबर है।

हांगकांग में प्रदर्शनकारी को नौ साल जेल, सुरक्षा कानून में पहली सजा

हांगकांग, एपी : हांगकांग में चीन की ओर से थोपे गए विवादित नए सुरक्षा कानून के तहत शुक्रवार को पहली सजा सुनाई गई। लोकतंत्र समर्थक एक प्रदर्शनकारी को नौ साल जेल की सजा सुनाई गई।

नए सुरक्षा कानून के तहत, 24 साल के टोंग यिंग-किट को आतंकवाद और अलगाववाद के आरोप में दोषी करार दिया गया। टोंग पर आराप था कि उसने एक जुलाई, 2020 को 'हांगकांग को आजाद करो' जैसे नारे लगाते हुए पुलिस अफसरों पर बाइक चढ़ा दी थी। वहीं, अमेरिका ने कहा, टोंग का ट्रायल पक्षपातपूर्ण ढंग से चलाया गया। कानून का उपयोग विरोधियों की आवाज कुचलने के लिए किया जा रहा है। चीन अधिकारों की मांग करने वाले लोगों को निशाना बनाना बंद करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के एशिया-पैसिफिक मामलों की क्षेत्रीय निदेशक यामिनी मिश्रा ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। यह कानून सरकार के आलोचकों को आतंकित करने का हथियार है।



तुर्की के जंगल धधके

अमेरिका के बाद तुर्की के जंगल भी आग से बुरी तरह धधक रहे हैं। अंताल्या प्रांत के मानवघाट शहर के पास लगी आग पर काबू पाने के लिए फायरफाइटर और स्थानीय नागरिक लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं। लेकिन तेज हवाओं और भीषण गर्मी की वजह से आग पर काबू पाने में दिक्कतें आ रही हैं। दक्षिणी हिस्से के जंगलों में लगी आग से कई लोगों के मारे जाने की भी सूचना है। यहां आसपास के करीब 20 गांवों को खाली कराया जा रहा है। कई जगहों पर आग की लपटें कई मीटर ऊंची उठती दिखाई दे रही हैं। एपी

लवलीना ने पदक पर जड़ा पंच

असम की मुक्केबाज ने टोक्यो ओलिंपिक में मुक्केबाजी में भारत का पहला पदक पक्का किया



2018
और 2019 विश्व चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहाई ने कांस्य पदक जीता था

2017
और 2021 एशियन चैंपियनशिप लवलीना कांस्य पदक अपने नाम कर चुकी हैं

जीत के बाद खुश लवलीना बोरगोहाई • एपी

टोक्यो, प्रेट्र : अपना पहला ओलिंपिक खेल रही लवलीना बोरगोहाई (69 किग्रा) ने पूर्व विश्व चैंपियन चीनी ताइपै की नियेन चिन चेन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश करने के साथ टोक्यो ओलिंपिक की मुक्केबाजी स्पर्धा में भारत का पदक पक्का कर दिया। भारोत्तोलक मीराबाई चानू के रजत जीतने के बाद भारत का दूसरा पदक इस ओलिंपिक में आएगा।

असम की 23 वर्ष की मुक्केबाज ने 4-1 से जीत दर्ज की। अब उनका सामना मौजूदा विश्व चैंपियन जुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली से होगा जिसने क्वार्टर फाइनल में अन्ना लिसेंको को मात दी। दो बार विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता लवलीना ने जबर्दस्त संयम का प्रदर्शन करते हुए उस विरोधी को हराया जिससे वह पहले हार चुकी हैं।

आक्रामक शुरुआत के बाद उन्होंने आखिरी तीन मिनटों में अपना रक्षण भी नियंत्रित रखा और जवाबी हमलों में भी कोई चूक नहीं की। पिछले साल कोरोना संक्रमण की शिकार हुई लवलीना यूरोप में अभ्यास दौरे पर नहीं जा सकी थी। रेफरी ने जैसे ही विजेता के रूप में उनका हाथ उठाया, वह खुशी के मारे जोर से चीख पड़ीं।

स्वर्ण लेकर आएगी लवलीना : पिता टिकेन बोरगोहाई : लवलीना के पिता टिकेन बोरगोहाई ने भरोसा जताया कि उनकी बेटी निश्चित रूप से दो और जीत दर्ज कर इस कांस्य पदक को स्वर्ण पदक में तब्दील करेगी। उन्होंने कहा, 'उनका सपना आखिरकार सच हो रहा है। उसने 2012 में शुरुआत की थी, तब से वह ओलिंपिक में पहुंचने और वहां पदक जीतने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगी हुई थी।' टिकेन बोरगोहाई ने कहा, 'वह सेमीफाइनल में जीतकर फाइनल में पहुंचेगी, मुझे पूरा भरोसा है। हमने सुबह उससे बात की थी और मुकाबले से पहले उसे आशीर्वाद दिया था।'

असम में जश्न का माहौल : लवलीना का पदक पक्का होने के बाद असम में जश्न का माहौल बन गया। असम ओलिंपिक समिति के महासचिव लख्य कंवर ने इसे राज्य के लिए सबसे बड़ा खेल का क्षण करार दिया। लवलीना के सेमीफाइनल में पहुंचने कुछ ही घंटों में मीडियाकर्मी भी अपनी ओबी वैन में इस 23 साल की मुक्केबाज के गोलाघाट जिले के बारा मुखिया गांव में स्थित घर की ओर बढ़ चले। लवलीना असम से ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं। उनके पदक पक्का करते ही स्थानीय लोग भी उनके घर पहुंचने लगे और वे सड़कों पर नाच भी रहे थे। टीवी चैनल के पत्रकारों ने उनसे भी बात की। वह शिव थापा के बाद असम से ओलिंपिक में पहुंचने वाली दूसरी मुक्केबाज हैं।

लवलीना पर इन्होंने खर्च की राशि

टाप्स	एसीटीसी	कुल
₹11,30,300	₹7,00,215	₹18,30,515

टाप्स : टारगेट ओलिंपिक पोडियम स्कीम
एसीटीसी : एनुअल कैलेंडर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन

हम इस पदक का इंतजार कर रहे थे। हर किसी ने इतनी मेहनत की है। मैं उसके लिए बहुत खुश हूं। वह हमेशा ही कम चर्चित लड़की रही है। यह पदक उसके लिए जश्न का मौका है।
एमसी मेरी कोम

किक बाक्सर से मुक्केबाज बनीं लवलीना

ओलिंपिक में देश के लिए दूसरा पदक पक्का करने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई को इस खेल से जुड़ने के लिए प्रेरित करने वाले भारतीय खेल प्राधिकरण के कोच पदम बोरो ने एक दिन पहले ही कह दिया था,वह आराम से जीतेगी, कोई टेंशन नहीं है। लवलीना पहले किक-बाक्सर थी और उन्हें एमेच्योर मुक्केबाजी में लाने का श्रेय बोरो को जाता है। उनकी इस शिष्या ने शुक्रवार को उन्हें निराश भी नहीं किया। लवलीना का खेलों के साथ सफर असम के गोलाघाट जिले के बरो मुखिया गांव से शुरू हुआ। यह स्थान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी प्रसिद्ध है। उनकी बड़ी बहनें लीचा और लीमा किक-बाक्सर हैं और सीमित साधनों के बाद भी उनके माता-पिता बच्चों की खेल महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने से कभी पीछे नहीं हटे। बोरो ने कहा, 'उन्होंने (माता-पिता) ने लवलीना का पूरा समर्थन किया। वे अक्सर मेरे साथ उसके खेल पर चर्चा करते थे और उसके सपनों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे।' लवलीना ने किसी को निराश नहीं किया।

इस 23 साल की खिलाड़ी की जीत को भारतीय महिला मुक्केबाजी में नए अध्याय की तरह देखा जा रहा है। दिग्गज एमसी मेरी कोम के ओलिंपिक से बाहर होने के बाद लवलीना ने अपने करियर के सबसे यादगार पल के साथ भारतीय प्रशंसकों को जश्न मनाने का मौका दिया। बोरो ने कहा, 'उनमें एक अच्छा मुक्केबाज बनाने की प्रतिभा थी और उसकी शरीर भी मुक्केबाजी के लिए उपयुक्त है। करियर के शुरू में भी उसका शांत दिमाग उनकी सबसे खास बात थी। वह ऐसी नहीं है जो आसानी से हार मान जाए। वह तनाव नहीं लेती है। वह बहुत अनुशासित खिलाड़ी है।' उनकी मां ममोनी का पिछले साल किडनी प्रत्यारोपण हुआ था। लवलीना ने उस समय कुछ दिनों के लिए उनसे मुलाकात की, लेकिन टूर्नामेंटों की तैयारियों के लिए 52 दिनों के लिए यूरोप जाने से पहले वह कोरोना से संक्रमित हो गईं। यह प्रशिक्षण दौरा उनके लिए महत्वपूर्ण था। मुक्केबाजों को शिविरों के फिर से खुलने के बाद भी कई दिनों तक उन्हें स्पैरिंग (दूसरे मुक्केबाज के साथ अभ्यास) की अनुमति नहीं थी।

खुद को साबित करना चाहती थी : लवलीना बोरगोहाई

लवलीना बोरगोहाई ने कहा कि टोक्यो खेलों के क्वार्टर फाइनल में वह कोई रणनीति बनाकर नहीं उतरी थी बल्कि रिंग के अंदर की परिस्थितियों के हिसाब से खेली थी क्योंकि चीनी ताइपे की मुक्केबाज से वह पहले चार बार हार चुकी थीं। लवलीना ने कहा, 'मैं उससे (नियेन चिन चेन) चार बार हार चुकी थी। खुद को साबित करना चाहती थी। मुझे लगा यही मौका है, अब मैं चार बार हारने का बदला लूंगी।' किस रणनीति के साथ रिंग में उतरी थीं, इस पर उन्होंने कहा, 'कोई रणनीति नहीं थी क्योंकि प्रतिद्वंद्वी मुक्केबाज इससे पकड़ सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि रिंग में ही देखूंगी और वहीं परिस्थितियों के हिसाब से खेलूंगी। मैं खुलकर खेल रही थी।' यह युवा मुक्केबाज कई परेशानियों से जूझने के बाद यहां अपने पहले ओलिंपिक तक पहुंची है, लेकिन अभी उनका इरादा कुछ भी सोचकर ध्यान भटकाने का नहीं है। उन्होंने कहा, 'पहली बात तो मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं सोच रही हूं। मुझे कांस्य पदक पर नहीं रुकना। खुद को साबित करके दिखाना था, मैंने यहां तक पहुंचने के लिए आठ साल मेहनत की है।' अगले मुकाबले के बारे में उन्होंने कहा, 'मेरा लक्ष्य स्वर्ण पदक है। पदक तो एक ही होता है। उसके लिए ही तैयारी करनी है। सेमीफाइनल की रणनीति बनानी है।'

मुक्केबाजी स्टार मुहम्मद अली की प्रशंसक लवलीना उनसे काफी प्रेरणा लेती हैं, उन्होंने कहा, 'वह दूरी बनाकर खेलते हैं, उनकी एक-दो बार वीडियो देखी हैं। उनका फुटवर्क और लांग पंच देखती हूं, हालांकि हर मुक्केबाज अलग होता है।'

सुपर सिंधू सेमीफाइनल में

- क्वार्टर फाइनल में अकाने यामागुची को दी शिकस्त
- आज सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की यिंग से होगा सामना

सिंधू पर इन्होंने खर्च की राशि

टाप्स	एसीटीसी	कुल
51,28,030	3,46,51,150	3,97,79,180

टाप्स : टारगेट ओलिंपिक पोडियम स्कीम
एसीटीसी : एनुअल कैलेंडर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन
नोट : सभी राशि रुपये में है



जीत के बाद जोश में पीवी सिंधू • एएनआइ

टोक्यो, प्रेट्र : मौजूदा विश्व चैंपियन पीवी सिंधू शुक्रवार को जापान की दुनिया की पांचवें नंबर की खिलाड़ी अकाने यामागुची को सीधे गेमों में पराजित कर यहां टोक्यो ओलिंपिक की महिला सिंगल्स स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गईं।

रियो ओलिंपिक की रजत विजेता ने शानदार रक्षण किया और अपने आक्रामक आलराउंड खेल की बदौलत क्वार्टर फाइनल में यामागुची को 56 मिनट में 21-13, 22-20 से शिकस्त दी। अब शनिवार को उनका सामना चीनी ताइपे की ताई जु यिंग से होगा।

मैच से पहले सिंधू का जापानी खिलाड़ी के खिलाफ जीत का रिकार्ड 11-7 था जिसे उन्होंने इस साल मार्च में आल इंग्लैंड में हराया था। यामागुची ने भी आक्रामक खेल दिखाने का प्रयास किया, लेकिन सिंधू ने अपने आक्रामक स्मैश और हाफ स्मैश से विपक्षी पर दबाव बनाया। शुरुआती गेम में सिंधू 2-4 से पिछड़ रही थीं, लेकिन उन्होंने तेजी से वापसी करते हुए इसे 6-6 से बराबर कर दिया। ब्रेक तक सिंधू 11-7 से आगे हो गईं। उन्होंने अपने फोर कोर्ट का बखूबी इस्तेमाल किया और नेट पर भी अच्छी रहीं। सिंधू ने नेट के करीब विनर लगाकर पहला गेम 23 मिनट में अपने नाम कर लिया। सिंधू ने दूसरे गेम में शानदार नेट ड्रिबल और क्रास कोर्ट स्मैश से ब्रेक तक पांच अंक की बढ़त बना ली। यामागुची ने हालांकि 8-13 से पिछड़ने के बाद वापसी की और अगले नौ मे से आठ अंक हासिल कर लिए जिससे उन्होंने 16-15 की बढ़त ले ली। यामागुची ने हालांकि 15-13 के स्कोर पर ही सिंधू को थकाने वाली रैली में उलझाया। जापानी खिलाड़ी अच्छा रक्षण कर रही थी जिससे सिंधू को करीब खेलने के लिए बाध्य कर दिया। इस दौरान उन्होंने गलती भी की और यामागुची ने 18-16 से बढ़त बना ली। यामागुची ने दो और गेम प्वाइंट हासिल किए जिससे उनकी वापसी करने की उम्मीद लग रही थी। लेकिन सिंधू ने फिर दो स्मैश लगाकर स्कोर 20-20 कर दिया। फिर एक और हाफ स्मैश ने वह मैच प्वाइंट तक पहुंचकर गेम जीत पाईं।

जापान पर जोशीली जीत

टोक्यो, प्रेट्र : गुरजंत सिंह के दो गोल की मदद से भारतीय पुरुष हाकी टीम ने पूल-ए के अपने आखिरी मैच में शुक्रवार को यहां मेजबान जापान को 5-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल से पहले आत्मविश्वास बढ़ाने वाली जीत दर्ज की। भारत की तरफ से हरमनप्रीत सिंह (13वें), गुरजंत सिंह (17वें और 56वें), शमशेर सिंह (34वें) और नीलाकांता शर्मा (51वें मिनट) ने गोल करके जापान के किले में सेंध लगाई। जापान की तरफ से केंता तनाका (19वें), कोता वतानबे (33वें) और काजुमा मुराता (59वें मिनट) गोल करके हार का अंतर ही कम कर पाए।

भारत पहले ही क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह सुरक्षित कर चुका था, लेकिन इस जीत से वह बढ़े मनोबल के साथ अंतिम-आठ के मुकाबले में उतरेगा। भारत ने पूल चरण में जापान के अलावा न्यूजीलैंड, स्पेन और अर्जेंटीना को हराया। आस्ट्रेलिया से उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस तरह से भारत पूल-ए में चार जीत और एक हार के साथ आस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर रहकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। आस्ट्रेलिया की टीम शीर्ष पर रही। क्वार्टर फाइनल एक अगस्त को खेले जाएंगे।

आखिरकार जीती महिला टीम : आखिरी मिनटों में नवनीत कौर के गोल की मदद से महिला हाकी टीम ने आयरलैंड को 1-0 से हराकर क्वार्टर नवनीत ने मैच का एकमात्र गोल 57वें मिनट में किया। इससे पहले भारत को मिले 14 पेनाल्टी कार्नर बेकार गए। भारत को इस मैच में हर हालत में जीत दर्ज करनी थी। इससे पहले भारत को नीदरलैंड्स ने 5-1 से, जर्मनी ने 2-0 और ब्रिटेन ने 4-1 से हराया। भारत को शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतने के साथ गोल औसत भी बेहतर रखना होगा।

क्वार्टर फाइनल लाइन-अप

मैच	समय
जर्मनी vs अर्जेंटीना	सुबह 6:00 बजे
आस्ट्रेलिया vs नीदरलैंड्स	सुबह 8:30 बजे
बेल्जियम vs स्पेन	दोपहर 3:00 बजे
भारत vs ग्रेट ब्रिटेन	शाम 5:30 बजे

नोट : क्वार्टर फाइनल एक अगस्त को होंगे।

तीसरे ओलिंपिक में भी खाली रही दीपिका की झोली

टोक्यो, प्रेट्र : दुनिया की नंबर एक तीरंदाज दीपिका कुमारी का ओलिंपिक पदक जीतने का सपना लगातार तीसरी बार टूट गया जब वह क्वार्टर फाइनल में कोरिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त अन सान से हार गईं। दीपका ने चार बार सात का स्कोर किया जबकि रैंकिंग दौर में ओलिंपिक रिकार्ड के साथ शीर्ष पर रही अन ने छह मिनट के अंदर 6-0 से जीत दर्ज कर ली। दीपिका 2016 रियो ओलिंपिक में प्री क्वार्टर फाइनल में हार गई थी जबकि लंदन ओलिंपिक में वह पहले दौर से बाहर हो गई थीं।

राष्ट्रीय रिकार्ड के बावजूद फाइनल से चूके साबले, दुती भी बाहर : ओलिंपिक की एथलेटिक्स स्पर्धा में भारत के अभियान की शुरुआत निराशाजनक रही जब अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपलचेस स्पर्धा में अपना ही राष्ट्रीय रिकार्ड बेहतर किया, लेकिन फाइनल में जगह नहीं बना सके जबकि दुती चंद औसत प्रदर्शन के साथ शुरुआती दौर से ही बाहर हो गईं। एमपी जबीर भी पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ से बाहर हो गए। साबले ने दूसरी हीट में 8:18.12 का समय निकाला और मार्च में फेडरेशन कप में बनाया 8:20.20 का अपना ही रिकार्ड तोड़ा। वह दूसरी हीट में सातवें स्थान पर रहे।

मनु, राही की हार : निशानेबाजी में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा। मनु भाकर और राही सरनोबत 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल्स में प्रवेश से चूक गईं। प्रिसीजन दौर के बाद 292 स्कोर करके मनु गुरुवार को छठे स्थान पर थी, लेकिन रैपिड दौर के बाद वह शुक्रवार को कुल 582 स्कोर करके 15वें स्थान पर रहीं। वहीं, राही 573 के स्कोर के साथ 32वें स्थान पर रहीं।

पदक तालिका

	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
चीन	19	10	11	40
जापान	17	4	7	28
अमेरिका	14	16	11	41
आरओसी	10	14	10	34
आस्ट्रेलिया	9	2	11	22
ग्रेट ब्रिटेन	6	9	9	24
द. कोरिया	5	4	6	15
नीदरलैंड्स	3	7	5	15
फ्रांस	3	5	5	13
जर्मनी	3	4	9	16
भारत	0	1	0	1

नोट : भारत तालिका में 51वें स्थान पर है।
आरओसी (रूसी ओलिंपिक समिति)

अब तीरंदाजी में अतानु ही उम्मीद

टोक्यो, प्रेट्र : अब तीरंदाजी में भारतीय चुनौती अतानु दास के रूप में ही बची है जो दो बार के ओलिंपिक चैंपियन ओह जिन हयेक को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। वह शनिवार को जापान के ताकाहारू फुरूकावा से खेलेंगे जो 2012 ओलिंपिक के रजत पदक विजेता और यहां टीम स्पर्धा के कांस्य विजेता हैं।

निराशा को दूर करना चाहेंगे सांवत और अंजुम : जब भारतीय निशानेबाज तेजस्विनी सावंत और अंजुम मौदगिल मैदान पर उतरेंगे तो वे इस निराशा के दौर को दूर करके इस खेल में भारत को पहला पदक दिलाना चाहेंगे। भारत के 15 सदस्यीय निशानेबाजी दल में से अभी तक सिर्फ सौरभ चौधरी (10 मीटर एयर पिस्टल) फाइनल में जगह बना पाए थे, लेकिन फाइनल में वह सातवें स्थान पर रहे थे।

सीमा पूनिया पर रहेगी निगाह : ओलिंपिक में शुक्रवार को एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन के बाद अब शनिवार को सभी की निगाह महिला डिस्कस थ्रो में सीमा पूनिया पर रहेगी। इसके अलावा इसी खेल में कमलप्रीत कौर अपनी छाप छोड़ना चाहेंगी। वहीं, पुरुष लंबी कूद में श्रीशंकर उतरेंगे।

फवाद संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर : पहली बार ओलिंपिक खेलों में चुनौती पेश कर रहे भारतीय घुड़सवार फवाद मिर्जा ने अच्छी शुरुआत की है और शुक्रवार को इवेंटिंग स्पर्धा में ड्रेसेज दौर के बाद तालिका में वह संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर रहे।

अमित पंघाल भी ला सकते हैं पदक

विजेंद्र सिंह



कलम से

उन्होंने कर दिखाया। लवलीना बोरगोहाई ने राष्ट्रीय मुक्केबाजी दल और पूरे देश को एक बड़ा लम्हा दिया। सभी की तरह मैं भी इस बात से बेहद खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि उन्होंने ये कर दिखाया। कुछ दिन पहले मैंने यही बात कही भी थी कि मैं उनसे पदक दौर में पहुंचने की उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि वह एक शानदार खिलाड़ी हैं। जिस तरह उन्होंने शुरुआती स्तर में नियेन चिन चेन के खिलाफ सीधे पंचों का इस्तेमाल किया वह देखकर मुझे काफी खुशी हुई। उन्होंने शुरुआत से ही मुकाबले पर दबदबा बना लिया और चीनी ताइपे की मुक्केबाज को अपने जैब्स और सीधे पंचों से पीछे धकेले रखा। रिंग में उनका चतुराई भरा खेल पूरे चरम पर था। मुझे कहना ही होगा कि जिस तरह लवलीना ने अपने कद का इस्तेमाल करते हुए सीधे पंच लगाए उसने मुझे याद दिला दिया कि मैं भी रिंग में इसी चीज को प्राथमिकता देता हूं। ओलिंपिक खेलों में मुक्केबाजी में देश का पहला पदकधारी होने के नाते मैं इस छोटे से क्लब में लवलीना का स्वागत करके खुश हूं, जिसका हिस्सा महान मेरी कोम भी हैं। मुझे उम्मीद है कि टोक्यो में एक और मुक्केबाज इस क्लब का हिस्सा बन सकता है। मेरे हिसाब से वह अमित पंघाल हैं। ऐसा हुआ तो ये क्लब 2012 लंदन ओलिंपिक में मेरी कोम के जीते गए कांस्य पदक के बाद से दोगुना हो सकता है। मुझे कहना ही होगा कि अगर पूजा रानी 75 किग्रा भारवर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीन की लि कियान के खिलाफ जीत दर्ज करने में सफल रहती हैं तो ये काफी शानदार होगा। उन्हें 2018 की विश्व चैंपियन और रियो खेलों की कांस्य पदक विजेता के खिलाफ जीत का विश्वास लेकर रिंग में उतरना होगा। (टीसीएम)

भारत के आज के मैच

पदक के मुकाबले

तीरंदाजी (व्यक्तिगत स्पर्धा) :
खिलाड़ी : अतानु दास, 1/8 एलिमिनेशन, सुबह 7:18 बजे से
फाइनल : दोपहर 1:15 बजे से

निशानेबाजी : महिला 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन क्वालीफिकेशन, सुबह 8:30 बजे से, फाइनल : दोपहर 12:30 बजे से
खिलाड़ी : अंजुम मौदगिल और तेजस्विनी सावंत

अन्य मुकाबले

एथलेटिक्स : सीमा पूनिया : महिला डिस्कस थ्रो, क्वालीफिकेशन, सुबह 6:00 बजे से
- कमलप्रीत कौर : महिला डिस्कस थ्रो, क्वालीफिकेशन, सुबह 7:25 बजे से
- श्रीशंकर : पुरुष लंबी कूद, क्वालीफिकेशन, दोपहर 3:40 बजे से

बैडमिंटन :
- महिला सिंगल्स, सेमीफाइनल, दोपहर 3:20 बजे से

खिलाड़ी : पीवी सिंधू

मुक्केबाजी
- पुरुष : राउंड आफ 16, सुबह 7:30 बजे से

खिलाड़ी : अमित पंघाल
- महिला : क्वार्टर फाइनल, दोपहर 3:36 बजे से

खिलाड़ी : पूजा रानी

गोल्फ : पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले राउंड-2, सुबह 4:00 बजे से
खिलाड़ी : अनिर्बान लाहिड़ी और उदयन माने

हाकी : महिला टीम, पूल-ए, सुबह 8:45 बजे से, बनाम दक्षिण अफ्रीका

घुड़सवारी
इवेंटिंग ड्रेसेज टीम एंड इंडिविजुअल दूसरा दिन, तीसरा सत्र, सुबह 5:00 बजे से
खिलाड़ी : फवाद मिर्जा

सेलिंग : पुरुष स्किफ 49ईआर रेस 10, 11 व 12, सुबह 8:35 बजे से
खिलाड़ी : केसी गणपति व वरुण ठक्कर

प्रसारण : सोनी नेटवर्क पर

टोक्यो में टेनिस | पहला सेट हारने के बाद ज्वेरेव ने की जोरदार वापसी, जर्मन खिलाड़ी की सर्विस के आगे असहज दिखे सर्बियाई स्टार

ज्वेरेव ने तोड़ा जोकोविक का गोल्डन स्लैम का सपना

3 बार ज्वेरेव जोकोविक को अपने करियर में हरा चुके हैं, जबकि दोनों के बीच हुए अन्य छह मुकाबलों में जोकोविक को जीत मिली है

22 मैचों में लगातार जीत दर्ज करने के बाद जोकोविक का विजय अभियान थमा



हार के बाद निराश जोकोविक • रायटर

टोक्यो, एपी : गोल्डन स्लैम का सपना लेकर खेलों के महाकुंभ ओलिंपिक में उतरे दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव की सर्विस का जवाब नहीं दे सके और हार कर बाहर हो गए। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में ज्वेरेव ने पहले सेट में पिछड़ने के बाद अपनी दमदार सर्विसों से दो घंटे तीन मिनट तक चले मुकाबले में सर्बियाई स्टार जोकोविक को 1-6, 6-3, 6-1 से हराया। इस हार के साथ जोकोविक का गोल्डन स्लैम पूरा करने का सपना भी टूट गया।

जोकोविक ने ज्वेरेव के खिलाफ पहला सेट आसानी से जीता, लेकिन ज्वेरेव ने दूसरे सेट में वापसी की और जोकोविक को पछाड़ा। तीसरे सेट में ज्वेरेव ने अपने प्रदर्शन से जोकोविक को स्तब्ध किया और उन्हें वापसी का कोई मौका नहीं देते हुए तीसरा सेट भी अपने नाम कर लिया। ज्वेरेव ने अपनी पहली सर्विस से 71 फीसद अंक लिए, जबकि सर्बियाई खिलाड़ी चारों प्रायस में विफल रहे और पूरे मैच के दौरान उनकी सर्विस का माकूल जवाब नहीं दे पाए। जोकोविक ने मुकाबले में सात बेजां गलतियां कीं, जबकि ज्वेरेव ने सिर्फ तीन बेजां गलतियां कीं।

जोकोविक ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतने की चाहत लेकर गोल्डन स्लैम के सपने को पूरा करने की तरफ बढ़ रहे थे। अगर वह स्वर्ण पदक जीतते और उसके बाद साल के अंतिम ग्रैंडस्लैम यूएस ओपन को भी अपने नाम कर लेते तो साल के चारों ग्रैंडस्लैम और ओलिंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले वह टेनिस जगत के पहले पुरुष खिलाड़ी बन जाते। इससे पहले साल 1988 में जर्मनी की महिला टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ ने गोल्डन स्लैम अपने नाम किया था।

ज्वेरेव स्वर्ण के लिए खचानोव से भिड़ेंगे : ज्वेरेव स्वर्ण पदक के लिए रूस ओलिंपिक समिति (आरओसी) के कारेन खचानोव से भिड़ेंगे, जिन्होंने दूसरे सेमीफाइनल में स्पेन के पाब्लो कारेनो बुस्ता को सीधें सेटों में 6-3, 6-3 से हराया। पाब्लो ने क्वार्टर फाइनल में आरओसी के ही डेनिल मेदवेदेव को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।

तीसरी बार ओलिंपिक कांस्य पदक का मैच खेलेंगे जोकोविक : जोकोविक ने 2008 बीजिंग ओलिंपिक में कांस्य पदक जीता था। 2012 लंदन ओलिंपिक में वह कांस्य पदक के मैच में हार गए थे, जबकि 2016 रियो ओलिंपिक में पहले दौर में ही बाहर हो गए थे। इस तरह वह अब तीसरी बार ओलिंपिक के कांस्य पदक का मुकाबला खेलेंगे, जहां उनका सामना स्पेन के पाब्लो कारेनो बुस्ता से होगा।

दैनिक जागरण

सप्तरंग

जोश नई राहों का

शनिवार, 31 जुलाई, 2021



लगातार सोचो और इस बात पर ध्यान दो कि तुम कैसे और बेहतर कर सकते हो, खुद से सवाल करो। -एलन मस्क

टेक लर्निंग

ट्रांसक्रिप्शन जाब से घर बैठे कमाई

अच्छी टाइपिंग के साथ-साथ आडियो को टेक्स्ट में कनवर्ट करना आता है, तो ट्रांसक्रिप्शन जाब आपके लिए कमाई का एक बेहतर जरिया बन सकता है। अच्छी बात यह है कि कई साइट्स घर बैठे इस तरह की नौकरियां पेश कर रही हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही वेबसाइट्स के बारे में...

ट्रांसक्रिप्शन मी: जो लोग तेजी से टाइपिंग करना जानते हैं, उनके लिए आज ट्रांसक्रिप्शन फील्ड में भी अच्छे मौके हैं। आजकल जनरल ट्रांसक्रिप्शन जाब के लिए भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। हालांकि मेडिकल और लीगल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट ज्यादा डिमांड में होते हैं और उन्हें पैसे भी काफी अच्छे मिलते हैं। मेडिकल और लीगल ट्रांसक्रिप्शन जाब के लिए इस फील्ड से जुड़ी जानकारी भी होनी जरूरी है। इस तरह के जाब्स के लिए ट्रांसक्राइबमी एक अच्छा प्लेटफार्म है, लेकिन यहां पर आपको टेस्ट पास करना होगा। इस प्लेटफार्म से 20 लाख से अधिक स्किल्ड प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं।
https://transcribeme.com

रेव: जो लोग घर बैठे ट्रांसक्रिप्शन जाब करना चाहते हैं, उनके लिए यहां पर काफी मौके हैं। हालांकि यहां पर जाब हासिल करने के लिए टेस्ट प्रासेस थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब एक बार टेस्ट पास कर लेते हैं, तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन वर्क के लिए अच्छा पेमेंट किया जाता है। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन और कैप्शन वर्क के लिए एक डालर प्रति मिनट तक पेमेंट किया जाता है, वहीं फारेन सबटाइटल्स के लिए तीन डालर प्रति मिनट तक पेमेंट होता है। इसके अलावा, यहां पर आप ट्रांसलेशन जाब भी हासिल कर सकते हैं।
www.rev.com



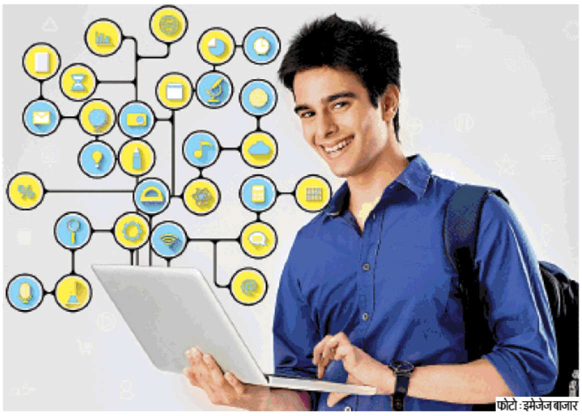
फोटो : इमेजेज बाजार

स्पीचपैड

इस साइट पर ट्रांसक्रिप्शन नौकरी के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। यहां से जाब हासिल करने के लिए आपको पहले अपना एकाउंट क्रिएट करना होगा। जब आप साइन-इन कर लेंगे, तो फिर टाप नेविगेशन बार में अपलोड फाइल्स पर क्लिक करें। जैसे ही फाइल अपलोड होगी, वह माई आडियो ऐंड वीडियो टैब में माई फाइल में दिखाई देगी। इसके बाद उस फाइल को टेक्स्ट में कनवर्ट करना होगा। यहां पर प्रति मिनट के रूप में पेमेंट किया जाता है। वैसे, इस जाब के लिए अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए।
www.speechpad.com

अमित निधि

हाल के वर्षों में एआइ, मशीन लर्निंग, ब्लाक चेन, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी नई तकनीकों के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए इंजीनियरिंग की पारंपरिक शिक्षा में भी बड़े बदलाव की जरूरत महसूस की गई। इन नई तकनीकों में सांख्यिकी, गणित, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आदि का भी काफी उपयोग होता है। यही कारण है कि इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के साथ इन नई तकनीकों का समावेश करते हुए दोनों का लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। आइए जानें, एआइसीटीई की देखरेख में तकनीकी शिक्षा में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं...



फोटो : इमेजेज बाजार

नये दौर की तकनीकी शिक्षा





टर्निंग प्वाइंट

लेफ्टिनेंट कर्नल कैलाश बंसल
डायरेक्टर, मीडिया ऐंड मार्गदर्शन सेल, एआइसीटीई

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के एक साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि, 'जब हंसी-खुशी से पढ़ाई होगी तो कामयाबी तय है।...राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के युवा वर्ग के सोच के अनुरूप है। 21वीं सदी के युवाओं को एक्सपोजर चाहिए। वे शिक्षा के पुराने बंधनों और पिंजरों से मुक्त होना चाहते हैं।' इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी दस नई पहल की जानकारी भी दी। इसमें 'आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस फार आल' भी शामिल है, जिसके तहत शिक्षा प्राप्ति के सभी चरणों में छात्रों को एआइ से संबंधित कोर्स करना होगा।

देखा जाए तो हाल के दिनों में आल इंडिया काउंसिल फार टेक्निकल एजुकेशन (एआइसीटीई) द्वारा भी तकनीकी शिक्षा में बदलाव लाने की दिशा में कई अहम कदम उठाए गए हैं, ताकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पारंपरिक तकनीकी शिक्षा को और ज्यादा समावेशी बनाया जा सके। इस क्रम में पहला बदलाव एंट्री लेवल विषयों में किया गया है। एआइसीटीई का मानना है कि वर्तमान में, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दाखिले फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के पारंपरिक विषयों पर आधारित हैं, जो नये दौर के मल्टीडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण की जरूरत को देखते हुए एक तरह से बाधा है। 21वीं सदी में जैव-प्रौद्योगिकी, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे नये सब-डोमेन के आने से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं के बीच अभी तक चली आ रही पारंपरिक व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। इन सब-डोमेन में कुशलता हासिल करने के लिए बायोलाजी, सांख्यिकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वोकेशनल स्ट्रीम्स जैसे एलायड विषयों के समझ की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पहले की तरह सिर्फ मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहा जा सकता। समय के साथ प्रासंगिक बने रहने के लिए कुछ दूसरे नये विषयों को भी जोड़े जाने की जरूरत है।

अनुमोदन प्रक्रिया में बदलाव: तकनीकी शिक्षा को इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुकूल बनाने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021 से अनुमोदन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। माना जा रहा है कि एआइसीटीई की इस पहल से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की सोच रखने वाले छात्रों को विषयों के चयन में काफी आसानी होगी यानी अब इंजीनियरिंग करने के लिए गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान, इंफार्मेशन प्रैक्टिसेज, जैव प्रौद्योगिकी, तकनीकी व्यावसायिक विषय, कृषि, बिजनेस स्टडी या उद्यमिता जैसे कोई भी तीन विषय होने चाहिए। प्रवेश स्तर की योग्यताओं को व्यापक बनाकर डोमेन के विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में शिक्षाविदों को भी इससे काफी मदद मिलेगी और वे इंटर-डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे।

समावेशी शिक्षा पर जोर: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा पर काफी जोर दिया गया है। एआइसीटीई द्वारा उठाए गए कदमों को भी इसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। ऐसे में किसी भी अनदेखे भय/आशंका या पूर्वाभास से चिंतित होने के बजाय यथास्थिति की व्यवस्था को तोड़ने वाले कदमों का स्वागत किया जाना चाहिए। तकनीकी शिक्षा में बदलाव क्यों जरूरी है, इसके लिए चिकित्सा विज्ञान का ही उदाहरण ले लीजिए। टोमोग्राफी या न्यूक्लियर मेडिसिन में गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के कई तत्व आपस में किसी न किसी रूप में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में किसी भी डोमेन में विषयों की कोई सीमा तय नहीं की जा सकती।

वैसे भी, शिक्षा तो उत्कृष्टता और परिणाम प्राप्त करने के लिए ही है। असल में, यह पहल खोये ज्ञान को फिर से खोजने की एक कोशिश है। इसी ने शिक्षा मंत्रालय को एआइसीटीई में इंडियन नालेज सिस्टम्स (आइकेएस) डिवीजन स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, जिसका उद्देश्य देश की समृद्ध विरासत और पारंपरिक ज्ञान के आधार पर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को और बढ़ावा देना है। ऐसे में हमारे वेद-पुराणों में निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों की पुनः खोज और प्राचीन ज्ञान से जुड़ने से हमारी रचनात्मकता को और बल मिलेगा।

क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम: एआइसीटीई द्वारा अप्रूवल प्रासेस हैंडबुक में भी बदलाव किया गया है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य योग्यता और कौशल को व्यावहारिक बनाते हुए इसे अधिक समावेशी बनाना है। दरअसल, एक छात्र की प्राकृतिक क्षमता को समृद्ध बनाने के लिए जो साधन चाहिए, उसी के लिए माडल पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत चार मैथमेटिक्स कोर्सेज, दो फिजिक्स कोर्सेज तथा केमिस्ट्री और बायोलाजी में एक-एक कोर्स की बात कही गई है। इस दिशा में ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए मैसिव ओपन आनलाइन कोर्स (एमओओसी) को अपनाया गया है। इसका क्रेडिट सिस्टम औपचारिक डिग्री प्राप्त करने में भी मान्य होगा। इसी तरह, भाषा की बाधा को दूर करने के लिए एआइसीटीई ने 'स्वयं' मंच पर उपलब्ध सभी पाठ्यक्रमों का आठ भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने की पहल की है। इंडक्शन प्रोग्राम भी ऐसी ही एक पहल है।

14 एंट्री लेवल विकल्प की उपलब्धता: देश के विकास के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर तकनीकी शिक्षा की प्रगति को केवल एंट्री लेवल विषयों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। इसलिए शैक्षणिक वर्ष 2021 से छात्रों को अप्रूवल प्रासेस हैंडबुक में 14 एंट्री लेवल विकल्प प्रदान किए गए हैं, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों के उन मेधावी छात्रों को भी समान अवसर मिल सके, जो किसी कारण ग्यारहवीं/बारहवीं में अपने पारंपरिक एंट्री विषयों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उन्हें डिग्री प्रोग्राम में शामिल होने से पहले ई-लर्निंग के तहत एडिशनल कोर्स कराया जाएगा।

एक वर्षीय प्रारंभिक पाठ्यक्रम की शुरुआत

देश में ऐसे कई डिप्लोमा छात्र होते हैं, जो खुद को आगे बढ़ाने और उत्कृष्टता हासिल करने की दिशा में अनुकरणीय उदाहरण पेश करते हैं। सोचिए, अगर उन्हें आगे बढ़ने का मौका न मिले, उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाए, तो क्या वे प्रतिभाएं आगे बढ़ने से रुक नहीं जाएंगी और इससे हमारी राष्ट्रीय संभावनाओं को गहरा आघात नहीं पहुंचेगा। आइआइटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान अभी तक अपने ब्रांड की वजह से बहुत ही ऊंचे प्रवेश मानदंड का पालन करते हैं। ऐसे में अगर कोई छात्र जो गणित/भौतिकी/रसायन विज्ञान में कमजोर है, लेकिन कटआफ की न्यूनतम सीमा क्वालीफाइ कर लेता है, उसे अब प्रासंगिक विषयों में एक साल का प्रारंभिक पाठ्यक्रम कराया जाएगा, ताकि उसे फिर से प्रशिक्षित करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके।



सक्सेस मंत्रा

रजत गांधी
सीईओ, फेयरसेंट

बड़ी सोच के साथ चाहिए कड़ी मेहनत

बैंकों की लंबी-चौड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय ग्राहकों को न्यूनतम दर पर एवं आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रजत गांधी ने अपने दो अन्य सह-संस्थापकों के साथ मिलकर आनलाइन पीयर टु पीयर लेंडिंग प्लेटफार्म 'फेयरसेंट' की नींव रखी थी। यह देश का पहला लेंडिंग प्लेटफार्म है, जो आरबीआइ द्वारा एनबीएफसी-पीटुपी लाइसेंस प्राप्त है। 2020-21 के वित्तीय वर्ष में प्लेटफार्म से करीब 1,145 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। इससे पहले के वित्तीय वर्ष में करीब 120 करोड़ रुपये के लोन का वितरण किया गया था। एक मार्केटर, स्ट्रेटेजिस्ट एवं ब्रांड बिल्डर के तौर पर 20 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले कंपनी के सीईओ रजत कहते हैं कि, 'कोरोना काल चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन पीटुपी लेंडिंग प्लेटफार्म्स ने 12 से 14 फीसद की ग्रोथ दर्ज की है। मैं मानता हूं कि हमें बड़ा एवं सकारात्मक सोचने के साथ-साथ हमेशा कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना चाहिए।'

दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और फिर एमबीए करने के बाद रजत ने एक बड़े मीडिया ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वहां 14 वर्ष काम करने के दौरान उन्होंने तमाम तरह के नये कदम उठाए। इसके बाद उन्होंने परफार्मिक्स कंपनी ज्वाइन की, जो शिकागो स्थित पब्लिसिस ग्रुप की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी। रजत बताते हैं, 'मैंने शुरुआती दौर में ही देश में इंटरनेट को बढ़ते हुए देखा है। आनलाइन रोजगार एवं वैवाहिक कंपनी संचालित करने के अपने अनुभवों के मद्देनजर जब खुद की पीयर टु पीयर आनलाइन लेंडिंग कंपनी फेयरसेंट शुरू की, तो खास मुश्किल नहीं हुई।'

निजी अनुभवों से आइडिया: रजत कहते हैं कि पीटुपी का आइडिया कुछ निजी अनुभवों से आया। मेरे एक सहयोगी अलग-अलग दोस्तों से छोटे कर्ज लिया करते थे। एक बार उन्हें मोटरसाइकिल खरीदनी थी। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट डालकर दोस्तों एवं परिवारवालों से आर्थिक मदद मांगी। एक हफ्ते में ही वह अपनी मोटरसाइकिल से आफिस आने लगे। इस तरह की कई अन्य घटनाओं एवं मेरे पूर्व के अनुभवों ने फेयरसेंट की नींव रखने में मदद की। 2011 में जब आइडिया पर काम करना शुरू किया, तब पीटुपी फाइनेंस के लिए इकोसिस्टम पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। बिजनेस को स्केलेबल बनाना और विश्वसनीयता कायम करना। लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री को जानने या परखने के लिए कोई क्रेडिबल ब्यूरो डेटा नहीं था। इसके अलावा, डिजिटल पेमेंट के विकल्प भी नहीं थे। दो साल लगे। फिर अपने सह-संस्थापक एवं कंपनी के सीओओ विनय मैथ्यू एवं नितिन गुप्ता के साथ मिलकर 2014 में हमने इसे लांच किया।

ईमानदारी से समझौता नहीं: इस इंडस्ट्री में निवेश हो रहे हैं। विस्तार हो रहा है। नई एवं इनोवेटिव टेक्नोलाजी आ रही है। रजत कहते हैं, हमारा अब तक का सफर चुनौतियों से भरा, लेकिन संतोषप्रद रहा है। हमारी इस पहल से लोगों को काफी फायदा हुआ है। यही मुझे नई वित्तीय व्यवस्था बनाने के लिए प्रेरित करता है और मैं आगे बढ़ता जाता हूं। मैं हर किसी के सुझावों पर ध्यान देने के बजाय अपने अच्छे सुझावों पर विश्वास करता हूं।

बातचीत : अंशु सिंह



फोटो : इमेजेज बाजार

कार्यक्षेत्र की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में विश्वास

भारत में बहुत बड़ा क्रेडिट गैप है। यहां एक बड़ी आबादी आज भी बैंकों का फायदा या तो बिल्कुल ही नहीं या फिर बहुत कम उठा पा रही है। ऐसे में पीटुपी लेंडिंग प्लेटफार्म ग्राहकों को आकर्षक रिटर्न देने के साथ ही विविध पोर्टफोलियो बनाने में मदद करते हैं। रजत की मानें, तो मांग एवं आपूर्ति को जोड़ते हुए इनकी कंपनी ने निवेश के लिए लोगों को वैकल्पिक माध्यम दिया है। इससे लघु एवं मध्यम उद्यमियों के साथ ही पर्सनल लोन आसानी से मिल पा रहे हैं। वह कहते हैं, यह सच है कि पीटुपी लेंडिंग स्पेस में अनेक आनलाइन प्लेटफार्म हैं। लेकिन आरबीआइ द्वारा सभी पीटुपी आनलाइन कंपनियों को एनबीएफसी-पीटुपी में रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्यता से सही कंपनी ही सर्वाइव कर पाएगी। मैं मानता हूं कि किसी भी सेक्टर में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का होना अच्छा होता है।



लाइफ स्किल

डा. अनिल सेठी
मोटिवेटर एवं लाइफ कोच

कामयाबी के लिए करें अपनी टीम को प्रेरित

आज के भौतिकवादी दौर में हर तरफ प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में समय और हालात किसी के लिए भी अच्छे और खराब हो सकते हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। समस्या के बाद भी आप कितने विश्वासी दिखते हैं। कहते हैं सफलता के कई पैरेंट्स होते हैं और असफलता अनाथ होती है। इस बारे में मुझे पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ा एक वाकया बहुत याद आता है जो कि हमें सही राह भी दिखाता है। जब वह प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर एसएलवी 3 का प्रक्षेपण करने के लिए सात वर्षों से अथक प्रयास कर रहे थे और अंततः 1979 में वह घड़ी भी आ गई, जब इस उपग्रह का प्रक्षेपण होना था। यह हमारा अंतरिक्ष में पहला प्रयास था, जब प्रक्रिया शुरू हुई तो पहले चरण में सब कुछ ठीक था। सब सांस रोककर इसको देख रहे थे। तभी दूसरे चरण में उपग्रह नियंत्रण से बाहर हो गया। 317 सेकंड के बाद पूरा ढांचा समुंद्र में गिर गया। पूरी टीम पर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। ये पल सबके लिए सदमे से कम नहीं थे। उस दिन एक प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया था।

संगठन के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन ने स्वयं पत्रकारों के सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे आत्मविश्वास के साथ दिए और कहा कि ये अभियान बहुत जटिल होते हैं और हम इसकी पूरी जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या कमी रह गई और आने वाले एक वर्ष के अंदर हम पुनः इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करेंगे। उनकी बातों ने टीम के अंदर एक नया आत्मविश्वास भर दिया। 18 जुलाई, 1980 को प्रक्षेपण की वह घड़ी आ गई और इस बार हम सफल हुए। यह भारत का अंतरिक्ष में पहला कदम था। इस कामयाबी से भारत अंतरिक्ष में उपस्थित विश्व के थोड़े से देशों में शामिल हो गया था। इस बार भी प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन था और प्रोफेसर धवन ने इस बार माइक मेरे आगे कर दिया और मुझे सारे जवाब देने दिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे लीडरशिप का सबसे बड़ा सबक सीखने को मिला।

किसी भी फील्ड में एक सच्चा लीडर हमेशा असफलता का दोष अपने ऊपर ले लेता है और सफलता का श्रेय अपनी टीम को देता है। क्योंकि आप एक कामयाब या इफेक्टिव लीडर तभी होंगे, जब आपकी टीम भी उतनी ही कामयाब होगी। इसलिए अपनी टीम को हमेशा प्रोत्साहित करें। सबको और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करें।



फोटो : विजुअल स्टाक

आज का भविष्यफल

के.ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: 31 जुलाई, 2021 शनिवार श्रावण मास कृष्ण पक्ष सप्तमी का राशिफल।
आज का राहुकाल: प्रातः 09:00 बजे से 10:30 बजे तक।
आज का दिशाशूल: पूर्व।
विशेष: सप्तमी तिथि की वृद्धि।

मेष: भावुकता में लिया गया निर्णय कष्टकारी हो सकता है। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। स्थानांतरण, विभागी परिवर्तन आदि की दिशा में सफलता मिल सकती है।

वृष: उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन सुखमय होगा।

मिथुन: शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। धर्म गुरु या पिता का सहयोग मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा।

कर्क: बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। किसी कार्य के संपन्न होने आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

सिंह: जीवनसाथी का सहयोग एवं सान्निध्य मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।

कन्या: रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी।

तुला: आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा।

वृश्चिक: शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सामाजिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यक्ति विशेष के कारण तनाव मिलेगा। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे।

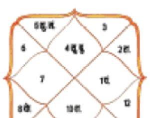
धनु: शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया श्रम सार्थक होगा। बुद्धि कौशल से किया गया प्रयास लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।

मकर: सामाजिक कार्य में रुचि लेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होंगे। नए संबंध बनेंगे।

कुंभ: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यक्ति विशेष के कारण तनाव मिलेगा। संयम बरतें। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

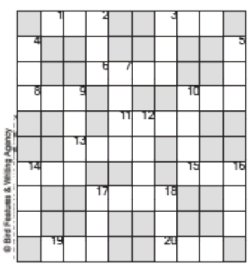
मीन: उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी। बहुप्रतिष्ठित कार्य के संपन्न होने से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में प्रगति होगी।

कल 1 अगस्त का पंचांग



कल का दिशाशूल: पश्चिम।
विक्रम संवत 2078 शके 1943 दक्षिणायन, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु श्रावण मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी 07 घंटे 57 मिनट तक, तत्पश्चात् नवमी भरणी नक्षत्र 19 घंटे 36 मिनट तक, तत्पश्चात् कृतिका नक्षत्र गण्ड योग 22 घंटे 01 मिनट तक, तत्पश्चात् वृद्धि योग मेष में चंद्रमा 26 घंटे 33 मिनट तक तत्पश्चात् वृष में।

वर्ग पहेली-1653



© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं
1 [illegible] [3]। 3 [illegible] [3]। 6 [illegible] [4]। 8 [illegible] [3]। 10 [illegible] [3]। 11 [illegible] [4]। 13 [illegible] [4]। 14 [illegible] [3]। 15 [illegible] [3]। 17 [illegible] [4]। 19 [illegible] [3]। 20 [illegible] [3]।

ऊपर से नीचे
2 [illegible] [3]। 3 [illegible] [3]। 4 [illegible] [3]। 5 [illegible] [3]। 7 [illegible] [4]। 9 [illegible] [2,2]। 10 [illegible] [4]। 12 [illegible] [4]। 14 [illegible] [3]। 16 [illegible] [3]। 17 [illegible] [3]। 18 [illegible] [3]।

कल का हल

अ	जे	य					प	रा	या
म			नो		क	प	ट		च
नं	जं	रा	ना				स		क
	त		नि		अ	मा	न	त	
	झा		भं	रं	ती				
				नि	न	शे		पौ	
	हे	रं	बा	जा		र		द	
कं		स				त्रं	च	प	नं
पा		खौ	न	ना		त			ला
लो	ह	र					खे	ल	ना

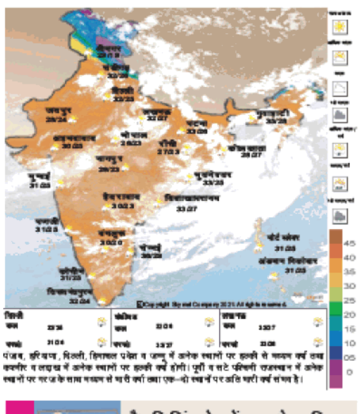
जागरण सुडोकू-1653

5								7
		8		2	1	5	6	
1	9					8		
	5			4			8	
	8	1			7	6		4
			9				3	
8	1			9		4	5	
		5	1		4		2	
9				5				3

कल का हल

3	6	5	9	2	4	7	1	8
2	9	7	6	8	1	3	4	5
1	8	4	7	3	5	2	9	6
8	2	9	1	6	7	5	3	4
4	7	1	2	5	3	8	6	9
6	5	3	8	4	9	1	2	7
7	4	2	5	1	6	9	8	3
5	1	6	3	9	8	4	7	2
9	3	8	4	7	2	6	5	1

मौसम



कल पढ़ें



कैटफिशिंग से रखें खुद को सुरक्षित

आजकल लोग दोस्ती के लिए आनलाइन प्लेटफार्म का खूब इस्तेमाल करते हैं, मगर दोस्ती की चाहत में कैटफिशिंग से सुरक्षित रहना जरूरी है। यह ऐसा जोखिम है, जो बैंक बैलेंस भी खाली कर सकता है। जानें कैटफिशिंग से खुद को सुरक्षित रखने के तरीके...

अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर पहली बार चलाया रोवर

वर्ष 1971 में आज ही अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार चांद पर रोवर से सैर की थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने अपोलो-15 अभियान में डेविड आर स्काट, जेम्स बी इरविन, अल्फ्रेड एम वार्डेन को चांद पर भेजा था।





पहली राज्य परिवहन सेवा की कोलकाता में शुरुआत

वर्ष 1948 में आज ही पहली राज्य परिवहन सेवा की कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में शुरुआत हुई थी। उस समय 25 बसों के साथ छह शहरों के लिए सेवा शुरू की गई थी। 1949 में डीजल की दो डबल डेकर बसें शामिल की गईं।

दारा सिंह के साथ फिल्मों ने बदल दी थी मुमताज की किस्मत

बतौर जूनियर आर्टिस्ट करियर शुरू करने वाली मुमताज का जन्म आज ही 1947 में मुंबई में हुआ था। छोटे-छोटे रोल कर रही मुमताज को दारा सिंह के साथ फिल्म ने बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। दोनों ने 16 फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें 10 हिट रहीं। इसके बाद, राजेश खन्ना के साथ 'दो रास्ते' से यह जोड़ी फिल्म हिट होने का फार्मूला बन गई थी। खिलौना के लिए 1971 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। 27 साल की उम्र में बिजनेसमैन मयूर मधवानी से शादी के बाद वह फिल्मों से दूर हो गईं।



टाइप 2 डायबिटीज से बचा सकता है मोटा अनाज

अध्ययन ▶ ग्लायसेमिक रिस्पांस बेहतर होने से डायबिटीज के जोखिम कम करने और इलाज में है कारगर

11 देशों में किए गए शोध का विश्लेषण फ्रंटियर इन न्यूट्रिशन में हुआ प्रकाशित

हैदराबाद, आइएएनएस : खानपान में संयम से बहुत सारे रोगों से बचाव किया जा सकता है। इस संबंध में लगातार शोध भी चलते रहते हैं। अब एक नए शोध में सामने आया है कि जौ-बाजरा जैसे मोटे अनाज शरीर के ब्लड शुगर को मैनेज करने में बड़ा सहायक होते हैं और इसे खाने से डायबिटीज टाइप 2 का जोखिम कम किया जा सकता है।

इस शोध के आधार पर जौ-बाजरा युक्त उपयुक्त आहार तैयार किया जा सकता है, जिससे डायबिटिक तथा प्री-डायबिटक लोगों को तो फायदा होगा ही और इसके साथ ही यह डायबिटीज की रोकथाम में कारगर हो सकता है।

इस संबंध में 11 देशों हुए शोध का विश्लेषण फ्रंटियर इन न्यूट्रिशन जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने जौ-बाजरा युक्त आहार का सेवन किया, उनमें खाने से पहले (फास्टिंग) और खाने के बाद (पोस्ट मील) ब्लड शुगर लेवल में 12-15 तथा 37 अंकों तक की गिरावट देखी गई। इस तरह ब्लड ग्लूकोज का लेवल डायबिटिक से प्री-डायबिटिक स्तर तक पहुंच गया। प्री-डायबिटिक लोगों में एचबीए1सी (ब्लड ग्लूकोज से जुड़ा हीमोग्लोबिन) के स्तर में औसतन 17 और 37 तक की कमी देखी गई, जिससे प्री-डायबिटिक व्यक्ति सामान्य की श्रेणी में आ गए। इन निष्कर्षों से पुष्टि होती है कि जौ-बाजरा जैसे मोटे अनाज खाने से ग्लायसेमिक रिस्पांस बेहतर होता है।

इंटरनेशनल क्राप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फार द सेमी-एरिड ट्रापिक्स (आइसीआरआइएसएटी) के मुताबिक, शोध के लेखकों ने इस मामले में 80



आहार में बढ़ाएं मोटे अनाज की मात्रा। फाइल फोटो

प्रकाशित अध्ययनों की समीक्षा की, जिनमें से 65 व्यापक विश्लेषण के योग्य थे और इसमें तकरीबन एक हजार लोगों की सहभागिता थी। इससे यह विश्लेषण सबसे बड़ा व्यवस्थित समीक्षा बन पड़ा। अब तक यह बात किसी को नहीं मालूम था कि डायबिटीज पर जौ-बाजरा जैसे मोटे अनाज को लेकर इतने ज्यादा वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं। लेकिन इनमें बताए गए फायदों को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

अध्ययन की मुख्य लेखिका आइसीआरआइएसएटी की वरिष्ठ पोषण विज्ञानी डाक्टर एस. अनिता ने बताया कि अब इस व्यापक और व्यवस्थित समीक्षा के वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित होने से यह विश्वास जमा है कि जौ-बाजरा ग्लूकोज के स्तर पर अंकुश रखता है और डायबिटिज का जोखिम कम करता है।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ न्यूट्रिशन (एनआइएन) की निदेशक हेमलता के मुताबिक, भारत में डायबिटीज रोगियों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। इनके इलाज पर भारी-भरकम राशि खर्च हो रहा है। इसका कोई आसान समाधान भी नहीं है। इसलिए जरूरी है कि जीवनशैली में बदलाव लाई जाए, जिसमें खानपान बहुत ही अहम है। इस तरह यह अध्ययन व्यक्ति और सरकार दोनों के स्तर पर एक उपयोगी समाधान उपलब्ध करा सकता है। इसके आधार पर कार्यक्रमों का सुसंगत नियोजन किया जा सकता है।

इंडियन नेशनल टेक्निकल बोर्ड आफ न्यूट्रिशन के प्रतिनिधि तथा अध्ययन के सह लेखक राज भंडारी का कहना है यदि हम जौ-बाजरा जैसे मोटे अनाज को आहार का मुख्य हिस्सा बनाएं तो न सिर्फ डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, बल्कि पोषण भी बढ़ा सकते हैं।

इंटरनेशनल डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक, डायबिटीज के रोगियों संख्या दुनिया के सभी हिस्सों में तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें भारत, चीन और अमेरिका जैसे देश सबसे आगे हैं। ऐसे में जौ-बाजरा को मुख्य आहार में शामिल डायबिटीज के बढ़ते प्रसार को थामा जा सकता है।

अध्ययन में पाया गया कि जौ-बाजरा का औसत ग्लायसेमिक इंडेक्स (जीआइ) 52.7 होता है, जो पके हुए चावल और रिफाइंड गेहूं से कम है। जीआइ एक ऐसा संकेतक है, जो बताता कि कोई खाद्य पदार्थ कितनी जल्दी ब्लड शुगर बढ़ा देता है। इसमें जीआइ 55 को कम या जीआइ 55-69 को मध्यम श्रेणी का माना गया है।



मसाने बीच का जंगल विश्व विरासत सूची में शामिल

फ्रांस के अर्जेलेस सुर-मेर में स्थित मसाने बीच के इन बेहद खूबसूरत जंगलों को यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। इसके अलावा तीन अन्य स्थानों को भी यह दर्जा दिया गया है। एएफपी

इधर-उधर की

दो साल बाद समाचार में दिख गया बिछड़ा कुत्ता

विस्कांसिन, एजेंसी : जिंदगी में कई बार कुछ ऐसा हो जाता है, जिसकी उम्मीद नहीं होती। अमेरिका के विस्कांसिन में एक परिवार के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। यह परिवार स्थानीय चैनल पर जब पालतू जानवरों से संबंधित समाचार देख रहा तो उनकी खुशी का उस समय ठिकाना नहीं रहा, जब उन्हें अपना वह कुत्ता दिख गया, जो दो साल पहले गुम हो गया था। चैनल वालों से संपर्क किए जाने पर उन्हें उनके बिछड़े कुत्ते से मिला दिया गया। विस्कांसिन ह्यूमन सोसायटी ने इंटरनेट मीडिया पर इसका वीडियो पोस्ट किया है, जिसे लोग खासा पसंद कर रहे हैं।



चैनल पर पालतू कुत्तों के बारे में दी जा रही थी जानकारी। इंटरनेट मीडिया

फेफड़ों के ट्यूमर पर अब हो सकेगा सटीक वार

जागरण संवाददाता, लखनऊ

फेफड़ों के ट्यूमर का रेडियोथेरेपी से सुरक्षित और कारगर इलाज की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अब नई तकनीक से ट्यूमर पर सीधे और अधिक प्रभावी तरीके से वार करना संभव होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि सीधे ट्यूमर पर रेडियोथेरेपी देने से ट्यूमर के आसपास की कोशिकाएं प्रभावित नहीं होंगी या बहुत कम होंगी, जिससे रेडियोथेरेपी का साइड इफेक्ट भी काफी कम होगा।

इसके लिए संजय गांधी पीजीआइ के रेडियोथेरेपी विभाग के प्रो. जेके मारिया दास, डा. योगनाथन, प्रो. शालीन कुमार और आइआइटी कानपुर के डा. आशीष दत्ता ने विशेष प्लेटफार्म (प्रोग्राम) तैयार किया है, जिसका परीक्षण लंग कैंसर के मरीजों पर काफी उत्साहजनक रहा है। इस प्रोग्राम को 3डी रोबोटिक मोशन प्लेटफार्म नाम दिया गया है। इस सफलता को इंडियन कैंसर कांग्रेस, बेंगलुरु में प्रस्तुत किया गया, जहां इसे काफी सराहना मिली।

प्रो. मारिया दास ने बताया कि फेफड़ों के ट्यूमर की गति सांस लेने की प्रक्रिया के साथ जुड़ी होती रहती है। हर व्यक्ति में गति की दिशा अलग-अलग होती है। कोई निश्चित दिशा गति की नहीं होती है। ट्यूमर पर रेडिएशन देते समय गति के कारण रेडिएशन ट्यूमर के आलावा आसपास के कोशिकाओं पर पड़ती है। इन कोशिकाओं को बचाने के लिए हल्की मात्रा में रेडिएशन देनी पड़ती है, तब भी सेल प्रभावित होते हैं। हमारे पास ऐसी रेडिएशन मशीन थी, जिससे ट्यूमर पर सीधे वार संभव था, लेकिन हर मरीज में अलग-अलग गति होती है और मशीन कितना सही काम कर रही है, यह पुष्टि नहीं हो पा रही थी। इस परेशानी से निजात पाने के लिए हम लोगों ने आइआइटी कानपुर के डा. आशीष दत्ता के साथ कार्ययोजना तैयार की। डा. दत्ता ने पूरा प्रोग्राम बनाया। हम लोगों ने मरीजों का सीटी डाटा दिया, जिसके आधार पर तैयार प्लेटफार्म का मरीजों पर परीक्षण किया गया।

उपलब्धि

- आइआइटी कानपुर और पीजीआइ ने मिलकर तैयार किया 3डी रोबोटिक मोशन प्लेटफार्म
- सांस की गति के साथ ट्यूमर की बदलती दिशा को निशाना बना दी जा सकेगी रेडियोथेरेपी



ट्यूमर का होगा सुरक्षित और कारगर इलाज। फाइल फोटो

लंग कैंसर मरीज का सीटी डाटा किया जाता है फीड

लंग कैंसर के मरीज का 4डी सीटी स्कैन करने के बाद ट्यूमर की स्थिति को तैयार किए गए प्लेटफार्म (प्रोग्राम) में फीड किया जाता है। यह प्लेटफार्म ट्यूमर के गति के साथ काम करता है, जैसे सही निशाना मिलता है रेडिएशन मशीन सीधे ट्यूमर पर रेडिएशन डालती है। इससे अधिक मात्रा में रेडिएशन देना भी संभव होता है। इस तकनीक का मरीजों पर भी परीक्षण किया गया, जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं। यह प्लेटफार्म डिपार्टमेंट आफ साइंस एंड टेक्नोलाजी के सहयोग से तैयार किया गया है।

याददाश्त पर भी असर डाल सकता है कोरोना संक्रमण

अनुसंधान



कोरोना के साइड इफेक्ट। फाइल फोटो

कोरोना वायरस (कोविड-19) की चपेट में आने वाले कई लोगों की सेहत पर इस खतरनाक वायरस का गहरा असर पड़ रहा है। इसका दीर्घकालीन प्रभाव पाया जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी दूसरी कई गंभीर समस्याओं का खतरा भी पैदा हो रहा है। अब एक नए अध्ययन का दावा है कि कोरोना संक्रमण का याददाश्त पर भी असर पड़ सकता है। इस खतरनाक वायरस का संबंध भूलने की बीमारी अल्जाइमर समेत सोचने और समझने की क्षमताओं में कमी से पाया गया है।

अमेरिकी अल्जाइमर एसोसिएशन की अगुआई वाले एक वैश्विक समूह के विशेषज्ञों ने यह पाया कि कोरोना से उबरने के बावजूद कई बुजुर्ग सूंघने की क्षमता में कमी समेत याददाश्त में गिरावट की समस्या से जूझ रहे हैं। इन पीड़ितों में ब्रेन इंजरी, न्यूरो इंफ्लेमेशन और अल्जाइमर से परस्पर गहरा ताल्लुक रखने वाले तंत्रिका तंत्र संबंधी लक्षणों की मौजूदगी पाई गई। अध्ययन के नतीजों के अनुसार, कोरोना संक्रमण के बाद याददाश्त में गिरावट का सामना करने वाले लोगों में कम ब्लड आक्सीजन का खतरा भी ज्यादा पाया गया। शोधकर्ताओं ने कहा कि कोरोना महामारी के कहर से दुनियाभर में स्वास्थ्य के मोर्चे पर गंभीर असर पड़ा है। हम इस बात का पता लगाने के लिए निरंतर अध्ययन के कर रहे हैं कि इसका हमारे शरीर और मस्तिष्क पर कैसा असर पड़ रहा है। अध्ययन से जुड़े अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अर्जेंटीना में कोरोना पीड़ित करीब 300 बुजुर्गों पर शोध किया। कोरोना को मात देने वाले इन बुजुर्गों में से आधे से ज्यादा में भूलने की समस्या पाई गई। -आइएएनएस

स्क्रीन शॉट

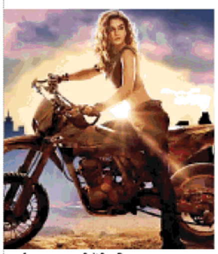
इंटरनेट मीडिया से ब्रेक लेना जरूरी मानती हैं सारा जेन डायस



डिजिटल डिटाक्स ब्रेक पर थीं सारा। इंस्टाग्राम

इंटरनेट मीडिया को लेकर सबकी अपनी पसंद-नापसंद है। कई लोग इस पर बहुत वक्त बिताते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनका मानना है कि कभी-कभार इंटरनेट मीडिया से ब्रेक भी लेना चाहिए। अभिनेत्री सारा जेन डायस ने इसे बहुत अच्छा नाम भी दिया है। इंस्टाग्राम पर लाइव चैट के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था कि कुछ दिन बाद लाइव आऊंगी, लेकिन फैंस की वजह से मुझे आना पड़ा। दरअसल, मैं पिछले कई दिनों से इंस्टाग्राम पर कुछ भी पोस्ट नहीं कर रही हूं। ऐसे में मेरे फैंस पूछने लग गए थे कि मैं कहां हूं, कहीं मेरी तबियत तो खराब नहीं है। मैं उन सबको बताना चाहती हूं कि बिल्कुल ठीक हूं। मैं डिजिटल डिटाक्स ब्रेक पर थी। मुझे इंटरनेट मीडिया की निगेटिविटी से ब्रेक चाहिए था, इसलिए मैं दूर थी। शायद आप सबको सुनने में अजीब लगे, लेकिन मेरे लिए यह बहुत ही सामान्य है। मैं अक्सर इंटरनेट मीडिया से ब्रेक लेती रहती हूं, न कुछ पोस्ट करती हूं, न ही किसी के कमेंट्स पढ़ती हूं। इंटरनेट मीडिया के अलावा मेरी अपनी जिंदगी भी है। खुद के लिए भी वक्त चाहिए, जरूरी नहीं कि मैं अपने जीवन में जो भी करूं, उसको इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करूं। मैंने अब डिजिटल डिटाक्स ब्रेक को अपनी आदत में शामिल कर लिया है। इस लाइव के दौरान सारा ने बताया कि वह जल्द ही अपनी आगामी वेब सीरीज की शूटिंग शुरू करेंगी, जो इस साल के अंत में रिलीज होगी। इस मौके पर एक फैन ने उनसे पूछा कि क्या वह सिंगल हैं? इस पर सारा ने हंसते हुए जवाब दिया कि हां, बिल्कुल सिंगल हूं, कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, तो मैं शादी भी कर सकती हूं।

हिंदी फिल्मों में एक्शन करने वाली कुछ चुनिंदा अभिनेत्रियों की सूची में कृति सैनन का भी नाम जुड़ रहा है। वह पहले कई मौकों पर एक्शन भूमिकाएं निभाने की इच्छा जता चुकी हैं और टाइगर श्राफ के साथ अगली फिल्म में उनकी चाहत पूरी हो रही है।



डर्ट बाइक चलाना सीखेंगी कृति। ● इंस्टाग्राम

गणपत में एक्शन करती दिखेंगी कृति

अब कई अभिनेत्रियां ऐसी फिल्में चुन रही हैं, जिनमें उन्हें एक्शन करने का मौका मिले। इसी कड़ी में कृति सैनन का भी नाम जुड़ गया है। कृति को फिल्म गणपत में टाइगर श्राफ के साथ एक्शन करने का मौका मिल रहा है। यह फिल्म दो पार्ट में बनने वाली है। जल्द गणपत पार्ट 1 पर काम शुरू होगा, जिसमें उन्हें बहुत सारा एक्शन करते देखा जा सकेगा। दैनिक जागरण से बातचीत में एक्शन की तैयारियों के सवाल पर कृति ने कहा कि फिल्म के बारे में अभी बात करना यूं तो जल्दबाजी है, लेकिन मैं इसमें एक्शन करने को लेकर बहुत उत्सुक हूं। गणपत फिल्म का जो मोशन पोस्टर आया था, उसमें मैं एक डर्ट बाइक (यह मोटरसाइकिल की ही तरह होती है, जिसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है) पर बैठी नजर आ रही हूं। दरअसल, वह बाइक मुझे फिल्म में चलानी होगी। डर्ट बाइक एक अलग तरह की बाइक होती है, जिसका पावर बहुत ज्यादा होता है। मैंने हाल ही में बुलेट चलानी सीखी है, लेकिन प्रोफेशनल बाइकर लगने के लिए और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डर्ट बाइक को चलाना अभी तक मैंने नहीं सीखा है। उसे भी सीखने के लिए उत्सुक हूं। गणपत फिल्म का निर्देशन विकास बहल करने वाले हैं।

हिंदी में बात करने पर आज की पीढ़ी अनाड़ी समझती है : श्वेता तिवारी

कई सालों से टीवी इंडस्ट्री में काम करते आ रही श्वेता त्रिपाठी इन दिनों खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में नजर आ रही हैं। कसौटी जिंदगी की से लेकर मेरे डैड की दुल्हन तक श्वेता कई शोज कर चुकी हैं। नई पीढ़ी के साथ काम करने और उनसे बेहतर परफार्म करने की मुश्किलों को लेकर दैनिक जागरण से बातचीत में श्वेता ने कहा कि आज की पीढ़ी से मुकाबला करना हर तरीके से बहुत मुश्किल है। पहले के मुकाबले अब फिटनेस को लेकर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहले हम ज्यादातर हिंदी में ही बात करते थे। हिंदी अगर आए, तो भी काम चल जाता था, लेकिन आज अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाएं अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप सिर्फ हिंदी में बात करेंगे, तो आज के युवाओं को लगता है कि यह तो अनाड़ी है, हालांकि उनकी यह सोच गलत है, लेकिन कई बार उनसे बहस करना बेमानी लगता है। आजकल चार लाइनों में एक लाइन हिंदी और बाकी की तीन लाइन अंग्रेजी में बोलनी पड़ती है। दोनों भाषाओं में सहज होना बहुत जरूरी हो गया है।



युवाओं से प्रतिस्पर्धा करने में मजा आ रहा है श्वेता को। इंस्टाग्राम

एकदम गोल रोटियां बनाता हूं, जिसके लिए तारीफें भी मिलती हैं : कैलाश खेर

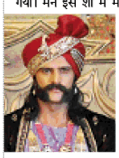
गाना और खाना बनाना दोनों ही काम बड़े मुश्किल हैं। बात करें अगर गायक कैलाश खेर की तो यह दोनों ही काम वह बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान कैलाश ने कहा कि मैं गाने के अलावा खाना भी बहुत स्वादिष्ट बना लेता हूं। अक्सर लोगों को रोटियां बनाना सबसे मुश्किल काम लगता है, लेकिन मैं रोटियां एकदम गोल बनाता हूं। इसके लिए मुझे तारीफें भी मिलती हैं। रोटी बेलना और सेंकना भी एक कला है। गोल रोटियां नरम भी होनी चाहिए। मैं दिल्ली से हूं। उत्तर भारत के लोग शुद्ध खाना पसंद करते हैं। उनके खाने में देसी घी और खास किस्म का स्वाद होता है। जब घर से बाहर निकला, तो ढाबे और होटलों का खाना खाकर ऊब गया। बाहर के खाने और मां के हाथ के खाने में फर्क है। मां जब सब्जियां लाती हैं, तो उसे अच्छे से धोकर काटती हैं, वह मेहनत बाहर के लोग नहीं करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में कई ढाबों पर रहा भी हूं, वहां देखा है कि कैसे बासी दाल को नई दाल में मिक्स करके तड़का मार दिया जाता था। फिर मैंने ठान लिया कि अब बस घर का बना खाना ही खाऊंगा।



खाना बनाने में भी मास्टर हैं कैलाश। इंस्टाग्राम

फ्रैक्चर के साथ स्टंट कर पाना आसान नहीं था

फिल्म एम एस धौनी: द अनटोल्ड स्टोरी तथा वेब सीरीज इनसाइड फेम अभिनेता जितिन गुलाटी हाल ही एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई वेब सीरीज छत्रसाल में महाराजा छत्रसाल के किरदार में नजर आए हैं। यह सीरीज 17वीं और 18वीं सदी में बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल के जीवन पर आधारित है। जितिन के मुताबिक यह शो उनके लिए आसान नहीं था। वह बताते हैं, 'निर्माताओं ने इससे पहले धारावाहिक पृथ्वी वल्लभ में मेरा काम देखा था। उसी के आधार पर 2018 में मुझे आडिशन के लिए बुलाया गया। मैंने इस शो में महाराजा के 20 वर्ष से लेकर उनके बुजुर्ग होने तक का किरदार निभाया है। इसलिए कई लुक टेस्ट किए और करीब तीन महीने की प्रक्रिया के बाद मैं इस शो के लिए चुना गया। महाराजा छत्रसाल के व्यक्तित्व को समझने के लिए मैंने उनकी लिखी कई किताबें पढ़ीं। मुझे अपना वजन बढ़ाना पड़ा और कई चीजों का प्रशिक्षण लेना पड़ा। शूटिंग के दौरान मेरे साथ दो हादसे भी हुए थे। दरअसल, इसके साथ मैं वेब सीरीज इनसाइड एज 2 की भी शूटिंग कर रहा था। उसके एक एक्शन सीन के दौरान मेरे पैर में हल्का फ्रैक्चर हो गया था। फिर इस शो की शूटिंग के दौरान घोड़े से गिरने की दुर्घटना हो गई थी। फ्रैक्चर के साथ बढ़ा हुआ वजन, उसके ऊपर कुश्ती, तलवारबाजी और घुड़सवारी के स्टंट कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था।' शो में जितिन के साथ आशुतोष राणा मुगल शासक औरंगजेब की भूमिका में हैं।



वेब सीरीज छत्रसाल में महाराजा छत्रसाल बने हैं जितिन ● पीआर टीम

रा के गुप्त अभियानों पर आधारित होगी पैंथर्स

जासूसी की कहानियों पर कई फिल्में बनी हैं। अब इन कहानियों को डिजिटल प्लेटफार्म पर नए अंदाज में पेश करने के लिए तैयार हैं निर्माता रॉनी स्क्रूवाला। रॉनी ने सीरीज की दुनिया में कदम रखते हुए अपनी थ्रिलर वेब सीरीज पैंथर्स की घोषणा की है। रेंसिल डिसिल्वा द्वारा निर्देशित इस सीरीज के कई सीजन बनेंगे। इसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रा) और पिछली सदी के छठे और सातवें में भारत-पाकिस्तान के बीच जासूसी से जुड़ी कहानियां होंगी। 45 मिनट के हर एपिसोड में उस दौर के रा नायकों के कारनामों का जिक्र होगा कि वे कैसे सुराग ढूंढते थे, जानकारियां इकठ्ठा करते थे और अपने लक्ष्य को हासिल करते थे। सीरीज में राजीव गांधी के विमान के अपहरण से जुड़ी साजिश का भी जिक्र होगा। साल 1971 में राजीव इंडियन एयरलाइंस के जिस विमान के पायलट थे, उसके अपहरण की साजिश थी, जिसे भारतीय एजेंट्स ने नाकामयाब कर दिया था। रॉनी ने पैंथर्स सीरीज के लिए ब्लू मंकी फिल्म्स के प्रेमनाथ राजगोपालन के साथ टीम बनाई है। रॉनी ने बताया कि पैंथर्स भारतीय जासूसी एजेंसी की कहानी है। ये कहानियां आंखें खोलेंगी। सीरीज में वास्तविकता और मनोरंजन के बीच सही संतुलन होगा। वहीं निर्देशक रेंसिल डिसिल्वा ने कहा कि लोग वास्तविक कहानियां पसंद कर रहे हैं। पैंथर्स में दिखाए जाने वाले रा के गुप्त आपरेशन वास्तविक जीवन में घटित हुए हैं। यह सीरीज रा एजेंसी के साहसिक कारनामों को एक ट्रिब्यूट होगी। पैंथर्स साल 2022 की पहली तिमाही में फ्लोर पर जाएगी।



रेंसिल डिसिल्वा द्वारा निर्देशित इस सीरीज के कई सीजन बनेंगे ● पीआर टीम

शादी की रस्म के लिए रितेश ने आठ बार छुए थे जेनेलिया के पांव

रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख की जोड़ी हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय जोड़ियों में शुमार होती है। अपनी शादी को लेकर जेनेलिया ने बताया कि शादी के दौरान रितेश को एक रस्म के रूप में आठ बार उनके पांव छूने पड़े थे। उन्होंने यह रहस्योद्घाटन डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 के दौरान किया, जिसमें वह बतौर अतिथि पहुंचे। शो से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस वीकेंड के एपिसोड की थीम शादी स्पेशल है। इस मौके पर प्रतिभागी कंटेस्टेंट अनीश तट्टीकोटा और उनके सुपर गुरु आकाश शेट्टी ने माही वे गाने पर शानदार परफॉर्मेंस देकर सबका ध्यान आकर्षित किया। उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद जेनेलिया ने कहा, 'ओ माय गाड। आपकी परफॉर्मेंस ने मुझे अपनी शादी की याद दिला दी। हमने भले ही अपनी शादियों का आधुनिकीकरण कर लिया हो और उन्हें पार्टी बना दिया हो, लेकिन मुझे पारंपरिक शादियां पसंद हैं और मैं खुद को खुशनसीब मानती हूं कि मेरी शादी भी ऐसी ही हुई थी। हर रस्म मेरे लिए एक बड़े उत्सव की तरह होती है। मैं अपनी विदाई के समय भी बहुत इमोशनल हो गई थी। फेरों के दौरान रितेश को एक रस्म के रूप में आठ बार मेरे पांव छूने पड़े थे।' वहीं रितेश देशमुख ने कहा, 'मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं यहां बैठकर इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देख रहा हूं। आप लोगों ने एक माहौल बना दिया है। ये सिर्फ एक गाना या कोरियोग्राफी नहीं है। यह देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने किसी करीबी की शादी में आया हूं।' यह एपिसोड आज (शनिवार को) सोनी चैनल पर प्रसारित होगा।



सुपर डांसर चैप्टर 4 में बतौर मेहमान पहुंचे रितेश और जेनेलिया। सोनी टीवी पीआर टीम

19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी बेल बाटम

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कई निर्माता हालात पर नजर रखे हुए हैं। सिनेमाघरों के खुलने पर वे अपनी फिल्मों की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म बेल बाटम की नई तारीख का एलान कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें फिल्म की संक्षिप्त जानकारी है और एक नया पोस्टर भी है। अक्षय ने लिखा, 'मिशन है आप लोगों को बड़े पर्दे पर एंटरटेन करने का। तारीख 19 अगस्त, 2021 है। बेल बाटम फिल्म आने जा रही है सिनेमाघरों में।' सत्य घटना से प्रेरित बेल बाटम में अक्षय कुमार के अलावा वाणी कपूर, हुमा कुरैशी और लारा दत्ता अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन रंजीत तिवारी ने किया है। लाकडाउन हटने के बाद कोरोना काल में शूट होने वाली बेल बाटम पहली फिल्म थी। फिल्म को पहले 27 जुलाई को रिलीज करने की घोषणा हुई थी, लेकिन कई राज्यों में सिनेमाघर न खुलने की वजह से टाल दिया गया था। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज भी एक साल से अटकी हुई है। इसके अलावा उनकी फिल्म पृथ्वीराज, रक्षा बंधन, राम सेतु, बच्चन पांडे भी रिलीज की कतार में हैं।



फिल्म में सीक्रेट एजेंट के किरदार में नजर आएंगे अक्षय कुमार ● इंटरनेट मीडिया